जलतरंग

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका

अंक 7

मार्च 2017





कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते समय बाये से खड़े श्री किरण रिजीजू (गृहराज्य मंत्री), श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी - राष्ट्रपति, रियर एडमिरल आर के श्रावत, सीएमडी, श्री गिरीश शंकर - संयुक्त सचिव राजभाषा



पुरस्कार प्राप्त करते समय बाएँ से खड़े श्री अनूपकुमार श्रीवास्तव, सचिव राजभाषा, श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी, राष्ट्रपति, श्री किरण रीजीजू (गृह राज्य मंत्री) रियर एडमिरल आर के श्रावत, सीएमडी, एमडीएल, डॉ बिपिन बिहारी - संयुक्त सचिव राजभाषा।

जलतरंग

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका

मुख्य परामर्शदाता

श्री सोपान एस कांबले विभाग प्रमुख (मानव संसाधन)

संपादक मण्डल

श्री बी डी साठे, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

श्री प्रकाश चन्द्र झा, उप महाप्रबन्धक (जहाज निर्माण)

श्री रामाश्रय यादव, उप प्रबंधक, (भंडार - पू.ख.)

श्री रामप्रीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

श्री पी डी सिद्दीकी, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

सुश्री जयंतिका मुखर्जी, हिन्दी अनुवादक

प्रकाशक

मीडियाट्रिक्स

511, चर्चगेट चेम्बर्स, 5 न्यु मरीन लाइन्स, चर्चगेट, मुम्बई - 400 020

सम्पर्क नं. +91 9920510882 / 22 6743 9594

हिन्दी अनुभाग

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

माझडॉक हाउस दूसरी मंजिल, डॉकयार्ड रोड, मुंबई - 400 010, फोन नं. 022-23710456

विषय सूची

एमडीएल का इतिहास - रामप्रीत एच यादव	6
मेक इन इंडिया पहल - तपन मण्डल	13
पनडुब्बी -गीता सुनतकरी	15
एस एस ए वर्कशाप - जान अब्राहम	20
एमडीएल शिपयार्ड में बुनियादी सुविधाएं - गणेश गोल्हा	23
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व - रोहित पांड्या	26
अँग्रेजी का इतिहास - पी डी सिद्दीकी	29
अमर शहीद भगत सिंह - ज़ाहिद माझगांवकर	34
डिजिटल इंडिया - राजेश आंबावाड	39
स्वच्छता - दुर्गेश कुमार राय	41
कम्प्यूटर के उपयोग में सुरक्षा - सुनील कुमार कुशवाहा	42
बलि पर रोक - पी आर सावंत	43
विमुद्रीकरण - जयंतिका मुखर्जी	44
स्वदेशीकरण - एस डी डोल्हारे	47
कश्मीर की कहानी - संजय मिश्रा	50
महर्षि दयानन्द - सनेही प्रसाद	56
भारतीय संस्कृति की महानता - रिजवान बसरी	60
हताशा - राकेश कुमार	61
एमडीएल के कार्यक्रमों की झलकियाँ	62

इस पत्रिका में दिये गयें लेखकों के विचारसें सम्पादक मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से...

मान्यवर,

01 जनवरी 2017 से मैंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले निदेशक (समवाय योजना एवं कार्मिक) के पद पर कार्य करते हुए राजभाषा हिन्दी की प्रगति, प्रचार एवं प्रसार के लिए वर्ष 2013 से निरंतर प्रयास किया है। इसका प्रमाण है कि पत्रिका प्रकाशन के आरंभ से अब तक अपने गुणवत्ता मानक को कायम रखा है और प्रत्येक अंक को पुरस्कार योग्य मानकर मुंबई टॉलिक ने सर्वोत्कृष्ट गृहपत्रिका का सम्मान दिया है। हमारी पत्रिका 'जलतरंग' को महामहिम राष्ट्रपति के करकमलों से 14 सितंबर 2015 को 'ख' क्षेत्र में प्रथम तथा वर्ष 2016 में द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की राजभाषा पत्रिका 'जलतरंग' का सप्तम अंक प्रकाशित होने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इस अंक के माध्यम से कंपनी के प्राचीन गौरवशाली इतिहास के साथ-साथ वर्तमान रक्षा उत्पादों का परिचय देने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका का सप्तक अंक मुख्य रूप से कंपनी उत्पादों एवं कर्मचारियों के सामयिक लेख पर आधारित है। भाषायी वर्गीकरण के आधार पर एमडीएल 'ख' क्षेत्र में स्थित है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों को एमडीएल कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास एवं योगदान से हासिल करने में कामयाब हुआ है। हिन्दी का अधिकतम प्रचार और प्रसार करना पत्रिका का उद्देश्य है। राजभाषा का अपने दैनिक कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग करना प्रत्येक कर्मचारी की राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एमडीएल सतत प्रयत्नशील रहता है। भारत सरकार अपने सभी कर्मचारियों से दैनिक कार्यालय कार्य हिन्दी में करने की अपेक्षा करती है।

मैं आशा करता हूँ कि गृहपत्रिका 'जलतरंग' का यह अंक अपने उद्देश्य में सफल होगा और इसमें संकलित रचनाएं सभी पाठकों के लिए लाभप्रद एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित...

कमोडोर राकेश आनन्द भानौ(नि)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



विभागप्रमुख (मानव संसाधन) की कलम से...

कंपनी की गृहपत्रिका 'जलतरंग' का सप्तम अंक प्रकाशित होने पर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि पत्रिका का प्रत्येक अंक विविधता के साथ प्रकाशित किया जाता है। यह पत्रिका की गुणवत्ता ही है जो 'ख' क्षेत्र की 64 सार्वजनिक उपक्रमों के बीच अपने लिए स्थान बनाने में अब तक सफलता प्राप्त करती रही है।

कंपनी कर्मचारियों की साहित्यिक रुचियों का प्रदर्शन और अभिव्यक्ति इसके माध्यम से प्रदर्शित होती है। कंपनी में आयोजित होने वाले साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के साथ विदेशी एवं देशी गणमान्य अतिथियों/प्रतिनिधियों के दौरों को भी पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है जो यार्ड की प्रगति और वृद्धि में सहयोग करते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का राष्ट्रीय कर्तव्य निभाना कंपनी अपना नैतिक कर्तव्य समझती है। कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी का विशेष विवरण इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पर्वों को विशेष स्थान दिया गया है। कंपनी प्रबन्धन कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास ते लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है।

मैं, हिन्दी अनुभाग के प्रयास की सराहना करता हूँ जिन्होने बेहतरीन पाठ्य सामग्री पत्रिका में शामिल किया है। पत्रिका की गुणवत्ता उन्नति के लिए भरपूर प्रयास किया गया है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारी पत्रिका 'जलतरंग' को इस बार भी इसकी विविधता और नवीनता के लिए पुरस्कार प्राप्त होंगे।

शुभकामनाओं सहित...

सोपान एस कांबले

विभागप्रमुख (मानव संसाधन)



संपादकीय...

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड देश का प्राचीन एवं प्रमुख शिपयार्ड है यह मुंबई के पूर्वी तट पर हार्बर क्षेत्र में स्थित है। माझगांव टापू के पास पहले से ही एक सकरी क्रीक थी जिसके माध्यम से जहाज समुद्र के किनारे तक आते थे। मराठा शासन के दौरान यहाँ एक सुखी गोदी का निर्माण किया हुआ। 16वी शताब्दी में पुर्तगलियों ने जहाजों की मरम्मत के लिए सूरत में एक गोदी का निर्माण किया था। अंग्रेजों से पुर्तगलियों का संबंध जुड़ने के बाद मुंबई गोदी का विकास पारसी जहाज निर्माताओं के माध्यम से विकसित हुआ। विभिन्न मालिकों के अंतर्गत यहाँ सुखी गोदीयों का निर्माण हुआ। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का विकास किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देश स्वतंत्र होने से पहले माझगांव डॉक का गठन किया गया।

प्रस्तुत अंक में कंपनी के राष्ट्रीयकरण से आज तक की प्रगति का व्योरा और भविष्य की प्रगति की रूपरेखा तैयार करने की पहल की गई है।

पत्रिका का मूल उद्देश्य राजभाषा का प्रचार करना और सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन साधारण रूप में प्रस्तुत करना है। पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए पठनीय सामग्री समाहित करने का प्रयास किया गया है कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से पत्राचार लक्ष्य निरंतर कायम रखने तथा बढ़ाने की कोशिश जारी है।

राजभाषा हिन्दी का अधिकतम उपयोग दैनिक जीवन में करना और हिन्दी का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। देश की अपेक्षाओं का साधन नागरिक होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है।

विगत 67 वर्षों में हिन्दी का सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है दुनिया के सभी नवस्वतंत्र देशों की ऐसी ही नियति रही है फिर भी अंग्रेजी के विकास की तुलना में हिन्दी ने विगत 68 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति किया है। अंग्रेजी ने अपना विकास दूसरी भाषाओं के माध्यम पूरा किया क्योंकि उसके पास शब्द निर्माण की क्षमता नहीं थी। क्षेत्र के अनुपात में अंग्रेजों का दायरा छोटा था और हिन्दी का दायरा विशाल है। इसलिए समुचित विकास हेतु अधिक समय लगना स्वाभाविक है।

वर्तमान सरकार का स्वदेशी भाषा के प्रति लगाव सकारात्मक है इससे आशा की किरण दिखाई दे रही है कि भविष्य में इसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि एकबार सरकारी कार्य प्रणाली का माध्यम बदलने पर भविष्य का पथ निश्चित हो जाता है।

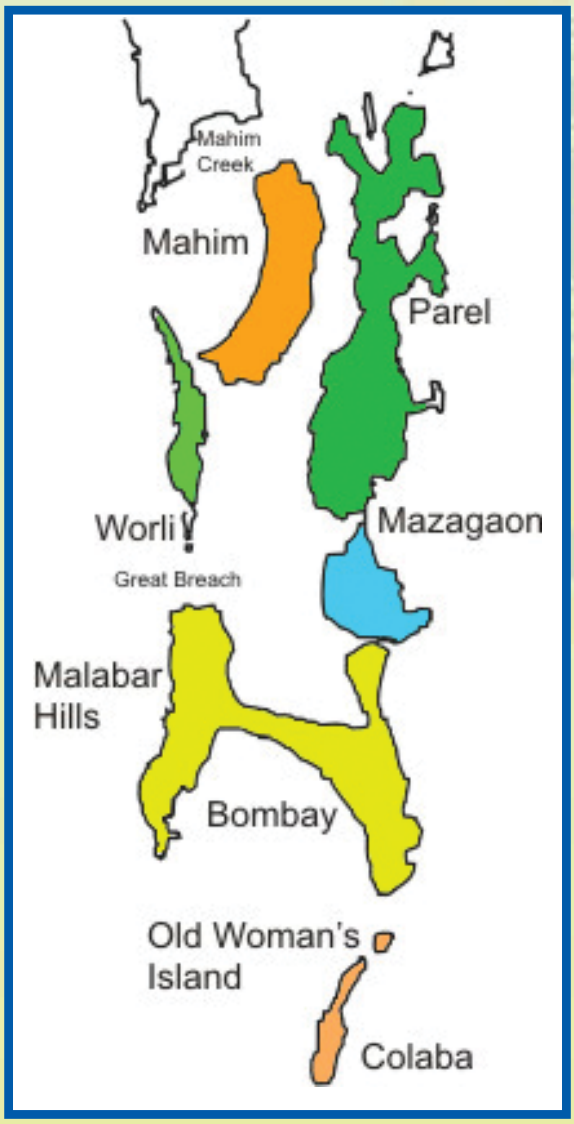
बी डी साठे,
अमप्र(मा.स) - न्हावा यार्ड

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का क्रमिक विकास



श्री रामप्रीत यादव
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

मुंबई के सात द्वीपों में माझगांव भी शामिल था दूसरे द्वीपों का नाम क्रमश: माहिम, वर्ली, माटुंगा, गिरगांव, ओल्डवूमेन्स लैण्ड तथा कोलाबा था। ये सभी एक दूसरे से अलग-अलग थे और अरब सागर में ज्वार-भाटा के समय आपस में मिलते थे।



प्राकृतिक रूप से माझगांव द्वीप के पास एक खाड़ी थी, जिसे माझगांव क्रीक कहा जाता था, आज उसे ही कसारा बेसीन के नाम से जाना जाता है। यह बेसीन प्रारंभ से ही बहुत गहरी थी, जिसमें बड़े जलयान आसानी से आ-जा सकते थे। 1000 से 1700 ईस्वी के दौरान माझगांव की सकरी खाड़ी में मुगल जलयानों के खड़ा करने का प्रमाण पाया जाता है। लगभग 1600 ईस्वी के दौरान अरब लोग माझगांव क्षेत्र में बार-बार आया करते थे। औरंगजेब के शासन के दौरान सिद्दियों ने माझगांव पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1675 से 1677 के दौरान कसारा बेसीन में सिद्दीयों के जहाज यहाँ लंगर डालते थे। आज जिसे मुगल डॉक कहते हैं, प्राचीन काल में यहाँ कीचड़ में एक गोदी थी जिसमें ज्वार भाटा के समय अरब लोगों के जहाज लंगर डालते थे और कीचड़ के स्लिप-वे पर ज्वार के समय खींचकर बाहर निकाले जाते थे।

1) जहाज मरम्मत तथा जहाज निर्माण केंद्र के रूप में माझगांव का विकास

मुंबई में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे जिनका आगमन सन् 1507 में माहिम में हुआ। यहाँ पहुँचने पर पुर्तगालियों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए माहिम में किल्ला बनाया जो आज भी जर्जर अवस्था में माहिम पश्चिमी समूद्री तट तथा नए रोप-वे ब्रिज के बीच स्थित है। सन् 1534 में पूरा मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। फिर भी पुर्तगालियों ने मुंबई के द्वीपों को अपने जहाज व्यवसाय के लिए लाभप्रद नहीं समझा और सन् 1661 में मुंबई के द्वीपों को ब्रिटेन को दे दिया। अंग्रेजों ने अनुमान लगाया कि समुद्री जल की गहराई ज्वार की स्थिति और मानसून से पर्याप्त सुरक्षा की दृष्टि से यह स्थान सुरक्षित है बॉम्बे हार्बर को जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत यार्ड के रूप में परिवर्तित करने के लिए थोड़े ही प्रयास करने की जरूरत है।

अँग्रेजी नौसेना का बेड़ा आधार सूरत में स्थित था जहाँ वे अपनी जहाजों की मरम्मत करते थे सन् 1686 में उन्होंने अपना जहाज मरम्मत केंद्र सुरत से मुंबई स्थानांतरित

किया। अँग्रेजों ने अपनी गोदी कॉसल एरिया में स्थापित किया, जिसे उस समय बॉम्बे डॉकयार्ड कहा जाता था और आज नेवल डॉकयार्ड के नाम से मशहूर है। उस जमाने में अपनी सुरक्षा के लिए अँग्रेजों ने दक्षिण मुंबई के कुछ क्षेत्रों में दीवार बनवाया था जो आज मौजूद नहीं है क्योंकि समय के साथ शहर का विस्तार कोलाबा, वीटी, गिरगाँव क्षेत्रों में आगे की ओर होता रहा, दीवार अब कहीं दिखाई नहीं देती लेकिन उस समय दीवार के भीतर स्थिति स्थानों को आज भी फोर्ट कहा जाता है।

उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी संयुक्त रूप से युद्धपोत और व्यापारिक तोपों का निर्माण करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पोत और युद्धपोत बॉम्बे डॉक यार्ड में लंगर डालते थे।

विदेशी व्यापार में भारी मुनाफा होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों को कायम रखने के लिए मुंबई में गोदी सुविधायें बढ़ाने का निर्णय लिया।

इसके लिए ऊपरी मध्य और निचले मुंबई में ड्राईडाक का निर्माण बॉम्बे डॉक यार्ड कैंसल एरिया में सन् 1750, 1762 तथा 1775 में क्रमश: किया गया। ये ही एकमात्र ड्राइ डॉक था जो बॉम्बे मरीन और ईस्ट इंडिया मेन दोनों के लिए उपलब्ध थे और बाहरी जहाजे भी इन्ही ड्राई डॉक में लंगर डालती थी।

जैसे-जैसे समय बीतता गया और जहाजों का कारोबार बढ़ता रहा जिसके कारण यहाँ की सुविधायें इन द्वीपों के पूर्वी समुद्री तट के उत्तर तरफ बनाना आवश्यक था।

300 टन क्षमता के जहाजों की बर्थींग करने के लिए एक सुखी गोदी स्थापित करने की आवश्यकता बॉम्बे डॉक यार्ड क्षेत्र से बाहर बनाने की परिकल्पना महसूस की गई और इसके कारण माझगाँव परिसर में अंग्रेजों द्वारा पोर्ट ट्रस्ट परिसर के आरम्भ होने से पहले शुरू किया गया।

बॉम्बे डॉक यार्ड से पहली बार विस्तार करने के उद्देश्यों से माझगांव क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया गया। माझगांव के इस पूर्वी समुद्री तट पर एक स्लिप-वे माझगांव मौजूद था जिसका निर्माण सन् 1673 में किया गया था। यहाँ पर एक छोटी गोदी थी जिसे माझगांव डॉक कहा जाता था। यह आज भी अपने वर्तमान रूप में मौजूद है, जिसका पुर्न:नवीनीकरण किया गया है।

इस छोटी सी बुनियाद के आधार पर माझगाव डाक रूपी विशाल महल खड़ा हुआ है।



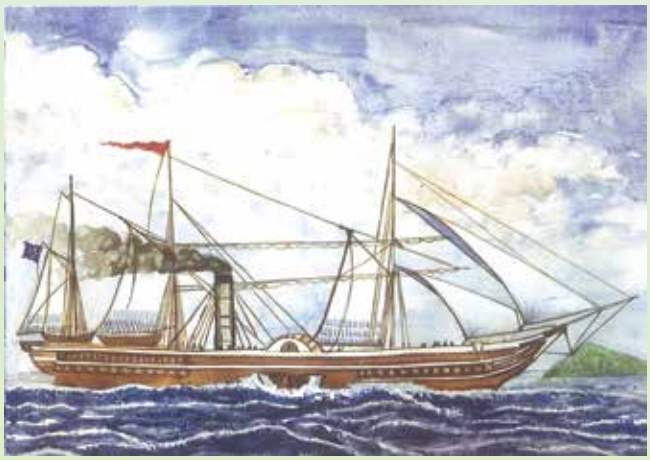
पुरानी छोटी गोदी (माझगाँव ड्राई डॉक)

माझगांव ड्राई डाक का कार्य सन् 1774 में पूर्ण हुआ। इस गोदी का प्रवेशद्वार कसारा बेसीन की ओर था जो ज्वार भाटा से संचालित होता था। इस गोदी का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों की देखभाल करना था, जिसमें अनेक जहाजों को नेवल डॉक यार्ड में भीड़-भाड़ के कारण नहीं ले जा सकते थे।

माझगांव डॉकयार्ड को इस प्रभार दूसरे नेवल डॉक के रूप में उपयोग किया जाता था और इसका प्रशासन बाम्बे मैरीन अधिक्षक के अधीन था। सन 1804 में श्री रुस्तम जी मानकेजी वाडिया ने जहाज निर्माता के रूप में इसका कार्यभार ले लिया। यह डाक यार्ड भी बाम्बे डॉक यार्ड से संबद्ध था। माझगांव ड्राई डॉक केवल मरम्मत और पुनसज्जा का कार्य नहीं करता था बल्कि जहाजों का निर्माण भी करता था। अनेक जहाजों का निर्माण माझगांव डॉक में किया गया और उनको खींचकर बाम्बे डॉकयार्ड में सज्जा के लिए ले जाया जाता था। इस प्रकार माझगांव डॉक ने प्रसिद्ध टिकवुड युद्धपोतों का निर्माण कर बॉम्बे डॉकयार्ड को सहयोग वाडिया के कुशल नेतृत्व में किया है।

नॉर्थ यार्ड और साउथ यार्ड

माझगांव परिसर में एक साथ दो यार्डों का विकास हुआ था जिन्हें आज नॉर्थ यार्ड और साउथ यार्ड के रूप में जाना जाता है। पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल नेविगेशन कंपनी ने (पी एंड ओ) ने मुगल ड्राई डॉक का सन् 1874 में अधिग्रहण किया। आरम्भ में पट्टे पर लिया था बाद में इसके मूल मालिक शेखजी से खरीद लिया। जैसे-जैसे पी एंड ओ की जहाजों का कार्यभार बढ़ने लगा उन्होंने विचार किया कि अपनी जहाजों की मरम्मत का केंद्र भी मुंबई में होना चाहिए। विस्तार की दृष्टि से सन् 1860 में पी एंड ओ कम्पनी ने माझगांव डॉक को खरीदा और सन् 1863 में मुगल ड्राई डॉक का विस्तार किया। माझगांव ड्राई डॉक के उत्तर पश्चिम तरफ एक त्रिकोण प्लॉट को पहले प्राप्त किया और सन 1865 में रिची ड्राई डॉक का निर्माण कराया और सन् 1870 में दक्षिण यार्ड को उत्तर यार्ड



एमडीएल में निर्मित पहली स्टीम चालित जहाज

से जोड़ दिया इस प्रकार नार्थ यार्ड में दो ड्राई डॉक हो गए पहला माझगांव ड्राई डॉक और दूसरा रिची ड्राई डॉक। दक्षिण यार्ड में केवल एक ड्राई डॉक है जिसे मुगल ड्राई डॉक कहते हैं यह आज भी बेहतर स्थिति में है और नियमित रूप से पनडुब्बी की पूर्ण सज्जा के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सन् 1960 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात दो स्लिप-वे का निर्माण दक्षिण और उत्तर यार्ड में जहाजों के बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। जहाँ जहाजों की इकाईयों को आपस में जोड़ा जाता है। इकाईयों को उठाने के लिए गोदियों के दोनों तरफ ट्रैक पर क्रेनें स्थापित की गई हैं। पी एंड ओ द्वारा वित्तीय कमी का सामना करने पर यह एहसास हुआ कि माझगांव के दो यार्डों को चलाना कठिन कार्य है। इसके कारण पी एंड ओ ने साउथ यार्ड को नए खरीददार द ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी लि. को बेच दिया जिसे पहले बी आई कहा जाता था।

माझगांव डाक कंपनी : सन 1970 से 1914 तक पी एंड ओ और बी आई कंपनियों ने अपने जहाजों का परिचलान क्रमश: नार्थ यार्ड और साउथ यार्ड से करते रहे। इसके कारण दोनों कंपनियों के बीच एक बढ़िया

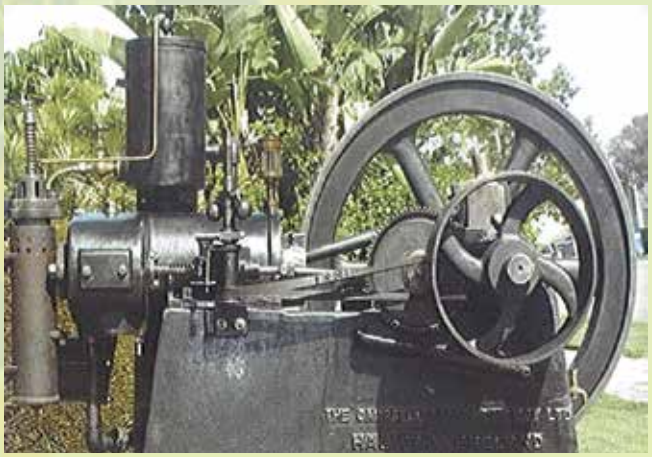


नार्थयार्ड में रिची ड्राई डॉक का चित्र

स्पर्धा उत्पन्न हुई। फिर भी सन 1915 से पहले ही नार्थ यार्ड और साउथ यार्ड एवं रिची ड्राईडॉक और ओल्ड मुगल डॉक सम्मिलित रूप से माझगाँव डाक कंपनी के नियंत्रण में आ गए क्योंकि यह प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान समन्वय और बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक था। पी एंड ओ कंपनी तथा बी आई कंपनी ने एक साझेदारी फर्म बनाया और वर्ष 1915 में माझगाँव डॉक कंपनी का गठन किया गया।

सन् 1940 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान माझगाँव डॉक लि. का उपयोग पैसेंजर लाइन्स पोतों का रूपान्तरण सैनिक पोत और अस्पताल पोत के रूप में युद्ध में सहायता करने के लिए एक अंग बनाकर ब्रिटिश सेना की सहायता की गई।

अनेक बड़े जहाज जो बम या टारपीडो के हमले में विकृत हो गई थी, ऐसी जहाजों को माझगाँव डाक कंपनी द्वारा नया जीवन प्रदान किया गया। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी मुगल ड्रायडॉक के प्रभारी अधिकारी थे। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि प्राथमिकता के आधार पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुगल ड्राईडॉक का इस्तेमाल सिर्फ जहाजों की मरम्मत के लिए किया जाए।



कैम्पबेल इंजन का चित्र

सन 1950 में एम डी एल ने कैंम्पबेल आयल इंजन का निर्माण आरम्भ किया और यूनाईटेड किंगडम से अधिकृत रूप से लाइसेन्स लेकर माझडाक आयल इंजन के नाम से बाजार में बेचा। इस पम्प का उपयोग मुख्य रूप से कृषि कार्यों हेतु किया गया था। इसकी मांग दस साल तक खूब रही बाद में मांग कम होने के कारण कम्पनी ने वर्ष 1966 से इसका उत्पादन बंद कर दिया।

माझगांव डॉक प्राइवेट लिमिटेड : द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात पी एंड ओ के साथ-साथ बी आई कंपनी ने परिचालन के लिए लागत में

कटौती का प्रयास किया जिसके कारण जहाजों का परिचालन प्रभावित होने लगा। सन 1948 में कंपनी ने नॉर्थ यार्ड की अपनी कुछ जमीन को पट्टे पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे दिया जिसका पट्टा सन 1962 में समाप्त हुआ। सन 1953 में मेसर्स सिंदीया वर्कशाप लिमिटेड ने नॉर्थ यार्ड और साउथ यार्ड के बीच स्थित खाली तिकोनी भूमि को खरीद लिया जहाँ समुद्र से जुड़ी एक छोटी गोदी थी। कम्पनी का उद्देश्य इस गोदी का उपयोग जहाज निर्माण तथा मरम्मत करना था। अनेक वर्षों तक सिंदीया वर्कशाप लिमिटेड ने जहाजों की मरम्मत का कार्य किया और कुछ वर्षों बाद बंद हो गई।

सन 1957 में, कंपनी की पूर्ण संरचना की गई, अब माझगाँव डॉक कंपनी की साझेदार कंपनी पी एंड ओ तथा बी आई एस एन कम्पनी को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर माझगाँव डॉक प्राइवेट लि. कंपनी के रूप में ब्रिटिश प्रबंधन के अंतर्गत कर दिया गया। जिसमें बी आई एस एन और पी एंड ओ के शेयरों को माझगाँव डॉक प्राईवेट लिमिटेड में निवेश कर दिया गया।

सन् 1950 से पहले और बाद में भी माझगाँव डॉक प्राईवेट लि. कंपनी राष्ट्र के जलयान और हार्बर क्राफ्ट की जरूरतों को पूरा कर रही थी, जबकि इसका मुख्य कार्य जहाज मरम्मत था।

भारत सरकार द्वारा माझगाँव डॉक का अधिग्रहण :

स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने रघु रमैया समिति की नियुक्ति भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत की बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए किया। समिति ने अनुभव किया कि



अधिग्रहण के समय एमडीएल ऐतिहासिक भवन का चित्र



अधिग्रहण के समय श्री वी कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री, श्री यशवंत राव चौहान मुख्यमंत्री एवं यार्ड के मुख्य अधिकारी का चित्र

एमडीएल में यार्ड सुविधायें मौजूद हैं इनका विकास कर जहाज निर्माण यार्ड के रूप में विस्तार किया जा सकता है, इसलिए समिति ने सरकार को सिफारिश किया कि वह इसका अधिग्रहण कर ले। 13 मई 1960 को रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन के संयुक्त प्रयास से माझगाँव डॉक लिमिटेड का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। इसे 14 मई 1960 को मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में निगमित कर राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया। एमडीएल का मुख्य उद्देश्य इसके जहाज मरम्मत कार्य के स्थान पर देश के लिए युद्धपोत निर्माण करना था।

5) युद्धपोत निर्माण के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण :

भारत में निर्मित होने वाले युद्धपोत के प्रकार पर निर्णय लेने से पहले एमडीएल ने आधुनिकीकरण और विस्तार नीति का कार्यान्वयन आरम्भ किया गया। उस समय एमडीएल का कुल क्षेत्रफल 32.65 एकड़ था और युद्धपोत निर्माण करने से पहले व्यापक आधुनिकीकरण और विस्तार करने की आवश्यकता थी। कसारा बेसीन उस समय बाम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अधीन था। दीर्घकालिक चर्चा के बाद सन 1963 में एक सहमति बनी जिसके अंतर्गत कसारा बेसीन बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एमडीएल को पट्टे पर मिला। इसका स्वामित्व प्राप्त के बाद एमडीएल ने भावी जहाज निर्माण योजना के लिए इसका रूपांतरण चारो ओर से घिरे वेट बेसीन के रूप में करना प्रारंभ किया। इसमें कसारा डॉक को गहरा करना और चारो ओर दिवार लगाना शामिल था।

मुगल ड्राई डॉक : मुगल डॉक माझगांव डॉक के इतिहास में दूसरा सबसे पुराना डॉक माना जाता है तथापि माझगांव में एक अन्य गोदी का अस्तित्व पहले समय से था। मुगल डॉक के स्वामी मकुल्ला के शेख थे जो हैदराबाद के नवाब भी थे। सन् 1935 में शेख को एच एच अवध बिन ओमर सुलतान नवाब जंग शमशेरल मुल्क बहादुर के नाम से जाना जाता था और उनका नाम डॉक के टाइटेल डीड में भी देखा जा सकता है। इस डॉक को पी एंड ओ एस एन कंपनी ने भाड़े पर लिया था जो मिर्जा अली मोहम्मद खान शूस्त्री के परिवार से थे।



मुगल ड्राई डॉक

इस डॉक का प्रयोग मूल रूप से फारस की खाड़ी, लाल सागर, जंजिबार आदि से डोह बेड़ा से व्यापार हेतु होता था। बाद के वर्षों में जब डॉक को पी एंड ओ कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया, यह प्रथा आगे भी चलती रही और डॉक को डोह बेड़ा द्वारा निरंतर भाड़े पर व्यापार करने के लिए लिया जाने लगा। यहाँ बहुत प्राचीन पंपिंग व्यवस्था थी, जिसमें लकड़ी के खोखले ट्रंक्स को बाल्टी से जुड़ा हुआ पाया गया जो हाथ द्वारा संचालित होता था यह तब दिखाई दिया जब पुराने डॉक के ऊपरी सेक्शन में पम्प लगाने के लिए इसे खोला गया। प्रारम्भिक रूप में निर्मित, पुराना मुगल डॉक 160 फीट लंबा, और 45 फीट चौड़ा था जो संभवत: सन् 1835 के आसपास बनाया गया था। सन् 1839 के बाद इस डॉक का उपयोग बंद हो गया था, लेकिन सन् 1860 में पी एंड ओ कंपनी ने इसे सरकार से बहुत ही कम दाम पर तट के अगले भाग को सुधारने के लिए अनुमति हासिल किया। पार्सि प्रकाश के अनुसार, मुगल डॉक को एक सुपरिचित व्यापारी आगा मोहम्मद रहीम सिराजी द्वारा जुलाई सन् 1843 में अधिग्रहण किया गया। उन्होंने इस डॉक का धुंजिभाई रुस्तमजी वाडिया के हाथों सौंप दिया। 1 जनवरी 1847 को पी एंड ओ कंपनी ने इस डॉक को पट्टे पर लिया, परंतु धुंजिभाई रुस्तमजी इस ड्राई डॉक के मास्टर बिल्डर मृत्यु तिथि 4 अगस्त 1854 तक बने रहे।

कसारा बेसिन - माझगांव डॉक में अब नाव के स्थान पर युद्धपोत निर्माण का कार्य शुरू होगा, यह विचार आने से पहले ही माझगांव डॉक के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना आरंभ हो गई थी। सर एलेक्सण्डर गिब्ब और पटनर्स ने युद्धपोत निर्माण की योजना की शुरूआत कर दी थी। एलेक्सण्डर गिब्ब और पटनर्स के प्रारंभिक रिपोर्ट में युद्धपोत निर्माण कुल आकलन रू.354 लाख से संशोधित होकर वर्ष 1965 में रू.716.03 लाख हुई। जून 1966 में रूपया अवमूल्यन के कारण इस आकड़े में एक छलांग आई और वह 802.03 लाख तक बढ़ गई। यही आगे जाकर रू.832 लाख तक पहुँची जो वर्ष 1971 में रू.950 लाख तक जाकर रूकी। वर्ष 1963 के अनुबंध के अंतर्गत कसारा बेसिन को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने माझगाँव डॉक लिमिटेड को पट्टे पर दिया। 1965 में, इस क्षेत्र के विकास हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई। जिसमें मूल रूप से इस बेसिन को गहरा करने और कसारा डॉक को घेरने के साथ ही, रिची ड्राई डॉक के लिए क्रेन ट्रैक, जहाजी घाट और जेट्टी से जोड़ने का काम शामिल था। 15 टन लफ्फिंग क्रेन और 80 टन हेवी लिफ्ट बर्थ साइड क्रेन को भी इंसटाल करने की योजना थी। होच्तिएफ प्रयोजनकर्ता के अंतर्गत इंडो-जर्मन जाइंट वेंचर, होच्तिएफ-मोर्डन पटेल, सबसे कम बोलिकर्ता रहे। इस जाइंट वेंचर में होच्तिएफ एजी, मार्डन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड शामिल थे। यह अनुबंध फरवरी 1966 में पूरा किया गया और उसके तुरंत बाद की कार्य का आरंभ हो गया। तब तक रियर एमडीएल की डोर एडमिरल एसएम नन्दा ने रियर एडमिरल बीए सैमसन को सौंप दी थी। कसारा बेसिन क्षेत्र को सबसे पहले सूखा बनाने की आवश्यकता थी जो तभी संभव हो सकता था जब उसे सागर तरफ से दीवार खड़ा हो सके और पानी को पंपिंग द्वारा निकालना था। कसारा बेसिन को घेरने हेतु दीवार का आरेखन एक सर्कुलर ग्रेविटी वॉल के रूप में किया गया, जिसमें सर्कुलर फैब्रिकेटेट आरसीसी युनिट शामिल था। इन यूनिटों का उत्पादन कसारा बेसिन के दक्षिण तरफ किया गया। रिची ड्राई डॉक की मुख्य निकास पाईप को मोड़ने की आवश्यकता थी, क्योंकि कसारा बेसिन में पानी को और पंप नहीं किया जा सकता था। 0.91 डाईमीटर की आरसीसी पाईपलाईन को दक्षिण दीवार के पीछे बिछाने की जरूरत थी ताकि पानी खुले समुद्र में गिर सके। कसारा बेसिन का कार्य और दो वर्षों तक चलता रहा। 23 अगस्त 1968 को कसारा बेसिन का कार्य पूरा हुआ और उसमें पानी भरा गया। क्रेनों के प्रतिष्ठापन के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ जैसे वेल्डिंग आउटलेट, इलेक्ट्रिक पावर आउटलेट, कॉम्प्रेसेड एयर, ऑक्सीजन और एकेट्यलेन लाइनों का भी इंस्टालेशन किया गया। कसारा बेसिन बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के पास उसके स्थापना के समय से ही था। मुख्य पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र से दूर स्थित होने के कारण इसका प्रयोग शायद ही होता था। यह क्षेत्र एमडीएल के उत्तरी परिसर से जुड़ा हुआ था और केवल मछली पकड़ने की नावों को रखने के लिए प्रयोग की जाती थी। एमडीएल ने इसे पट्टे पर लेने के लिए इच्छा जाहिर की पर पोर्ट ट्रस्ट इसे देने के लिए अनिच्छुक थे। श्री ए एल डायस, आईसीएस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, सौभाग्य से एमडीएल के निदेशक मण्डल के सदस्य रहे थे। उन्हें यह भली प्रकार मालूम था कि इस बेसिन की आवश्यकता माझगाँव डॉक के विकास के लिए आवश्यक है। जब वे 13 मार्च 1963, में एमडीएल मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त हुए तो पोर्ट ट्रस्ट की जमीन को पट्टे पर लेने का फैसला अब उनके हाथों में था। पोर्ट ट्रस्ट कसारा बेसिन को पट्टे पर देने का निर्णय देश के सामुद्रिक रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सामने आया।

कसारा बेसिन का माप निम्न लिखित है :

अधिकतम लंबाई - 275.23 मि.
प्रवेश मार्ग की चौड़ाई - 26.21 मि.
बेसिन की औसत चौड़ाई - 47.12 मि.
दहलीज की गहराई - 9.75 मि.

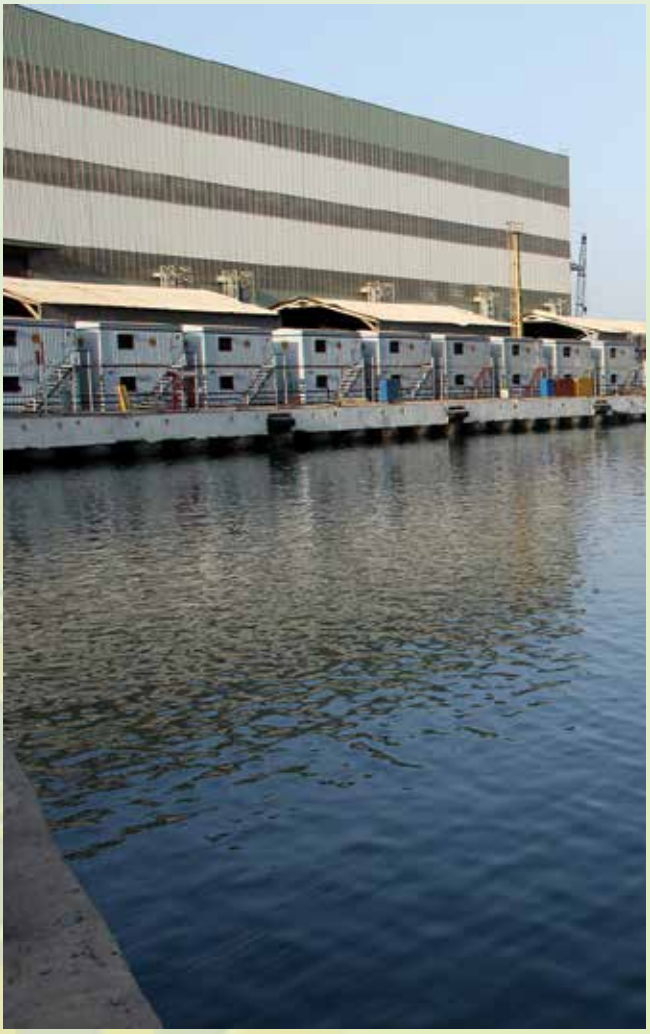


कसारा बेसिन का दौरा करते रक्षा मंत्री

23 अक्टूबर 1968 के सुबह 11 बजे, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत निर्मित प्रथम फ्रीगेट, आईएनएस नीलगिरि का जलावतरण एमडीएल के स्लिपवे से किया। उसी दिन इस पोत को नए कसारा वेट बेसिन में खींच कर लाया गया और दक्षिण दीवार की छोर पर आउटफिटिंग के लिए रखा गया।

कसारा बेसिन निर्माण में दोनो किनारों पर क्रेन ट्रैक बिछाना, बेसीन में पूर्व तरफ भराईकर नया जहाज घाट का निर्माण करने के साथ ही एक नई जेट्टी का निर्माण भी करना था। सन् 1963 के अंत तक साउथ यार्ड में 450 फुट लंबे स्लिप-वे का निर्माण किया गया (जहाँ पहले युद्धपोत नीलगिरी का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था) साउथ यार्ड में ही उत्पादन और एसेम्बली शाप का निर्माण सन् 1967 में पूरा हुआ और इसके साथ ही एमडीएल परिसर में अनेक कार्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। प्रोडक्शन एंड एसेम्बली शॉप के साथ प्लेट पर मर्किंग करने के लिए मॉर्डन ऑप्टिकल टावर का निर्माण, वेल्डिंग, गैस कटिंग, प्लेट बेंडिंग मशीन की स्थापना की गई, जिससे कि 40 टन वजन के स्टील मैटेरियल को प्री-फेब्रिकेटेड इकाई में तेजी से रूपांतरित किया जा सके। दक्षिण यार्ड के स्लीप-वे के दोनों तरफ क्रेन ट्रैक पर 15 टन क्षमता की लफिंग क्रेनों की स्थापना की गई। 80 टन की भारी लिफ्ट तथा बर्थ साइड क्रेन रिची ड्राय के ट्रैक पर बिठाई गई।

कसारा बेसीन को चारो ओर से बंद वेटडॉक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया और 23 अगस्त 1968 को इसमें पानी भरा गया। जलबंद (काफर डैम) खुलने के दो माह बाद 23 अक्टूबर 1968 को भारत में निर्मित पहले युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी को उसी दिन जलावतरण के पश्चात खींचकर कसारा वेटडॉक में लाया गया था। यहाँ युद्धपोत को दक्षिणी दीवार से बाँधकर बाह्य सज्जा का कार्य पूरा किया गया।



नया कसारा बेसिन

विस्तार योजना की प्रगति के साथ अतिरिक्त सुविधायें भी चरणबद्ध रूप से उपलब्ध होने लगी। विस्तार के विभिन्न चरणों के दौरान भूमि पट्टे पर आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त किया गया। मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा दक्षिण यार्ड से अपना पट्टा समाप्त होने के बाद जनवरी 1962 में हट गया।

अलकाक एशडाउन एरिया का क्षेत्रफल 9.50 एकड़ था, जिसे माझगाँव डॉक ने सन् 1973 में अधिग्रहण किया और 5.75 एकड़ भूमि समुद्र में भरकर निरंतर बढ़ाया है। कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और सुविधाओं का उन्नयन भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के 10 सालों में पूरा किया गया, जिसके कारण यार्ड की विशाल अभियांत्रिकी क्षमता में वृद्धि हुई। एमडीएल एक संतुलित छोटे जहाज मरम्मत यार्ड से धीरे-धीरे विकसित होकर भारत के पश्चिमी तट पर भारत का मुख्य और देश का अग्रणी शिपयार्ड बना है।

मेक इन इंडिया पहल



तपन कुमार मण्डल
प्रबंधक (पी15बी)

भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' नीति का पालन करते हुए माझगांव डॉक ने पोत निर्माण में स्वदेशीकरण प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया है। इस जलावतरण के साथ कम्पनी अपने स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता को निरंतर विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

युद्धपोत / पण्डुब्बियों के रूपांकन और निर्माण का कार्य बहुत ही जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि युद्धपोत / पनडुब्बी में बड़ी मात्रा में अभियांत्रिकी, विधुतीय, इलेक्ट्रानिक और पोतकाय एवं आयुध प्रणाली में विविध प्रकार की तकनीकी कौशल प्रौद्योगिकी शामिल होती है। अनेक मुख्य अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक और आयुध प्रणालियाँ आज भी आयात की जाती हैं क्योंकि इनका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। आयातित प्रणालियाँ न केवल बहुत महंगी हैं अपितु असंतोषजनक लाईफटाइम सपोर्ट की प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं जो पोतों / पण्डुब्बियों की मारक क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से युद्ध के दौरान इनका समय से उपलब्ध होना, संतोषजनक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। ऐसी अति निर्भरता विभिन्न प्रणालियों की उच्च लागत वाली प्राप्तियाँ विदेशी कंपनियों से जुड़ी हुई हैं। इसका निराकरण केवल स्वदेशी रूपांकन, विकास और निर्माण उद्योग में प्रोत्साहन देकर किया जा सकता है। मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक लक्ष्य है जो भारत को निर्माण केंद्र के रूप में तब्दील कर सकता है और काफी हद तक इससे सैन्य मामलों में हम आत्म निर्मर हो सकते हैं।

एमडीएल युद्धपोत / पण्डुब्बियों का निर्माण ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विशेष विवरण / मांग के अनुसार करता है और विभिन्न उपकरणों / प्रणालियों को संग्रहीत करके युद्ध के लायक बनाता है। कुछ उपकरण प्रत्यक्ष रूप से युद्धपोतों पर लगाने के लिए ग्राहक द्वारा प्रदान किए जाते हैं और शिपयार्ड में सुसज्जित और एकीकरण के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में अभियांत्रिकी, विधुतीय, इलेक्ट्रानिक और आयुध प्रणालियाँ शिपयार्ड में ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट विक्रेताओं (वेंडरों) से एकल निविदा / जांच के आधार पर प्राप्त की जाती हैं जिससे कि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी और गुणवत्ता शर्तों को पूरा किया जाता है। शिपयार्ड में यह सहूलियत नहीं है कि शेष सामग्री उपकरण की प्राप्ति विभिन्न विक्रेताओं से प्रतियोगिता के आधार पर करे जिससे कि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी और गुणवत्ता शर्तों को पूरा किया जा सके। फिर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिकतर उपकरण ग्राहक द्वारा नामांकित किए जाते हैं जो युद्धपोतों / पनडुब्बी में निर्धारित लक्ष्य के अपेक्षित कार्य पर आधारित होते हैं।

पी15 बी पोत की विशेषताए :-

पोत का प्रकार	मिसाइल विध्वंसक
संपूर्ण लंबाई	163.2 मीटर
चौड़ाई	17.4 मीटर
डिजाईट ड्राट	0.05 मीटर अधिकतम 6.5
विस्थापन क्षमता	7300 टन
गति	30 नाट
प्रोपेल्सन	कोगैग

मोरमुगाओं:- पी15 बी के दूसरे विध्वंसक मोरमुगाओ का जलावतरण 17 सितम्बर 2016 को नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल सुनील लांबा की उपस्थिति में श्रीमती रीना लांबा द्वारा किया गया है। ये गाइडेड मिसाईल विध्वंसक अपने पुर्ववर्ती पी15 बी कोलकाता श्रेणी के अनुवर्ती हैं।

इन पोतो में प्रौद्योगिकी का उन्नत रूप स्थापित किया जायेगा। यह पोत द स्टेट आफ आर्ट प्लेटफार्म, कम्बेट सिस्टम से सुसज्जित हैं इसके माध्यम से भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी।

इन पोतो की लम्बाई 163 मीटर है। इसमें चार गैस टरबाईन इंजन



लगाये गये हैं। पानी में इसकी विस्थापन क्षमता 7300 टन है इनका रूपांकन विशेष रूप से किया गया है जिससे कि समुद्र में गति 30 नाट से कम न हो। स्वदेशी रूपांकन स्टील्थ विध्वंसक में स्टेट आफ द आर्ट वेपन, सेन्टर और अग्रिम सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली विश्वस्तरीय माडूलर लिविंग स्पेस, परिस्कृत ऊर्जा वितरण प्रणाली, और अन्य अग्रिम विशेषताएँ शामिल की गई हैं।

यह विध्वंसक सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाईल सिस्टम से सुसज्जित होगे। जिससे कि पोत की एयर डिफेंस कैपेसिटी और एन्टीशिप क्रुज मिसाईल के खतरों से मुकाबला कर सके। इनमें 30 एमएम की रैपिड फायरगन स्थापित की गई है जिसमें समीप से रक्षा करने की क्षमता होती है और एम आर गन से कारगर नौसेना गन फायर सपोर्ट प्राप्त करने में सहायता मिलती है। स्वदेशी रूप से विकसित डुएयल ट्यूब टारपीडो लांचर्स और राकेट लांचर्स से पोत के एन्टी सबमैरीन क्षमता में वृद्धि होगी।

मोरमुगाओ उत्पादन आरम्भ तिथि - 29 जूलाई 2014
कील लेइंग - 04 जून 20

पी17 - इस परियोजना के अंतर्गत चार स्टील्थ युद्धपोतों का निर्माण करना है। पिछले वर्ष पोत का उत्पादन आरंभ हुआ। अनुभव की विपुलता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के कारण भविष्य में बनने वाले पोतों की लागत तथा निर्माण समय में कमी आएगी। भारतीय नौसेना की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमडीएल सतत तैयार है। इस प्रकार एमडीएल भारत सरकार के कार्यक्रम - 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार कर रहा है।

पनडुब्बी



गीता सुनतकरी
प्रबंधक (योजना-पूर्वखंड)

समुद्री विध्वंसक एवं रक्षक: पनडुब्बी समुद्र के अंदर व सतह पर चलने वाला एक जलयान है। इसका हिंदी में शाब्दीक अर्थ है 'पानी के अंदर डूबकर चलने वाला यान'। इसका मुख्य कार्य जल के अंदर और सतह पर रहकर शत्रु के युद्धपोत, जलयान, पनडुब्बी एवं वायुयान को राडार और सोनार की सहायता से टॉरपीडो और प्रक्षेपणास्त्र द्वारा नष्ट कर परास्त करना है। पनडुब्बी का आविष्कार इस योजना के आधार पर की गई कि समुद्री सतह पर रहकर शत्रुपक्ष के युद्धपोत और जलयानों को नष्ट नहीं किया जा सकता है।

सर्वप्रथम सन १६२० में एक डच नागरिक 9कार्नलियस ड्रेबेल" ने पहली पनडुब्बी इंग्लैंड के राजा 9जेम्स प्रथम" की सेवाओं के लिए प्रस्तुत किया। पहली मिलिट्री पनडुब्बी 9टरटिल" सन १७७५ में एक अमेरिकन डेविड बुसनेल द्वारा बनाई गयी थी। यह पूर्णत: हस्तचालित थी और समुद्र जल के अंदर एक आदमी को ले जाने में सक्षम थी।

पनडुब्बी के प्रकार

(A) **स्वरूप के आधार पर - मुख्यत:** तीन तरह की पनडुब्बीयाँ होती है

(1) दबित पनडुब्बी : दाबयुक्त पनडुब्बी का प्रयोग समान्यत: बहुत छोटी और खर्चीली होने के कारण धनी लोगों के द्वारा समुद्री जीवन का आनंद उठाने के लिए किया जाता है।

(2) वैज्ञानिक पनडुब्बी : वैज्ञानिक पण्डुब्बियों का प्रयोग समुद्र और झील की तली का निरीक्षण करने और वहाँ से जैविक सैंपल लाकर वैज्ञानिक शोध कार्य करने हेतु होता है। **डी.एस.वी.एल्विन** उपरोक्त पनडुब्बी का एक उदाहरण है।

(3) मिलिट्री पनडुब्बी : मिलिट्री पनडुब्बी का प्रयोग प्राय: नौ सेना द्वारा अणुनाभिकीय युद्ध, बैलास्टिक मिसाइल और भारी बमबारी की सहायता से अवरोध उत्पन्न करके दो देशो के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। इस प्रकार कीग पनडुब्बी का प्रयोग अधिकांशत: दुनिया के सभी देशों द्वारा विशेषतया अमेरीका, ब्रिटेन, नार्थ कोरिया, चीन और रूस द्वारा किया जाता है। इसका उदाहरण अमेरिकन सीवुल्फ़ क्लास की पनडुब्बी है।

(B) **ईधन के आधार पर :**

(1) डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी : डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में डीजल इंजन के साथ-साथ बैटरी भी होती है। सन 1928 में अमेरिकन नेवी ब्यूरो ऑफ इंजीनियरिग ने एक प्रस्ताव दिया कि समुद्र सतह पर पनडुब्बी के प्रोपेल्लर को सीधे न चलाकर डीजल-इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कर दिया जाय। जिसके अनुसार डीजल-इंजन पहले जेनरेटर चलाएगा जिससे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कर दिया जाय। जिसके अनुसार डीजल-इंजन पहले जेनरेटर चलाएगा जिससे इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होगी। बाद में यह बैटरीया चार्ज होकर इलेक्ट्रिक मोटर चलाएगी जो प्रोपेल्लर साफ्ट से युग्मित रहता है वह साफ्ट को घुमाएगा। माझगांव में बनी सभी पनडुब्बियाँ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं।

(2) अणुशक्ति चालित पनडुब्बी : इस प्रकार की पनडुब्बी में मुख्यत: न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होता है जो शुद्ध इनरिच यूरेनिअम का प्रयोग करता है। यह प्लांट स्टीम का उत्पादन करता है और यही स्टीम प्रोपेल्लर को चलाती है। इस प्रकार की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी अरिहंत है।

C) अणुशक्ति चालित पनडुब्बी : दुनिया के विकसित देशों की नौसेनाओ के पास मुख्यत: तीन प्रकार के वेपन पनडुब्बी होती हैं।

(1) **गाइडेड-मिसाइल पनडुब्बी:** इस प्रकार की पनडुब्बी सतह पर आक्रमण के लिए एकबार 154 क्रुज मिसाइल ले जा सकती है जिससे उस देश की पूरी नौ सेना मजबूती से खड़ी रह सके।

(2) **बैलास्टिक मिसाइल पनडुब्बी:** यह पनडुब्बी अंतरद्विपीय सामरिक युद्ध के लिए न्यूक्लियर मिसाइल ले जाती है।

(3) **अटैक पनडुब्बी :** यह शत्रुपक्ष के युद्ध पोतो और पण्डुब्बियों को निशाना बनाती है। इसके अलावा समुद्र तल में माइन बिछाना और सूचना संग्रह करना इसका मुख्य कार्य है।

श्रेणी और वर्ग :

पनडुब्बी और युद्धपोतों के संदर्भ में श्रेणी और वर्ग इन दो शब्दों का प्रयोग हमेशा होता है। यह वर्ग प्रत्येक बोट की प्रकृति (मारक क्षमता, विधि, प्रकार और आयुध) को बताता है। जबकि श्रेणी प्रथम बोट के रूप में बाकी सारे बोटों का प्रतिनिधित्व करता है। पनडुब्बी की स्पीड **'नॉट'** में मापी जाती है। एक नॉट या नोटिकल माइल्स 1.852 किमी / घंटा अथवा 1.151 मील / घंटा होता है। भारतीय पनडुब्बी की अधिकतम गति 11 नॉट (20 किमी / प्रतिघंटा) होती है। चीन ने सन 2013 में अपने पनडुब्बी की सबसे तेज गति लगभग 100 नॉट घोषित किया था।

आजकल दुनिया के 40 देशो द्वारा लगभग 450 से ज्यादा पण्डुब्बियों का प्रयोग सामरिक कार्यों के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा 74 पनडुब्बी रूस के पास हैं, दुसरे नंबर पर अमेरिका के पास 72 तीसरे नंबर पर चीन के पास 63, चौथे नंबर पर ईरान के पास 32, पाँचवे नंबर पर जापान के पास 18, छटें नंबर पर भारत के पास 15, और पाकिस्तान के पास कुल 08 (हसमत, हुरमत, खालिद, शाद, हमजा और मिगजेट टाइप की X- क्राफ्ट) पनडुब्बियाँ हैं।

आई.एन.एस.सिंधुरक्षक की 14 अगस्त, 2013 को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद भारत के पास कुल 15 पनडुब्बीयाँ बची हैं। इसमें रसियन मूल की सिंधुघोष श्रेणी की एस.एस.के. किलो क्लास की 09 पनडुब्बी, भारत में निर्मित एस.एस.के क्लास की, शिशुमार श्रेणी की 04, एक अणुशक्ति चालित एस.एस.एन क्लास की चक्र श्रेणी की 01, रशिया से 10 वर्ष के लिए लीज पर ली गयी आई.एन.एस चक्र हैं। एक स्वदेशी न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी की एस.एस.एस.बी.एन क्लास की अरिहंत है। इस श्रेणी की दूसरी निर्माणाधीन पनडुब्बी अरिधमन है। इस श्रेणी की कुल चार पनडुब्बियाँ है जबकि दो अभी बनाना बाकी है। अरिहंत का हारबर ट्रायल और समुद्री ट्रायल दिसम्बर 2014 में शुरू हुआ था।

एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 7-8 पारंपरिक पण्डुब्बियों को दुश्मन सेनाओ के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। सक्रिय रूप से मात्र 13 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बीयाँ हैं, जिसमें से 10 वर्ष से अधिक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। भारतीय नौसेनाओं में मजबूत बेड़ा के रूप में फेस सेवर आई.एन.एस चक्र विराजमान है।

भारतीय नौसेना और पण्डुब्बियों के कुछ तथ्य:

1) पनडुब्बी के पायनियर	सन 1962 में पनडुब्बी के प्रथम प्रशिक्षुओं के समूह का प्रशिक्षण एच.एम.एस (HMS) डॉल्फ़िन पर दिया गया।
2) प्रथम भारतीय पनडुब्बी	8 दिसंबर, 1967 को प्रथम पनडुब्बी आई.एन.एस कालवरी को कमोडोर श्री के सुब्रमण्यम को सुपुर्द किया गया।
3) प्रथम भारतीय पनडुब्बी सैनिक को महावीर चक्र	कमोडोर श्री एम.एन.सावंत
4) सन 1971 के युद्ध में भाग लेने वाली प्रथम पनडुब्बियाँ	a) आई.एन.एस करंज (कमोडोर बी. एस. शेखावत के अधीन) b) आई.एन.एस कुरसुरा (कमोडोर ए. औदितों के आधीन) c) आई.एन.एस खांडेरी (कमोडोर राय मिलन के अधीन)
5) प्रथम भारतीय पनडुब्बी को वीर चक्र	तत्कालीन कमोडोर बी.एस. शेखावत (बाद में चीफ नेवल स्टाफ,)
6) भारतीय नौसेना की सिंधुघोष श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी	आई.एन.एस सिंधुघोष (30 अप्रैल 1986 को कमोडोर के.सी.को सुपुर्द किया गया
7) भारतीय नौसेना की एस.एस.के की प्रथम पनडुब्बी वर्ग	आई.एन.एस शिशुमार (22 दिसम्बर, 1986 को कमोडोर पी.एम. भाटे को सुपुर्द की गयी)
8) भारतीय नौसेना द्वारा प्रथम अणुशक्ती चालित पनडुब्बी	आई.एन.एस चक्रा (अकुला वर्ग) (जनवरी, 1988 से 1991 तक कैप्टन आर.एन. गणेश के अधीन)

9) स्वदेश निर्मित एस.एस.के वर्ग की प्रथम पनडुब्बी	आई.एन.एस शल्की (06 फरवरी 1992 को कमोडोर श्री के.एन. सुशील को सुपुर्द की गयी।
10) (माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई) प्रथम मिसाइल से सुसज्जित पनडुब्बी	आई.एन.एस सिंधुशास्त्र (19 जुलाई 2000 को कमोडोर आर. शरीन को सुपुर्द की गई।

डिकमीशण्ड सबमैरीन:

1) चार्ली क्लास - आई.एन.ए, चक्रा (S71) k43 सन 1987-1991 के बीचलीज़ पर थी।

२) कालवरी क्लास - आई.एन.एस करंज (S21)
आई.एन.एस खंडेरी (S21)
आई.एन.एस कालवरी (S23)

३) बैला क्लास - आई.एन.एस बेला (S40)
आई.एन.एस वागीर (S41)
आई.एन.एस वागली (S42)
आई.एन.एस वागशीर (S43)

माझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड का इतिहास लगभग 243 वर्ष पुराना है। यहाँ एक छोटी गोदी सन 1774 में बनी थी। यह आज भी दुनिया की सबसे पुरानी क्रियाशील गोदीयों में से एक है। यहाँ भारतीय नौसेना के शिपरिपेयर का काम शुरू किया गया था और सन 1960 में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन उपक्रम के रूप में अधिग्रहण किया गया यह दुनिया के बड़े शिपबिल्डरों में एक ISO-9001 प्रमाणित राष्ट्र का पोत निर्माता कंपनी है।

यह सदैव भारतीय नौसेना के लिए नवलशिप, ऑफशोर, प्लैटफार्म, टैंकर, बल्क कॅरियर, प्लैटफार्म सप्लाई वेसल और पेट्रोल बोट बनाने में संलग्न रहा है।

सन 1984 में तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा माझगांव डॉक लिमिटेड में पनडुब्बी यार्ड का अनावरण करने के बाद भारतीय नौसेना के इतिहास में एक नए दौर का सूत्रपात हुआ। सबसे पहले यहाँ जर्मन प्रौद्योगिकी के आधार पर दो पनडुब्बियों (शंकुल और शल्की) के निर्माण का पहला आदेश प्राप्त हुआ। इस यार्ड ने अपनी अतिउत्तम प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रशिक्षित कार्मिको के लगातार प्रयत्न से अपने लक्ष को प्राप्त कर लिया, जिसके परिणाम स्वरुप 7 फरवरी 1992 को शल्की और लगभग दो वर्ष बाद 28 मई 1994 को शंकुल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

इससे उत्साहित होकर भारतीय नौसेना ने सन 2005 में कालवारी श्रेणी की अटैक सबमैरीन (स्कोर्पिन, P-75) की छः बोटों हेतु लगभग 23,000/- करोड़ रुपये का निर्माण आदेश दिया है। कालवारी श्रेणी की प्रथम बोट आई.एन.एस कालवारी का जलावतरण सितम्बर 2015 में किया गया और सितम्बर 2016 में सुपुर्दगी की गई है। इस श्रेणी की दूसरी बोट खांडेरी है।



कलवरी का चित्र

पी -75 परियोजना



स्कोर्पिन पनडुब्बी की विशेषताएँ-
श्रेणी - स्कोर्पिन
सम्पूर्ण लंबाई - 61.7 मीटर
अधिकतम चौढ़ाई - 6.20 मीटर
विस्थापन - 1565 टन
गति - 200 नाट



खंडेरी (यार्ड 11876)

प्रेसर हल का निर्माण - मई 2010
बूट टुगेदर - नवंबर 2015
अनडाकिंग - नवंबर 2015
बैटरी कमीशनिंग - अक्टूबर 2016
जलावतरण - 2017

स्कोर्पिन श्रेणी पनडुब्बी - स्वदेशीकरण का प्रयास

मेन थ्रस्ट ब्लॉक - सीओ 2 एब्जर्बर
बालास्ट वेंट वाल्वज - स्टियरिंग कंट्रोल



वेपन हैंडलिंग एवं स्टोरेज सिस्टम - आर ओ प्लांट्स
टॉरपीडो लांचिंग ट्यूब्स - हल हैचेज़
एचपीएआर बाटल्स - नॉन रिर्टन वाल्वज
एसएसए वर्कशाप में निदेशक मण्डल का चित्र

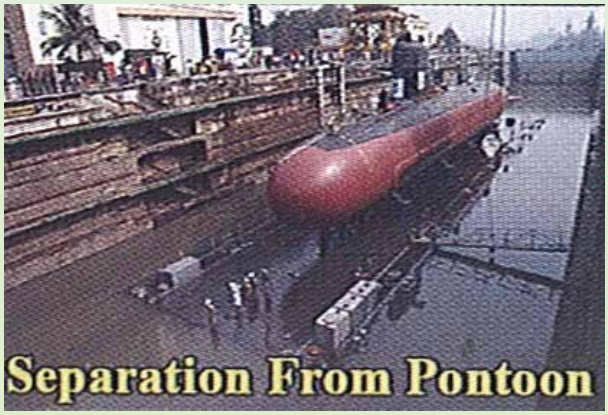


एमडीएल में बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि

युद्धपोत एवं पनडुब्बी निर्माण



खंडेरी का जलावतरण



पंटून से पन्डुब्बी का पृथक्करण

खंडेरी

समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर खंडेरी की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना में 2017 में की जाएगी। खंडेरी एक खतरनाक मछली का नाम है। इसके नाम पर ही पनडुब्बी का नाम रखा गया है। भारतीय नौसेना में खंडेरी नाम की पनडुब्बी 06 दिसंबर 1968 को शामिल की गई थी। 20 साल की सेवा के उपरांत उस पनडुब्बी की डीकमीशनिंग 18 अक्टुबर 1989 में हुई थी। नौसेना में एक परंपरा है कि डीकमीशन्ड पण्डुब्बियों के नाम पर नई पनडुब्बी का नामकरण किया जाता है।

माझगांव डॉक लिमिटेड के पुराने इतिहास को देखते हुए इसके स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना करना और उद्योग जगत में उच्च शिखर पर स्थापित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यह भारत के लिए एक गौरवमयी ताज के तुल्य है। इस यार्ड ने अपने आपको उस स्थान पर स्थापित कर लिया है जहाँ दूसरे राष्ट्रों को पहुँचने में समय लगेगा।

ऐसे कर्मठशील एवं प्रयत्नशील उपक्रम को मेरा शत्-शत् नमन।



जलावतरण के समय खंडेरी का चित्र





जॉन अब्राहम
उमप्र (इन्फ्रा प्रोजेक्ट)

एसएसए वर्कशॉप

अलकाक यार्ड में ओ, एन, जी, सी के जैकअप रिग, प्रतितट मंच का कार्य समाप्त होने के पश्चात कोई नया आदेश नहीं मिला और यार्ड के उपकरणों और मशीनरी का उपयोग नहीं हो रहा था। उस बड़े भूभाग का समुचित उपयोग करना जरूरी था।

पूर्व खंड में पनडुब्बी निर्माण के लिए स्थान की कमी को देखते हुए प्रबंधन ने योजना बनाई गई कि अलकाक यार्ड की खाली जमीन का उपयोग पनडुब्बी निर्माण हेतु बुनियादी सुविधा का विकास करने के लिए किया जाय। कंपनी को नौसेना से 06 स्कोर्पीन पनडुब्बी निर्माण का आदेश मिला हुआ है उन्हे समय से पूरा करना आवश्यक है क्योकि इस योजना पर कार्य विलंब से आरंभ हुआ है। बुनियादी संसाधनों की सहायता से निर्माण अवधि तथा लागत में कमी होगी जिससे भविष्य में और आदेश प्राप्त होंगे। कार्य प्रचुरता तथा भावी योजना का विचार करते हुए अलकाक यार्ड में पनडुब्बी के लिए एसएसए वर्कशॉप निर्माण किया गया है।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को भारतीय नौसेना की ओर से 06 स्कोर्पीन श्रेणी पण्डुब्बियों निर्माण करने का आदेश परियोजना पी75 के अंतर्गत दिया गया है। एमडीएल के पास पहले से ही पूर्व खंड में सबमैरीन एसेम्बली के लिए ड्राई डॉक से सुसज्जित कार्यशाला है। फिर भी यह सुविधा भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी निर्माण समय सीमा में तैयार करके सुपुर्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पण्डुब्बियों की सुपुर्दगी समय सारणी को पूरा करने के लिए वर्तमान के साथ साथ भविष्य की मांगो को पूरा करने के लिए भी एमडीएल ने पनडुब्बी निर्माण हेतु अपनी बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन करना शुरु किया है। सबमैरीन सेक्शन एसेम्बली वर्कशॉप अलकाक यार्ड में बुनियादी सुवि धा संवर्धन कार्यक्रम का एक अंग है। इसके निर्माण से एमडीएल को भारतीय नौसेना के लिए पण्डुब्बियों की सुपुर्दगी तथा रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख विशेषताएँ - इस कार्यशाला का आकार निम्नलिखित है लंबाई लगभग 220 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर है और ऊंचाई 39 मीटर है । इसकी संरचना स्टील के साथ ही सहायक संरचना आरसीसी से



एसएसए वर्कशॉप का आंतरिक चित्र

निर्मितकी गई है इसमें कार्यशाला भवन और रेस्टरूम भी है। पूर्व निर्मित भवन में एमएस स्लाइडिंग डोर लगे हैं जिसकी लंबाई 40 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है इसके साथ ही पूर्वी केबल के छोर पर 4 पैनल लगे हुए हैं जिससे 30 मीटर लम्बे और 18 ऊंचे क्रेन से पूरे पनडुब्बी का मूवमेंट किया जा सकता है। कार्यशाला की छत वैकुम डीवाटर्ड है जिसमें इमबेडेड लैंड 2 मीटर x 2 मीटर सी वी की टाईल्स लगी हुई। इस वर्कशॉप में यूटिलिटी सेवाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें ऑक्सिजन, फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फोर्सड काम्प्रेसड एयर सिस्टम, वाटर स्पायर्स और फायर फाइटिंग सिस्टम, फोसर्ड एयर वेंटीलेशन सिस्टम लगे हुए हैं। वर्कशॉप में 4 ईओटी क्रेन लगी हुई है जिनकी क्षमता 30 टन हैं। ये दो स्तरीय हैं। 02 नग सेमी गोलीएथ क्रेन भी लगार्ड गई है जिनकी क्षमता 150 टन है और 01 नग 60 टन क्षमता की सेमी गोलीएथ क्रेन बाटम टियर में लगाई गई है। जिसमें सबमैरिन के संचालन में सुविधा हो। वहाँ पर एक ब्लास्टिंग एवं पेंटिंग चेम्बर है।

कार्यशाला क्षेत्र में ही अंदर वॉशिंग एरिया है। जहाँ पनडुब्बी अनुभाग की सफाई और ब्लास्टिंग के साथ पेंटिंग की सुविधा है।

विश्राम कक्ष भवन

इसमें भूतल के साथ 03 मंजिला आरसीसी से निर्मित सुपर स्ट्रक्चर हाउसिंग सब स्टेशन भूतल पर बना हुआ है। पेंट्री एरिया प्रथम तल पर है और लाकर एसएम माडूलर टायलेट / कामगारों के लिए बनाया गया है बाथरूम दूसरे और तीसरे मंजिल पर पैसेंजर लिफ्ट के साथ उपलब्ध है। अगले हिस्से में दूसरे तल पर हल एवं विद्युत विभाग का कार्यालय है तीसरे ताल पर वित्त विभाग का कार्यालय है और चौथे महले पर पूर्व खंड वाणिज्य विभाग का कार्यालय माडुलर चेयर से सुसज्जित है।

जल प्रबंधन प्रणाली

रिसायकिल वाटर का उपयोग कार्यालय भवन और विश्राम कक्ष में किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी, ग्रेवाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ऑइल वाटर सेपरेटर की सुविधा ट्रीटेड वाटर का उपयोग करने के लिए किया जाता है।

पर्यावरण का प्रभाव

यह कार्यशाला एमडीएल परिसर के अंदर खुली भूमि पर निर्मित की गई है इसलिए इससे समुद्री पर्यावरण को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा।
इस कार्यशाला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जीरो डिस्चार्ज के साथ प्रदान किया गया है इससे कोई जल प्रदूषण नहीं होगा।
फ्यूम एकट्रेक्शन सिस्टम कार्यशाला में लगाया गया है। जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा।





एसएसए वर्कशॉप और मोड्युल शॉप में पण्डुब्बियों की एसेम्बलिंग

एसएस परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी

नए निर्माणाधीन क्षेत्र में उपरोक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. सम्पूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र - लगभग 63950 वर्गमीटर
2. एसएसए कार्यशाला क्षेत्र - लगभग 96000 वर्गमीटर
3. कार्यालय भवन - लगभग 2740 वर्गमीटर
4. विश्राम कक्ष भवन - लगभग 730 वर्गमीटर
5. रोडवेज - लगभग 8500 वर्गमीटर

1. कार्यशाला भवन

कार्यशाला क्षेत्रफल - 220.40 मीटर लम्बाई
44.00 मीटर चौड़ाई
39.00 मीटर ऊंचाई

कार्यालय भवन - इस भवन में लगभग 250 मीटर कार्मिकों के आवास की व्यवस्था है।

2. विश्रामकक्ष भवन

- इस भवन में लगभग 525 कार्मिकों के कपड़े बदलने की जगह और प्रसाधन की सुविधा है।
- भूतल के साथ तीन मंजिला आरसीसी संरचना में एलीवेटर लगा हैं।
- भूतल पर इलेक्ट्रोनिक पैनेल लगाया गया है।
- प्रथम तल पर डाइनिंग एरिया में एक समय 170 कर्मचारी खाना खा सकते है।
- प्रसाधन विश्राम कक्ष सहित लाकर दूसरी और तीसरी मंजिल पर उपलब्ध है।
- टेरिस फ्लोर का रूपांकन इस प्रावधान से किया गया है जिसमें बगीचा जैसी हरियाली की विशेषताएँ हैं।

4. सहायक भवन

कामगारों के लिए शौचालय, फायर वाटर टैंक एवं एफएफ पम्प रूम
क्षमता - 3,50,000 लीटर,
क्षमता - 3,50,000 लीटर



गणेश गोल्हा
प्रबंधक (मा.सं.पू.ख)

एमडीएल शिपयार्ड में बुनियादी सुविधाएं

माझगांव डॉक ने बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण संवर्धन और उन्नयन करने की आवश्यकता सन 1981 में अनुभव किया जब यूके की फार्म मेसर्स एप्लोडर ने सिफारिश किया कि यहाँ पर माडुलर हल कंस्ट्रक्शन शॉप के साथ हेवी ड्यूटि गैन्ट्री क्रेन की स्थापना की जाए।

यह बुनियादी संवर्धन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि एमडीएल के नजदीक कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। फिर भी मई 1998 में एमडीएल ने इस समस्या का समाधान खोज लिया और एमडीएल के दक्षिण यार्ड से सटी हुई सिंधिया वर्कशॉप लिमिटेड की भूमि का अधिग्रहण कर लिया। सन 1997 की समांतर कार्रवाई में, रक्षा मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय दल का गठन विकसित देशों के कुछ शिपयार्ड का दौरा करने के बाद अपना निम्न अवलोकन प्रस्तुत किया।

अ) सभी शिपयार्डों ने माडुलर निर्माण की परिकल्पना को स्वीकार किया है जिससे 65% से 85% तक बाह्यसजा कार्य जहाज के जलावतरण से पहले पूर्ण कर लिया जाता है।
आ) कम्पुटराइज़ड योजना, लाजिस्टिक सूचना प्रणाली आरंभ कर दी गई है।
इ) क्रेन की क्षमता 150 टन से अधिक पाई गई थी। तदनुसार निम्नलिखित सिफारिशों को शिपयार्ड में लागू किया गया।
अ) जल के नीचे प्लाजमा सीएनसी प्लेटकटिंग मशीन की स्थापना।
आ) सीएनसी पाइप बेडिंग मशीन का प्रतिस्थापन।
इ) माडुलर शॉप के साथ माडुलर निर्माण क्रेन सुविधा के साथ।
ई) कम से कम 150 टन की क्रेन का उपयोग माडुलर शॉप से स्लीप-वे पर ले जाने के लिए किया जाए।
उ) रूपांकन, योजना, सामग्री, प्रबंधन इत्यादि के लिए कम्पुटराइज़ड प्रणाली का उपयोग करना।

स्कोर्पिन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के अंग के रूप में मेसर्स - थेल्स और मेसर्स डीसीएन के एक दल ने एमडीएल का दौरा किया और यहाँ उपलब्ध सुविधाओं की जांच किया।

उन्होंने सिफारिश किया कि एमडीएल में क्रेडल एसेम्बली शॉप के साथ एक अतिरिक्त भंडार का निर्माण किया जाए। इस सिफारिशों पर कार्य वित्तीय कारणों से रुका रहा। इसी बीच माझगांव डॉक ने समर्पित इन हाउस परियोजना प्रबंधन दल का गठन किया और बड़ा बुनियादी सुविधा संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किया जिसे माझगांव आधुनिकिकरण परियोजना (एसएमपी) के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड की मेसर्स हासकोनिंग, बीवी (एचएनबीवी) को इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। मेसर्स एचएनबीवी विश्वप्रसिद्ध सलाहकार हैं इनको समुद्री निर्माण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इन्होंने अनेक शिपयार्ड एवं बन्दरगाहों का विकास किया है।

मेसर्स एचएनबीवी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के साथ गहन परस्पर चर्चा की गई यथा, जहाज निर्माण, एसडी एंड डी, अनुरक्षण और अंत में अनुमोदन होने पर अंतिम रूप दिया गया। यह निधि मंजूर होने पर पास किया गया। एमएमपी के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का



निर्माण ग्राहक वित्तपोषण संम्पति के रूप में नौसेना परियोजना के पर्याप्त निधि से किया गया है। इस परियोजना पर लगभग रुपये 826 करोड़ लागत आई है।

माझडॉक आधुनिकिकरण परियोजना में, मूलभूत सुविधाएं यथा एक नया वेट बेसिन, एक हेवी ड्यूटि गोलिएथ क्रेन, एक माडुल वर्कशॉप और पनडुब्बी के लिए एक क्रेडल एसेम्बली का निर्माण शामिल है। 300 टन की भारी गोलिएथ क्रेन के साथ माडुल वर्कशॉ प, जहाज निर्माण में निर्माण की माडुलर संकल्पना को अपनाकर क्रांतिकारक परिवर्तन कर रहा है।

स्टेट ऑफ आर्ट माडुल शॉप संकुचनशील छत के साथ, गोलियथ क्रेन के समालोचन से एमडीएल को एकीकृत माडुलर निर्माण संकल्पना को स्वीकार करने में सहायता करती है।

वर्तमान परंपरागत इकाई आधारित आगम - (40 से 50 टन) जिसमें बाह्यसज्जा केवल 35% की सीमा तक ही प्राप्त होती है। माडुलर तकनीकी के द्वारा हल निर्माण, बाह्यसज्जा और जहाजों की पैकींग 300 टन तक माडुल शॉप में हो सकती है।

जहां बाह्यसज्जा का वास्तविक प्रतिशत 65% तक बैठाया जा सकता है। इसके द्वारा निर्माण अवधि में विशेष कमी होगी।

स्टेट ऑफ आर्ट माडुल शॉप के अलावा एक क्रेडल एसेम्बली का निर्माण भी स्कोर्पिन पनडुब्बी के निर्माण कार्यक्रम के अंग के रूप में किया गया है।

क्रेडल एसेम्बली का मुख्य उपयोग संरचना एवं पूर्व बाह्यसज्जा क्रेडल स्ट्रक्चर के लिए यूनिट ब्लॉक एसेम्बली में किया जा रहा है। पनडुब्बी के विविध खंड क्रेडल (प्रत्येक 100 टन) की एक साथ जोड़ने की क्षमता, बहुत दिनों से अनुभव की जा रही थी। स्थान की कमी को सीएएस ने आंशिक रूप से हल कर दिया है। सीएएस को एक नए भंडार भवन



के साथ मिला लिया गया है जहां स्वचालित पुन:प्राप्ति प्रणाली की व्यवस्था है साथ ही संवेदनशील और परिष्कृत उपकरणों को नियंत्रित वातावरण में रखने की सुविधा है।

नया वेट बेसिन सिविल अभियांत्रिकी का सुंदर नमूना है जिसे समुद्री पर्यावरण के अनुसार बनाया गया है। यह नया वेट बेसिन 2700 वर्गमीटर के क्षेत्र में निर्मित है इसमें दो युद्धपोत और दो पनडुब्बी लंगर की क्षमता है और साथ ही 100 टन, 50 टन और 15 टन क्षमता लेवेल लुफ़्फ़िंग क्रेनें भी लगाई गई है। एमडीएल में केवल 1400 वर्गमीटर का कसारा वेट बेसिन है जिसका निर्माण सन 1968 में जहाजों की सर्विसिंग के लिए किया गया था यहाँ पर लंबे समय तक कार्य हो रहा है। लंगरगाह स्थान की कमी के कारण एमडीएल अबतक निर्माणाधीन युद्धपोतों के लिए नौसेना डॉकयार्ड/एनबीपीटी, में अपने जहाजों का लंगर करता था जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर हैं तथा जिसके कारण अनावश्यक रूप से श्रमिक, भंडार, मशीनरी आदि को नियमित रूप से नौसेना की सुविधाओं के लिए ढोया जाता था। नया वेट बेसिन संतुलित, टिकाऊ, ढाँचा के साथ बनाया गया है जो 75 वर्षों तक क्रियाशील रहेगा और इससे एमडीएल की लंगरगाह आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी।

गोलिएथ क्रेन की सफल संरचना एवं प्रतिस्थापन से यह दूर से माइलस्टोन के रूप में दिखाई देता है यह एमडीएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके निर्माण के पीछे अनेक बाधाएं और चुनौतियाँ थी। जिसमें एक हेवी ड्यूटि गैनट्री क्रेन शामिल है जो रेल पर 138 मीटर चौड़ाई में आर-पार स्लिप-वे एवं मोडुल शॉप के बाहर चलती है। इसको उठाने की क्षमता 300 टन है।

पीले रंग में तीन पाए पर स्थापित गोलियथ क्रेन समुद्र की ओर से क्रेडल शॉप का दृश्य



पीले रंग में तीन पाए पर स्थापित गोलियथ क्रेन



रोहित पंड्या
उप प्रबंधक (सी एस आर)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कम्पनी ने महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के कई जिलों में गरीब और आदिवासी समाज की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश किया है। सीएसआर के लिए आबंटित राशि का उपयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले उपयोग किया जाता है।

ठाणे जिला के खरडे गाँव में ग्रामीणों के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था, गरीब बच्चों के लिए साइकिल का वितरण, गाँववालों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था, बीड जिला में सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था, कुओं की सफाई करना, जल संचयन के लिए वृक्ष लगाना, कल्याण में कातकरी समुदाय के बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए एबीएम समाज प्रबोधन संस्था के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिसमें 100 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष से पहल की गई है। जिसमें मुंबई महानगर तथा डॉ. बाबा आमटे के वर्धा कुष्ठ आश्रम के लिए भी मशीने तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

मुंबई के केईएम अस्पताल में गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी और देहाती दोनों लोगों के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं।



माझगांव डॉक ने मुंबई महानगरपालिका द्वारा संचालित केईएम अस्पताल के नियोनेटल इंटेन्सिव केयर यूनिट के उपकरणों का नवीनीकरण करने की ज़िम्मेदारी लिया है। इसके लिए कंपनी ने अति आधुनिक उपकरण मंगाकर कुछ अनुभागों को सुसज्जित किया है। इसमें 42 बेड हैं जिसमें 15 वेंटिलेटर और 16 नॉन इंटेन्सिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट मशीन समाज के गरीब लोगों के लिए प्रदान की गई है। सरकारी अस्पताल के माध्यम से समुदाय के गरीबों, बंचितों के शिशुओं को सुविधाएं प्रदान करने की अनोखी पहल की गई है।



20 बधिर बच्चों की सहायता के लिए कोचलियर इम्पाल्स्ट सर्जरी की व्यवस्था कंपनी ने किया है। जो गरीबी के नीचे रहने वाले परिवारों से संबन्धित है उनको मेसर्स आर्टिफिचीयल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जनवरी 2016 तक 18 सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई है।

लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी ने थाना एवं रायगढ़ जिले के गरीब परिवारों के जरूरत मंद 5000 लोगों के मोतियाबिन्द (कैटेरेक्ट) आपरेशन का खर्चा उठाया है। इसके साथ कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल में ओपीडी विभाग, आपरेशन थियेटर, कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण के लिए साहयता कर रही है। आफ़थैल्मीक



एमडीएल द्वारा महिलाओं का मोतियाबिन्द (कैटेरेक्ट) आपरेशन

उपकरों की खरीद भी उनके लिए किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान : माननीय प्रधान मंत्री के आहवान पर स्वच्छ भारत अभियान की पहल कंपनी द्वारा व्यापक रूप से की गई है। इसके अंतर्गत कंपनी के गैर जरूरी अभिलेखों, ई-वेस्ट, ड्रेनेज लाइन की मरम्मत करने का कार्य पूरा किया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों से स्वच्छता पर निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया है जिसके माध्यम से चार उप समितियां गठित की गई है। इससे त्रिस्तरीय कार्यों का समायोजन किया जा रहा है।

1) कंपनी के भीतर 2) एमडीएल के बाहर 3) ग्रामीण क्षेत्रों में एमडीएल परिसर में कार्य - कंपनी के अंदर कार्यशाला प्रमुखों और ब्लॉक प्रमुखों को संबन्धित भवनों / कार्यस्थानों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है जिसमें आस पास के 15 मीटर क्षेत्रों को शामिल किया गया है।



शिपयार्ड के सभी कर्मचारी श्रमदान के माध्यम से प्रतिदिन 1/2 घंटा संबंन्धित कार्य स्थल पर सफाई में लगायेंगे। इसके अंतर्गत उस विभाग के पुराने अभिलेखों, ई-वेस्ट, मलवा को नियमित रूप से हटाएँगे। कैंटीन का कचरा दूर करने के लिए कंपनी परिसर में बायोगैस प्लांट लगाया गया है। कंपनी परिसर में सड़कों की सफाई के लिए एक रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी गई है जो नियमित रूप से सफाई कार्य करती है।





कंपनी में स्थित सभी शौचालयों का नवीनीकरण किया गया है और सतत सफाई का ध्यान रखा जाता है।

एमडीएल के दक्षिण यार्ड में स्थित स्लिवे पर पहले जहाज निर्माण विभाग के इस्पात, शीट की कतरन के अलावा अन्य प्रकार के कचरा पड़ा रहता था जिसे नियमित साफ सुथरा रखा जाता है।

चार नग पोर्टेबल मूत्रालय की स्थापना यार्ड में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल नियंत्रण छिड़काव आवासीय कॉलोनियों में किया जाता है और निगरानी करने की व्यवस्था की गई है।

पहले कंपनी में सबसे बड़े कसरा बेसिन के चारों ओर छोटी-छोटी झोपड़ीनुमा ठेकेदारों के कार्यशाला और कार्यालय के साथ कंपनी के विभागों के कर्मचारी झोपड़ीनुमा स्थानों पर बैठते थे। स्वच्छता अभियान के दौरान प्रबंधन ने इन सभी झोपड़ीनुमा छपरों को हटाकर सबके लिए पोर्टेबल कैबिन की व्यवस्था किया हैं।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था आवासीय भवन जैसे करी हाउस, आंग्रे हाउस और सबमैरीन वर्कशॉप पर की गई है। सबमैरीन प्रोजेक्ट के कार्यालय भवन में पीने के पानी तथा वेस्ट वाटर सेवा के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। कंपनी के भीतर स्थित सभी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, जिसके कारण कंपनी परिसर में कम धूल उत्पन्न होती है।

एमडीएल परिसर के बाहर की गतिविधियाँ - एमडीएल क्षेत्रों का चुनाव स्वच्छता के लिए प्रभाग के अनुसार किया गया है। जैसे समवाय, जहाज निर्माण, पनडुब्बी, वित्त प्रभाग।

एमडीएल परिसर के बाहर कंपनी की दीवार से सटी जयभीम नगर झोपड़पट्टी है। उनके लिए शौचालय बनाने की योजना इस वर्ष पूरी की जाएगी।

एमडीएल परिसर के बाहर की सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी कंपनी ने लिया है और एक एनजीओ की नियुक्ति सड़कों की सफाई हेतु किया है जिसमें कर्मचारी रखे गए हैं जो नियमित रूप से सड़कों की सफाई करते है और कंपनी का एक अधिकारी उसकी निगरानी करते हैं।

कंपनी के बाहर इस्टर्न एक्सप्रेस के नीचे बीपीटी रोड पर डिवाइडर के दोनों ओर सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने की योजना है।

कंपनी का प्रयास है कि एमबीपीटी, एमसीजीएम के सहयोग से स्थायी इको फ्रेन्डली ठोस कचरा प्रबंधन की योजना बनाई जाय और विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाए।

माझडॉक हाउस के सामने बगीचा की व्यवस्था की गई है। सौंदर्यीकरण करने के लिए गमलों में पौधे लगाए गए हैं और फर्श पर गार्डनिंग के लिए कृत्रिम घास भी लगाई गई है।

एमडीएल के परिसर के अंदर स्थित पोस्ट ऑफिस और पोलिस चौकी का नवीनीकरण और पेंटिंग किया गया है।



एमडीएल पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण



पी डी सिद्दीकी
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

अंग्रेजी भाषा और इतिहास

अंग्रेजों के साथ हमारा दोस्ती-दुश्मनी का रिश्ता रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनकी भाषा, साहित्य और सभ्यता को अपनाकर हम उन्हें जाने पर मजबूर क्यों करते ? यदि ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज भी यहाँ राज करते-करते बसने से परहेज क्यों करते ? यदि सब कुछ ठीक होता तो अंग्रेजी को अपनाकर उसे 15 वर्ष के बाद विदा करने का संकल्प क्यों लेते ?

और यदि संकल्प कर ही लिया था तो दो वर्ष बाद ही उसे रोकने का निर्णय क्यों लेते ? नेहरू जी तो कभी-कभी कवि की तरह बोलते थे: जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ तो इंग्लिस्तान की याद आती है और जब इंग्लिस्तान में होता हूँ तो हिंदुस्तान की याद आती है। हममें से कितने ही क्यों कहते : जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिन्दी में सोचते हैं और जब हिन्दी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में सोचते हैं ?

हममें से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कभी इंग्लैंड में भी विदेशियों का राज था और विदेशी भाषा ही वहाँ की राजभाषा थी। वहाँ लगभग 300 वर्षों तक राजभाषा अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच थी, और अंग्रेजी - भाषी लोगों ने अपनी पार्लियामेंट में विदेशी भाषा को अंग्रेजों के प्रति विदेशियों का षड्यंत्र कहा था। यदि विदेशी भाषा फ्रेंच इंग्लैंड की जनता के प्रति षडयंत्र थी तो अंग्रेजी का भारत पर लादा जाना षड्यंत्र क्यों नहीं था ? इसी षड्यंत्र की कहानी हमारे लिए बड़ी रोचक और प्रेरणादायक है। संविधान में निर्धारित था कि इसके लागू होने के 15 वर्ष बाद अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं होगा। 1967 का संविधान संशोधन हमारी वक्रचाल का ही धोतक है। इंग्लैंड दो बार विदेशी राज के अधीन था और दोनो बार विदेशी राजभाषा की घुटन में जीता रहा, पहली बार रोमन साम्राज्य के अधीन (सन 43 से 410 तक) और दूसरी बार नार्मन राज में (सन 1066 के बाद) पहली बार राजभाषा लैटिन थी और दूसरी बार फ्रेंच थी। लैटिन भाषा सन 410 में रोमनों के साथ वापस चली गई और फ्रेंच सन 1362 में ब्रिटेन से भगा दी गई।

दोनों बार विदेशी भाषा के स्थान पर देश की भाषा अंग्रेजी अविकसित अवस्था में ही राजभाषा बनाई गई।

सन् 43 में रोमनों ने ब्रिटेन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। उस समय वहाँ की केल्टिक भाषा को उखाड़कर लैटिन भाषा लागू कर दी क्योंकि राजवर्ग की भाषा लैटिन थी। रोमन सभ्यता उस समय इंग्लैंड की अपेक्षा विकसित हो चुकी थी और उनकी भाषा और साहित्य भी विकसित हो चुके थे। रोमन सभ्यता और जीवन शैली के अनुरूप नगर, छावनी इत्यादि बनाए गए तथा उनको मिलाने के लिए बड़े-बड़े मार्ग भी बनाए गए। रोमन भवन, स्नानागार, मंदिर, नाट्यशालाएँ आदि बनाए गए। रोमन फैशन के कपड़े, आभूषण, बर्तन, सजावट का



इंग्लैंड का मानचित्र



रोमन साम्राज्य का मानचित्र

सामान इत्यादि प्रयोग में आने लगी। इंग्लैंड का रोमकरण वैसे ही हो गया जैसे भारत का अंग्रेजीकरण।

इंग्लैंड वालों को मातृभूमि के प्रति यह भाषा का बदलाव पसंद नहीं था। उन्होंने 18 वर्ष बाद ही फ्रेंच शासन के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बोडिसिया नाम की एक महिला के नेतृत्व में हुआ जिसका पति एक शासक सरदार था और वह रोमन युद्ध में मारा गया था। इस विद्रोह में दोनों ओर से करीब 70000 हजार लोग मारे गए थे। विद्रोह से रोमनों को एक अनुभूति हुई कि यदि किसी देश की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया जाए तो मानो की उसके शरीर पर अधिकार कर लिया, किंतु क्या शरीर मात्र पर अधिकार करने से किसी देश या जाति के मन और आत्मा पर भी अधिकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि देश की धरती पर कब्जा कर लेने से ही ब्रिटेन रोमन हो जाता तो विद्रोह क्यों होता? इसलिए रोमन गवर्नर ने एक शिष्ट-रूप लेकिन कपटपूर्ण तरकीब सोची: क्यों न ब्रिटेन के लोगों को रोमन भाषा के सौष्ठव, रोमन साहित्य के लालित्य तथा रोमन सभ्यता के विलास का आदत लगाकर उन्हें सुखभोग और मानसिक कोमलता का शिकार बनाया जाए? वे स्वयं ही अकर्मण्य बन जाएंगे और अपनी शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि प्रत्येक समस्या के लिए रोमनों पर निर्भर रहने लगेंगे। यह नीति लागू की गई। ब्रिटेन के उच्च वर्ग को रोमन सभ्यता और विलास की आदत लगाई गई। ब्रिटेन का रोमनिकरण हो गया। वे हर बात के लिए रोमनों का मुंह ताकने लगे। कई सौ वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। फिर पाँचवी सदी के प्रारंभ में जर्मनों की ओर से रोम पर आक्रमण होने लगे। रोमन शासक और सेना अपने रोम की रक्षा के लिए वापस चले गए। ब्रिटेन के लोग यह नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोमनों से रुकने की प्रार्थना की। पर रोमन तो रुक नहीं सकते थे, वे अपने देश के लिए चले गए। उनके जाने के पश्चात ब्रिटेन पर पिक्ट्स और स्काट्स ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। भोग विलास के कारण अपने आपसे थके ब्रिटेनवासी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाये और रोम से सुरक्षा की प्रार्थना करने लगे। रोम वालों को अपने राज्य की चिंता थी। ब्रिटेन और उनकी सभ्यता आक्रमणकारियों से हार गए। कुछ समय बाद जर्मन ज्यूट, एंग्ल और सैक्सन लोग इंग्लैंड पहुँच गए और ब्रिटेन फिर से गुलाम हो गया। एंग्लो के निवास स्थान होने के कारण ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ गया। रोमन प्रभाव भी समाप्त हो गया : आक्रमणकारियों ने रोमन सभ्यताग्रस्त ब्रिटेनवासियों को पछाड़ दिया।

ब्रिटिश भारत में लार्ड मैकाले के शिक्षा प्रस्ताव और अँग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के 18 वर्ष बाद सन् 1853 में मैकाले के रिस्तेदार और धर्म प्रचारक चार्ल्स ट्रेवेल्यण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेष समिति के सामने अपनी राय प्रकट करते समय ब्रिटेन के रोमनकरण की चर्चा की थी और यह कहा था कि जैसे रोमनों ने ब्रिटेन के लोगों को रोमन भाषा, साहित्य और सभ्यता की आदत लगाया था वैसे ही कंपनी सरकार को भी भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य एवं विलास का अनुभव करा देना चाहिए। जब रोमन जाने लगे तो, ब्रिटिशों ने उनको रोकना चाहा था। इसी प्रकार यदि अंग्रेजों को कभी भारत से जाना भी पड़ेगा तो अंग्रेजी रंग में रंगे भारतीय स्वयं उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। भाषा और साहित्य के माध्यम से मन और संस्कारों पर विजय पाई जाती है और मन और संस्कारों के माध्यम से आत्मा पर प्रभाव कायम किया जाता है। यह योजना ब्रिटिश इतिहास के रोमन अध्याय के आधार पर बनाई गई थी।

ब्रिटेन की दूसरी पराजय सन् 1066 में नारमंडी राज्य के राजा विलियम ने ब्रिटेन के शाह हैरल्ड को हेस्टिंग्ज नामक पहाड़ी स्थान पर युद्ध में हराकर ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। नार्मन राज्य की स्थापना के साथ ही उनकी भाषा फ्रेंच ब्रिटेन की राजभाषा बन गई। करीब तीन सौ वर्ष तक सन 1066 से 1362 तक इंग्लैंड की राजभाषा फ्रेंच थी।

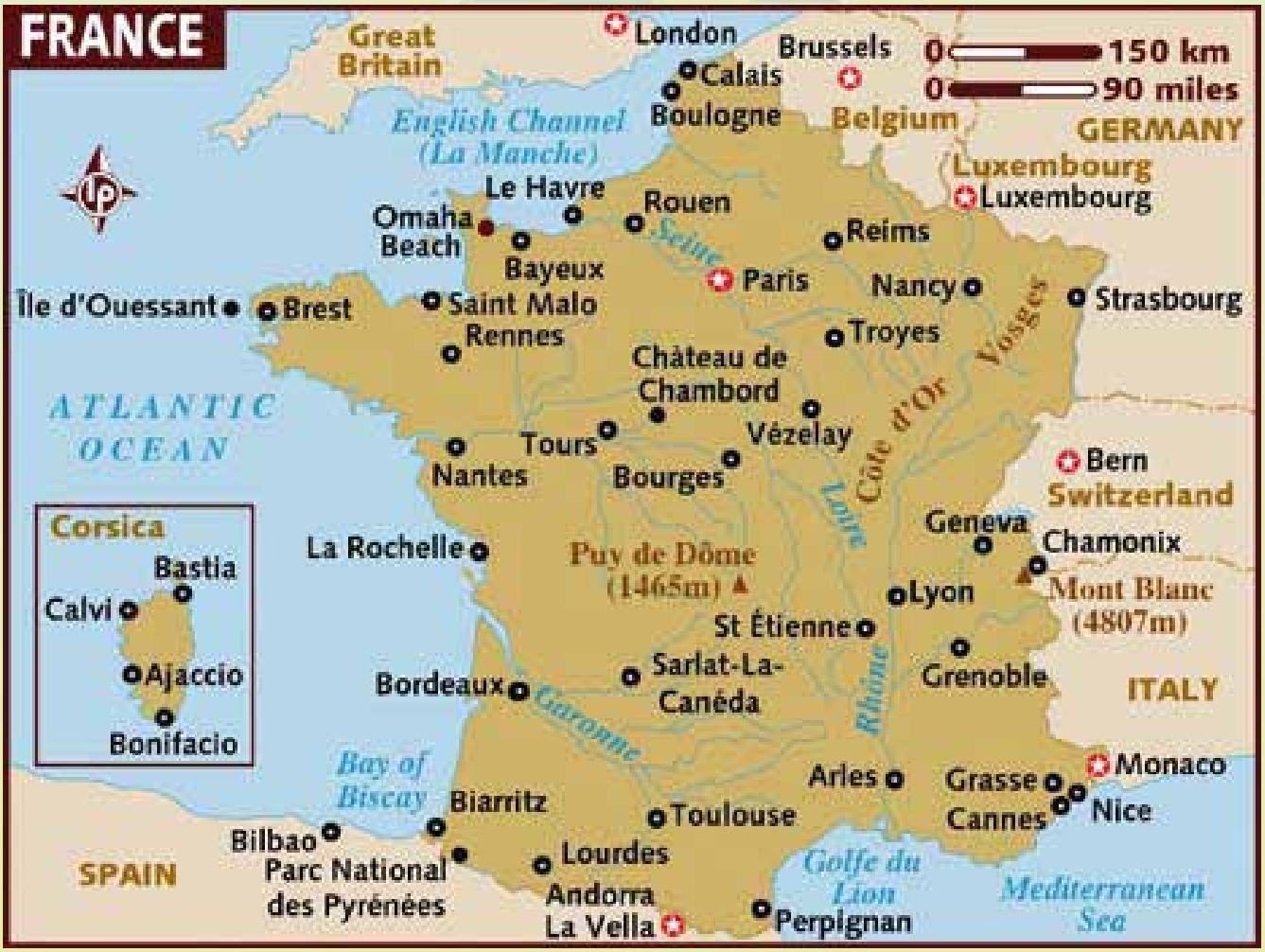
जिस प्रकार अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद भारत के शासन-प्रशासन का अंग्रेजीकरण हो गया था, इसी प्रकार इंग्लैंड के शासन-प्रशासन का भी फ्रांसीसीकरण हो गया। अंग्रेज शासक लड़ाई में मारे गए थे, और उनके स्थान पर नार्मन अधिकारियों को तैनात किया गया था। छठी शताब्दी के पश्चात इंग्लैंड में ईसाई मत का प्रचार हुआ और वहाँ रोम के अधीन चर्च की स्थापना की गई थी। नार्मन काल में चर्च के सभी अधिकारी नार्मन ही थे। ये सभी नार्मन केवल फ्रेंच भाषा ही जानते थे। वे अँग्रेजी नहीं जानते थे और न ही उन्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता थी। उन्होंने इंग्लैंड में ही एक विशिष्ट फ्रांस बना लिया था। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच फैशन, फ्रेंच शिष्टाचार, फ्रेंच सभ्यता, का ही बोलबाला था। इंग्लैंड में रहने वाले इन शासकों के सामने इंग्लैंड के निवासी खानसामा, बैरा और फराश बन गए। शासक वर्ग अंग्रेज कुलियों को जानबूझकर दूर रखते और इनते प्रति घृणास्पद बर्ताव करते थे। अधिकारियों की नजर में ये नौकर अल्हड़-गवार ही थे।

नार्मन और अंग्रेजों के बीच रंगभेद नहीं था। इसलिए उच्चवर्गीय अंग्रेजों, और नार्मनों के बीच रिश्ते-नाते भी होने लगे थे। वहाँ के उच्च वर्गीय अंग्रेज धीरे-धीरे शासक वर्ग के निकट आने लगे। फलस्वरूप उच्च वर्गीय शासकों की निकटता से फ्रेंच भाषा भी सीखने लगे और

नए सामाजिक आचार-व्यवहार के माध्यम से एक नया संभ्रांत वर्ग अस्तित्व में आने लगा। ऐसे ही भारत में भी हुआ था, अंतर यह था कि यहाँ रंगभेद था और वहाँ नहीं था। पर भाषा की विशिष्टता दोनों जगह एक-सी थी। भाषा शासन-प्रशासन और समाज संबंधी वर्ग-विशेष का एक प्रतीक बन गई। संभ्रांत वर्ग के लोग फ्रेंच बोलते और आम जनता अँग्रेजी बोलती थी। फ्रेंच शासक की भाषा थी अंग्रेजी गँवारों की भाषा बन गई। उसी प्रकार भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी शासक की भाषा बनी जबकि भारतीय भाषाएं गवारों की बन गई।

जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत से आर्थिक लूट किया था। ठीक उसी तरह इंग्लैंड से भी धन लूट कर नार्मडी भेजा जाने लगा और अनेकों नार्मनों को ऊंचे-ऊंचे सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया जैसे भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ था। नार्मनों ने इंग्लैंड को वैसे ही एक उपनिवेश समझ लिया था जैसे अंग्रेजों ने भारत को समझ रखा था।

फ्रेंच भाषा और साहित्य की शान सारे इंग्लैंड में छा गई। यदि अंग्रेज अच्छे पदों पर नियुक्त होते थे तो उन्हे अपमान सहना पड़ता था। भारत में स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी अंग्रेजी न जानने वालों का उपहास किया जाता है। अलबर्ट बाँ महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **'अँग्रेजी भाषा का इतिहास'** में इस पर विस्तार से लिखा है। एक तत्कालीन इतिहासकार रॉबर्ट हल्काफ के हवाले से वे लिखते हैं कि उस समय अंग्रेज नाम भी एक प्रकार की गाली बन गया था। यह स्मरणीय है कि अँग्रेजी राज में भारत में भी हिन्दुस्तानी, काला, कुली इत्यादि शब्द पर्याय बन गए थे। आज भी इंग्लैंड में भारतीय दिखने वाले आदमी को पाकी, निगर आदि कह दिया जाता है। यह भी स्मरणीय है कि प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी गोरों को बंदर, कोढ़ी, लालमुँहा इत्यादि कहा जाता था। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी भी समाज-समुदाय में हर समय हुआ करता है जब दो समाज आपस में अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा जातीय कारणों से मानसिक विकार का



फ्रांस का नक्शा

शिकार बन जाते हैं। हल्काफ का कहना है कि नार्मन शासक वर्ग ने हर संभव कोशिश किया कि अंग्रेजी भाषा को किसी तरह समाप्त कर दिया जाए ताकि अंग्रेजी-फ्रेंच का विवाद ही खत्म हो जाए और सारे लोग फ्रेंच ही बोलने लगें। ब्रिटिश शासन के दौरा भारतीय भाषाओं का भी बूरा हाल हुआ।

अंग्रेजी-विरोधी और फ्रेंच समर्थक राजनीति करीब 150 वर्ष तक खूब चली। इंग्लैंड के संपन्न परिवार फ्रेंच सीखने लगे और अपने बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने के लिए फ्रेंच ट्यूटर रखने लगे।

भारत में भी कुछ समय तक ऐसा हुआ था। कहा जाता है कि बचपन में नेहरू जी को पढ़ाने के लिए अंग्रेज ट्यूटर रखे गए थे। इंग्लैंड में फ्रेंचपरस्ती के साथ-साथ अँग्रेजी बेबसी से डेढ़ सौ वर्षों तक चलती रही, कुछ समय पश्चात देश की आम जनता ने अंग्रेजी के पक्ष में फ्रेंच भाषा का विरोध किया और चुनौती दे डाली।

सन् 1200 से 1250 तक का समय ब्रिटिश भाषा इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ था। डेढ़-दो सौ वर्ष के बाद भी फ्रेंच जनभाषा नही बन पाई थी। वर्ग भाषा अवश्य बन गई थी। जो लोग पढ़ते-लिखते और बोलते थे उनके उच्चारण और लेखशैली से साफ पता चलता था कि ये लोग सोचते अंग्रेजी में हैं और लिखते-बोलते फ्रेंच में हैं। वे वैसी ही छोटी-छोटी स्पेलिंग, ग्रामर तथा एक्सेनट (स्वर का उदात या अनुदात रूप) की गलतियां करते थे जैसी साधारण अंग्रेजी लिखने वाले हिंदुस्तानी करते हैं।

अंग्रेजी-फ्रेंच के अवमान और अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों के राजनीतिक पुनरूत्थान के कारण-
1) अंग्रेज और नार्मन जातियों का संगठन
2) नार्मनों का इंगलैंड में स्थायी निवास
3) अंग्रेजी भाषा की राजोचित प्रतिष्ठा

ये तीनों कारण भारत में नहीं घट सकते थे। अंग्रेज और नार्मनों में रंगभेद नहीं था जीवन के प्रति आधारभूत और वास्तविक दृष्टिकोण में भी कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों में कोई धार्मिक या सांप्रदायिक अंतर भी नहीं था क्योंकि दोनों जातियाँ / ईसाई वर्ग से थी। दोनों जातियों में आपस में विवाह होने लगे थे। भारत में ऐसा नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था। अंग्रेज यहाँ बसने के लिए नहीं आए थे। सन् 1200 के आसपास अंग्रेज और नार्मन इकट्ठे रहते रहते ऐसे मिल गए थे कि यह पता नहीं चल पाता था कि कौन अंग्रेज है और कौन नार्मन।

सन् 1204 में नार्मडी पर फ्रांस के शासक ने कब्जा कर लिया और नार्मन वंशी इंगलैंड के राजा ने उसकी नार्मडी स्थित सारी संपति, जमीन-जायदाद जब्त कर लिया। उस समय जो नार्मन इंग्लैंड में रहते थे वे दोनों जगह नार्मन और इंगलैंड में आ जा सकते थे। सन् 1244 में फ्रांस के शासक ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि इंग्लैंड निवासी नार्मडियों को नार्मडी और इंग्लैंड में से किसी एक को चुनना होगा, वे दोनों देशों के नागरिक नहीं रह पाएंगे। जिन नार्मनों ने इंग्लैंड में विवाह किया था और जिनका घर - जायदाद आदि बन गए थे वे इंग्लैंड में ही रहे और नार्मडी को छोड़ दिया। इंग्लैंड में स्थायी तौर पर बसने के कारण वे वैधानिक और वास्तविक रूप से अँग्रेजी जनसमुदाय के सदस्य बन गए।

देशवासी एक हो गए तो भाषा विदेशी क्यों? यह एक यक्ष प्रश्न बन गया था। देश-प्रेम और भाषा-भक्ति ने जोर मारना प्रारंभ किया। सन् 1234 में चर्च के उच्चाधिकारी राजा से मिले और उनके फ्रेंच-भाषी सामंतों के विरूद्ध और राज्य के हित में अपना विरोध प्रकट किया। ये दो सामंत थे : विंचेस्टर के बिशप पीटर और दूसरे, पीटर द रिवो। चर्च के अधिकारियों ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि ये दोनों सामंत अपने आपको सारी राजशक्ति का मालिक समझते हैं और सारे अंग्रेज अधिकारियों को राजकार्य से निकाल चुके हैं। ऐसा क्यों? क्या इंग्लैंड के लोग राजा के विश्वासपात्र नहीं हैं? क्या राज्य और राजा पर देश के लोगों का कोई अधिकार नहीं है या उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? ये लोग राजा और देश के निवासियों के बीच एक ऐसी खाई खोदेंगे जो दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।

उन्होंने राजा से प्रार्थना किया कि इन सामंतों के इशारों पर न चलें। एक और चर्च अधिकारी बिशप ग्रासटेस्ट ने सन 1252 में कठोर शब्दों में राजा को चेतावनी दी कि ये विदेशी केवल विदेशी ही नहीं हैं, वे इंग्लैंड के घोर शत्रु भी हैं। ये देश को लूट रहे हैं। वे न तो इस देश के निवासियों को पहचानते हैं और न ही इस देश की भाषा को समझते हैं।

उस समय ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा असभ्यता की प्रतीक थी। अब फ्रेंच विदेशियों के गले का हार नहीं बल्कि काँटा बनने लगी। **राबर्ट ऑफ ग्लौस्टर ने सन 1300 में सामयिक विषयों की चर्चा करते हुए कहा: ''इंग्लैंड को छोड़कर, सारे संसार में ऐसा कोई देश नहीं जिसकी अपनी भाषा न हो।''** 'कर्सर मुँडाई' नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि क्या फ्रांस में अंग्रेजी बोली या समझी जाती

है? फिर इंग्लैंड में फ्रेंच क्यों? यदि मैं अपने देश की भाषा में लिखता हूँ तो कौन-सा गुनाह करता हूँ? मैं सबके लिए लिखता हूँ और वे सब मेरी भाषा को समझते हैं...।'' एक और अंग्रेजी लेखक ने लिखा कि ''...इंग्लैंड में जन्मे और यहीं रहने वाले अंग्रेजी समझते हैं। वे न फ्रेंच समझते हैं न लैटिन। लिखना या बोलना केवल अंग्रेजी में ही हो सकता है और होना चाहिए...।'' विलियम ऑफ नेसिंग्टन ने सन 1325 में 'मिरर लाइफ" नाम पुस्तक में लिखा है मैं न लैटिन लिखूंगा न कोई और भाषा, केवल अंग्रेजी लिखूंगा। हम इंग्लैंड में जन्मे हैं, यहीं पले हैं, यही रहते हैं, तो फ्रेंच या लैटिन क्यों? पढ़े-लिखे, छोटे-बड़े, सब अंग्रेजी समझते हैं...।""

सामाजिक चेतना जागृत होने के बाद अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ने लगा। सन् 1327 में शाह एडवर्ड द्वितीय की ओर से लंदन शहर को कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए। मेयर, महानगरपालिका सदस्य और नागरिकों के सामने नगर-भवन में एक प्रमाणपत्र पढ़कर सुनाया गया। प्रमाणपत्र अंग्रेजी में था। सन् 1337 में शाह एडवर्ड तृतीय ने संसद का एक अधिवेशन फ्रांस के राज्याधिकार के विषय में सलाह प्राप्त करने के लिए बुलाया। संसद का संबोधन राजा की ओर से एक वकील ने किया। वकील महोदय लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी तीनों भाषाएँ जानते थे, फिर भी उन्होंने अपना वक्तव्य अंग्रेजी में दिया ताकि सब लोग इसे भली भाँति समझ सकें।

सन् 1356 में लंदन के मेयर की ओर से यह आदेश दे दिया गया कि लंदन और मिडल सेक्स के न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में संपन्न की जाएगी।

ब्रिटेन की जनता के प्रति विदेशी राजभाषा के रूप में फ्रेंच भाषा का षड्यंत्र रचा गया था और उसके माध्यम से अंग्रेजों के साथ अन्याय तीन सौ वर्ष ब्रिटीश से किया जा रहा था। उसका वैधानिक निराकरण सन 1362 में हुआ। संसद ने अक्टूबर में एक प्रस्ताव पास किया जिसका शीर्षक था 'स्टेच्युट ऑफ प्लीडिंग"। प्रस्ताव इस प्रकार है :-

सरकार के सामने बार-बार चर्च-अधिकारियों, सामंतों, राज्याधिकारियों और जन-साधारण के द्वारा प्रमाण-सहित निवेदन किया गया है कि इस देश के साथ एक षडयंत्र रचा गया है। क्योंकि देश के कायदे-कानून जनसाधारण को मालूम नहीं है, क्योकि उनके आवेदन, प्रतिवेदन, जांच, निर्णयादी फ्रेंच भाषा में किए जाते हैं और जनता इसे समझती नहीं है। और जो लोग शाही या दूसरी अदालतों में आवेदन, प्रतिवेदन करते हैं, उन्हें विदेशी भाषा के कारण यह पता नहीं चलता कि सरकारी अफसर या वकील उनके पक्ष या विपक्ष में क्या कह रहे हैं। यह सही होगा कि देश के कायदे-कानून को देश की प्रचलित भाषा में सुचारू रूप से समझा जा सकता है, और प्रत्येक नागरिक नियमों का अतिक्रमण किये बिना अपनी स्वतंत्रता, और संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं एवं जिन-जिन अन्य देश-प्रदेशों में राजा या सामंत या राज्याधिकारी गए हैं वहाँ प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकार और सुव्यवस्था उपलब्ध होगी, अत: अपनी प्रजा की सुव्यवस्था और सुख-शांति के लिए और उपरोक्त कारण से जो क्षति और अन्याय उनके साथ होते रहे हैं या हो सकते हैं उनके निराकरण के लिए राज्य के द्वारा यह आज्ञा, अनुज्ञा और आदेश दिया जाता है कि देश की किसी भी अदालत में किसी भी जज के सामने, किसी और (म्युनिसिपल) अदालत में किसी मिनिस्टर या अधिकारी के सामने, कहीं भी, जो मुकदमे पेश किए जाते हैं उन सबका आवेदन, प्रमाण, उत्तर-प्रत्युत्तर, परीक्षण और निर्णय अंग्रेजी भाषा में किया जाए और उनका रिकार्ड लैटिन में रखा जाए।

यह प्रस्ताव फ्रेंच भाषा में ही पास किया गया था क्योंकि उस समय फ्रेंच ही राजभाषा थी। इसका रिकार्ड लैटिन में रखा गया क्योंकि लैटिन परीक्षित, सम्माननीय और पवित्र भाषा मानी जाती थी। भारत से तुलना करें तो लैटिन संस्कृत के समान धर्म और धर्मशास्त्र की भाषा थी। हम यह कह सकते हैं कि देशी भाषा का यह वैधानिक सम्मान ब्रिटेन की संसद के मतानुसार वहाँ के धर्मशास्त्र का अंग बन गया।

मध्यकालीन देशों और राज्यों की भाषा-स्थिति यह रही है की पहले मातृभाषा, दूसरी, सरकार की भाषा और तीसरी चर्च की भाषा, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशोंमें लैटिन उनके घर की भाषा मातृभाषा-जैसे भारत में हिन्दी, अथवा और कोई भी भारतीय भाषा, सरकारी भाषा मातृभाषा- जैसे भारत में हिन्दी, अथवा और कोई भी भारतीय भाषा, सरकारी भाषा अँग्रेजी और धार्मिक भाषा संस्कृत इत्यादि थी। जैसे-जैसे मानव परिवार आधुनिकता की ओर चला, ये तीनों भाषथाएँ भी साथ चलीं। जिस देश या समाज में ये तीनों भाषाएँ एक रही वह देश आधुनिक समाज है। जिन देशों में स्वदेशी के अलावा विदेशी भाषा है वह देश पिछड़े समाज में गीना जाता है।

ब्रिटेन सन् 1362 में आधुनिकता की ओर बढ़ा क्योंकि देशी भाषा सरकारी भाषा बन गई। क्या अँग्रेजी उस समय विकसित भाषा थी? क्या राजभाषा बनने के लिए अँग्रेजी ने कोई तैयारी की थी? इन प्रश्नों का उत्तर तो अगले चार सौ सालों के इतिहास में प्राप्त होगा।



जाहिद माझगांवकर
डीओएस - टेकक

अमर शहीद भगत सिंह

23 मार्च 2017 को शहीद भगत सिंह की 110 वीं जयंती भारत तथा पाकिस्तान में मनाई गई हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को, गाँव बावली, जिला लायलपुर पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था।



यह सिख परिवार था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी काण्ड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रान्तिकारियों को फाँसी और अन्य 16 को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पण्डित चन्द्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े गए और उसे एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेजी अधिकारी जे.पी. सांडर्स को गोली मार दिया था। इस कार्रवाई में क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की। क्रान्तिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रे. ज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद दोनों ने गिरफ्तारी भी दी थी।





शहीद भगत सिंह का पुस्तैनी मकान (पाकिस्तान)

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के समय भगत सिंह 12 वर्ष के थे घटना की सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियाँवाला बाग पहुँच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रान्तिकारी किताबें पढ़ कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं ? गांधी जी का असहयोग आन्दोलन छेड़ने के बाद वे गांधीजी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रान्तिकारियों के हिंसक आन्दोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधीजी के असहयोग आन्दोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, किन्तु समूचे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। उन्होंने गांधीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन की जगह देश की स्वतन्त्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारम्भ किया तथा कई क्रान्तिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रान्तिकारियों में चन्द्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु आदि थे।

सॉण्डर्स की हत्या के बाद एचएसआरए द्वारा लगाए गए परचे। सन 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया गया था जिससे आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गयी। लाला जी का बदला लेने की क्रान्तिकारियों ने योजना बनाई। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट स्काट को मारने

POSTER-AFTER SAUNDERS' MURDER

"Notice"

By Hindustan Socialist Republic Army.

'Bureaucracy Beware'

With the death of J.P. Saunders the assassinaiton of Lala Lajpat Rai has been avenged.

It is a matter of great regret that a respected leader of 30 crores of people was attacked by an ordinary police officer like J.P. Saunders and met with his death at his mean hands. This national insul was a challenge to young men.

Today the world has seen that the people of India are not lifeless; their blood has not become cold. They can lay down their lives for the country's honour. The proof of this has been given by hte youth who are ridiculed and insulted by the leaders of their own country.

'Tyrant Government Beware'

Do not hurt the feelings of the oppressed suffering people of this country. Stop your devilish ways. Despite all your laws preventing us from keeping arms and despite all your watchfulness, people of this country would conitnue to get pistols and revolvers. Even if these arms are not adequae in numbers for an armed revolution, they would be sufficient for avenging the insult to the country's honour. Even if our own people condemn us and ridicule us and if foreign government subjects us to any amount of repression, we shall all be ever ready to teach a lesson to foreign tyrants who insult our national honour. Despite all opposition and repression, we shall carry forward the call for revolution and even we go to the scaffold for being hanged, we shall continue to shout:

"Long Live Revolution!"

We are sorry to have killed a man. But this man was a part of cruel, despicable and unjust system and killing him was a necessity. This man has been killed as an employ of the British Government. This Government is the most oppressive government in the world.

"We are sorry for shedding human blood but it becomes necessary to bathe he alter of Revolution with blood. Our aim is to bring about a revolution which would end all exploitation of man by man.

"Long live Revolution!"

Sd/- Balraj
Commander-in-Chief, HSRA

18th December, 1928.



दाहिने से चौथे खड़े भगत सिंह अपने स्कूल में अन्य साथियों के साथ

की योजना सोची। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठे गए जैसे कि वह खराब हो गयी हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चन्द्रशेखर आज़ाद के डी.ए.वी. स्कूल की चाहर दावारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे।

17 दिसंबर 1928 को करीब सवा चार बजे, ए.एस.पी सॉण्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सिर में मारी जिसके बाद वह होश खो बैठे। तत्पश्चात भगत सिंग ने सन 3-4 गोली दाग कर उनके मरने का पूरा इन्तज़ाम कर दिया। जब दोनों भाग रहे थे एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चन्द्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया - "आगे बढ़े तो गोली मार दूँगा।" नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया।

भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे परन्तु वे वामपंथी (कम्युनिष्ट) विचारधारा के समर्थक थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से पूरी तरह प्रभावित थे। साथ ही, वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। इसके कारण उन्हें पूँजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसन्द नहीं थी। उस समय अँग्रेज ही सर्वेसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अत: अँग्रेजों का मज़दूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मज़दूर विरोधी ऐसी नीतियों का ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना हेतु उनके दल का समर्थन था। सभी चाहते थे कि अँग्रेजों को पता होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। जागरुकता के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केन्द्रीय एसेम्बली में बम फेंकने की योजना बनायी थी।

भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अँग्रेजों तक उनकी 'आवाज़' भी पहुँचे। हालाँकि प्रारम्भ में उनके दल के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे पर अन्त में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केन्द्रीय असेम्बली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहाँ कोई मौजूद नहीं था। पूरा हाल धुएँ से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे पर उन्होंने पहले ही योजना बनाई थी कि उन्हें दण्ड स्वीकार है चाहें वह फाँसी ही क्यों न हो; अत: उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज़ तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने "इन्कलाब-जिन्दाबाद, साम्राज्यवाद-मुर्दाबाद!" का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। कुछ देर बाद ही पुलिस आ गयी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

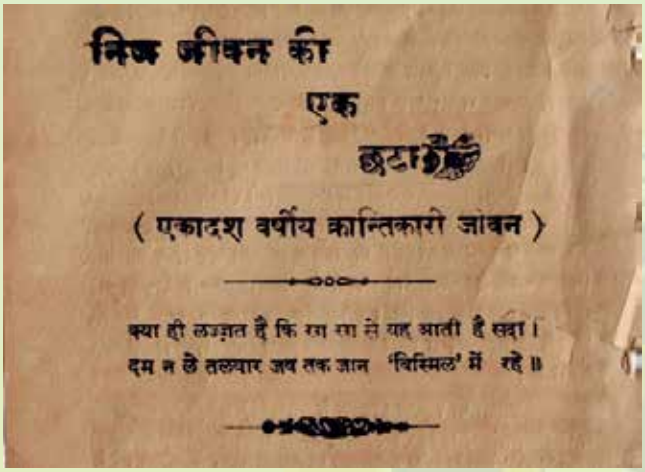
जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन



वर्ष 1927 में पहली बार गिरफ्तारी के बाद जेल में खींची गई भगत सिंह की फोटो

निरंतर जारी रहा। उस दौरान लिखे गए लेख व सगे सम्बन्धियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूँजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने जेल में अँग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ? जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हडताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे।

सिन्ध से प्रकाशित बिस्मिल की आत्मकथा का प्रथम पृष्ठ। यही पुस्तक भगत सिंह को लाहौर जेल में भेजी गयी थी।



26 अगस्त, 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 एफ तथा आईपीसी धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्तूबर, 1930 को अदालत ने 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई परन्तु यह अपील 10 जनवरी, 1931 को रद्द कर दी गई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पं. मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी, 1931 को अपील दायर किया कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी, 1931 को वायसराय से बात किया फिर 18 फरवरी, 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्को के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की गई थी। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था क्यों कि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। जेल का नाई बरकत प्रत्येक कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी दी जाएगी। कैदियों ने बरकत से मनुहार किया कि वह फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दें ताकि वो अपने पोते-पोतियां को बता सकें कि कभी वह भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे।

नाई बरकत, भगत सिंह की कोठरी में आया और वहाँ से उनका पेन कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रॉ निकाला गया।

भगत सिंह को किताबे पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वह उनके लिए कार्ल लीबनेख़ की 'मिलिट्रिज़म', लेनिन की 'लेफ्टविंग कम्युनिज़म' और अपटन सिनक्लेयर का उपन्यास 'द स्पाई' कुलबीर के ज़रिए भिजवा दें।

भगत सिंह जेल की कठिन ज़िंदगी के आदी हो चले थे, उनकी कोठरी नंबर 14 का फ़र्श पक्का नहीं था। उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका पाँच फिट, दस इंच का शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए।

भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ मेहता से कहा कि वह पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस का मेरा धन्यवाद पहुँचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुँचे।

मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रान्तिकारियों को बता दिया कि उनकी तय वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह छह बजे की बजाय आज शाम सात बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।

किसी ने भगत सिंह से कहा कि अंतिम समय में ईश्वर का याद कर लो। भगत सिंह बोले, "पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के दुखों के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है।"

भगत सिंह बीच में खड़े थे। भगत सिंह में अपनी माँ को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वह फाँसी के तख्ते से 'इन्कलाब ज़िंदाबाद' का नारा लगाएंगे।

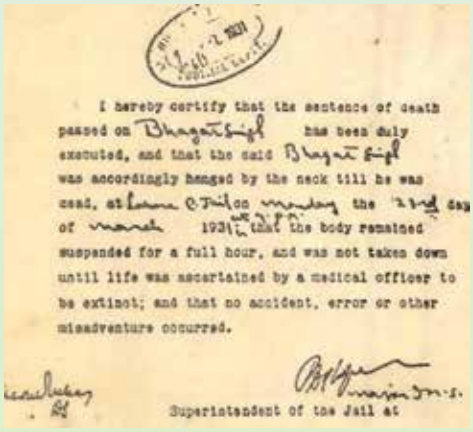
23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7 बजकर 33 मिनट पर भगत

सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फाँसी दे दी गई। फाँसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फाँसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था - "ठहरिये ! पहले एक क्रान्तिकारी दूसरे से मिल तो ले।" फिर एक मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले "ठीक है अब चलो।"

फाँसी पर जाते समय वे तीन मस्ती से गा रहे थे -
मेरा रँग दे बसन्ती चोला, मेरा रँग दे;
मेरा रँग दे बसन्ती चोला। माय रँग दे बसन्ती चोला।

भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र

फाँसी के बाद कहीं कोई आन्दोलन न भड़क जाए इसके डर से अँग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर को ओर ले गए जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गाँव के लोगों ने जब आग जलती देखी तो नजदीक गए। जिससे डरकर अँग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकडों को सतलज नदी में फेंककर भाग गए। गाँव वालों ने पास जाकर देखा और इनके मृत शरीर के टुकडों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इस घटना के बाद लोग अँग्रेजों के साथ-साथ गांधीजी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। गांधीजी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झण्डों से गांधीजी का स्वागत किया। एकाध जगह पर गांधीजी पर हमला भी हुआ, किन्तु सादी वर्दी में उनके साथ



I hereby certify that the sentence of death passed on Bhagat Singh has been duly executed, and that the said Bhagat Singh was accordingly hanged by the neck till he was dead, at Lahore Jail on Monday the 24th day of March 1931, that the body remained suspended for a full hour, and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extinct; and that no accident, error or other misadventure occurred.

Superintendent of the Jail at

भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र



The Tribune.

BHAGAT SINGH, RAJGURU AND SUKHDEV EXECUTED.

AN "LAST INTERVIEW" WITH RELATIONS.

Shouts Emerge From Jail.

सुखदेव, राजगुरु तथा भगत सिंह को फाँसी दिए जाने की खबर - लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्युन का मुख्य पृष्ठ

चल रहे पुलिसवलों ने उन्हें बचा लिया।

जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अन्दाज लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि (पंजाब की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिन्दी और अरबी एवं उर्दु के सन्दर्भ में विशेष रूप से,) जाति और धर्म के कारण आयी दूरियों पर दु:ख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अँग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार पर सोचते थे।

भगत सिंह को हिन्दी, उर्दु, पंजाबी तथा अँग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी इसे उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिन्दा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफ़िनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पं. राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो-जो दिशा-निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश: पालन किया। उन्होंने अँग्रेज सरकार का एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अँग्रेजी सरकार के खिलाफ़ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबन्दी समझा जाए तथा फाँसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फाँसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था -

उन्हें यह फ़िक्र है हरदम, नयी तर्ज़-ए-जफ़ा क्या है ?
हमें यह शौक है देखें, सितम की इन्तहा क्या है ?

दहर से क्यों खफ़ा रहें, चर्ख का क्या गिला करें।
सारा जहाँ अदू सही, आओ ! मुक़ाबला करें।

इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चन्द्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खायी थी कि उनकी जिन्दगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखायी।

डिजिटल इंडिया



राजेश हिंदूराव आंबवड
प्रबंधक (भण्डार पूर्वखंड)

डिजिटल इंडिया के रूप में, एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आरम्भ दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 01 जुलाई दिन बुधवार 2015 को हुआ था। इसकी शुरूआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों (टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, आरआईएल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, विप्रो अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी आदि) की मौजूदगी में हुई।

इस देश को डिजिटल रुप से सशक्त देश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य कागजी कार्यवाही को घटाने और भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की सेवा उपलब्ध कराना है। ये बहुत ही प्रभावशाली और कार्यसुलभ है जो बड़े स्तर पर समय और मानव श्रम की बचत करेगा। किसी भी जरुरी सूचना तक पहुँच के लिए तेज गति इंटरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने के लिए 01 जुलाई 2015 को इस पहल की शुरुआत की गयी थी। पूरे देश में डिजिटल संरचना का निर्माण, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना जैसे डिजिटल इंडिया के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सेवा प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को फायदा पहुँचायेगा। इस कार्यक्रम की निगरानी और नियंत्रण करने के लिये डिजिटल इंडिया सलाहकर समूह (संचार एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा संचालन) की व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट को (एक लाख करोड़ रुपये) अनुमोदित किया गया है और 2019 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की सफलता ई-गर्वनेंस के साथ भारतीय लोगों की सेवा करने के नरेन्द्र मोदी के सपने के सच होने जैसा होगा। कागज़ी कार्यवाही को घटाने, कार्य कुशलता में सुधार और समय की बचत के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकार की सेवा के साथ ये भारतीय नागरिकों को सहज करने के लिए है।

9डिजिटल इंडिया" भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके अंतर्गत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, वह है **भारतीय प्रतिभा (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) = कल का भारत (आईटी)।**

यह योजना वास्तव में तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर-दराज के गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से खास तौर पर भारत के ग्रामीण इलोकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करेगी। खुद प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं।

इस परियोजना के लोकार्पण से आरंभ में ही लगभग 250,000 गाँवों और देश के अन्य आवासीय इलाकों में तेज गति के इंटरनेट कनेक्शन को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक योजना बनायी गयी थी। इस प्रोजेक्ट में "भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड" द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गयी है जो सराहनीय है।

डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाईजेशन आसानी से होगा जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा दक्ष बनाने में मदद करेगा। ये कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी बचत करेगा। सरकार और

निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए बड़ी संख्या के गाँव वास्तव में पिछड़े क्षेत्रों से पूर्ण रुप से डिजिटली लैस इलाकों के रुप में एक बड़े बदलाव से गुजरेगा। भारत में सभी शहर, नगर और गाँव तकनीकी होंगे। मुख्य कंपनियों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) के निवेश के साथ 2019 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना है। अंबानी ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में लगभग 2.5 लाख करोड़ निवेश के लिए घोषणा किया है।

इस कार्यक्रम के तीन मुख्य दृष्टिगत क्षेत्र है:

- भारतीय लोगों के लिए एक जनोपयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना हो क्योंकि यह तेज गति की इंटरनेट पहुँच कराएगा जिससे सभी सरकारी सेवा तक आसान और तेज पहुँच हो जाएगी। यह नागरिकों को जीवनपर्यन्त, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामाणिक रुप से डिजिटल पहचान उपलब्ध कराएगा। यह किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे बैंक खाता संभालना, वित्त प्रबंधन, सुरक्षित और सुनिश्चित साईबर स्पेस, शिक्षा आदि के लिए बेहद कारगर साबित होगा।
- सुशासन की अत्यधिक माँग और ऑनलाईन सेवा डिजिटाईजेशन के द्वारा वास्तविक समय में सभी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। डिजिटल रुप से बदली हुई सेवा भी वित्तिय लेन-देन को आसान, इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद के बनाने से ऑनलाईन व्यापार करने के लिए लोगों को बढ़ावा देगी।
- भारतीय लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुँच के द्वारा डिजिटल साक्षरता को वास्तव में मुमकिन बनाएगी। ऑनलाईन प्रमाणपत्र या जरुरी दस्तावेज़ों को जमा करने के लिए यह लोगों को सक्षम बनाएगी ना कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक प्रस्तुति की आवश्यकता होगी।

इस पहल के निम्न लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया गया है।

- ब्रॉडबैंड हाइवे सुनिश्चत करना।
- मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक ऐक्सेस सुनिश्चित करना।
- जनता इन्टरनेट ऐक्सेस कार्यक्रम को सुगम बनाना।
- ई-गवर्नेन्स - तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार लाना।
- ई-क्रान्ति - सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रुप से प्रदान करना।
- सभी के लिए ऑनलाईन सूचना उपलब्ध कराना।
- ज्यादा आईटी नौकरियों को सुनिश्चित करना।
- जल्दी पैदावार कार्यक्रम।

डिजिटल इंडिया अभियान के निम्न लाभ:

- डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करना यह मुमकिन बनाएगा जिसके परिणाम स्वरुप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई-शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज़ को कम करने से कागजी कार्यवाही को घटाएगा।
- यह एक प्रभावशाली ऑनलाईन मंच है जो चर्चा, कार्य करना, और वितरण जैसे विभिन्न दृष्टिकोन के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को शामिल कर सकता है।
- सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाईन लक्ष्यों की प्राप्ति को यह सुनिश्चित करेगा।
- कहीं से भी अपने दस्तावेज और प्रमाणपत्र को ऑनलाईन जमा करना लोगों के लिए यह संभव बनाएगा जिससे शारीरिक कार्य कम होगा।
- ई-हस्ताक्षर संरचना के द्वारा नागरिक अपने दस्तावेजों को ऑ नलाईन हस्ताक्षरित करा सकता है।
- ई-अस्पताल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक सेवाओं को आसान बना सकता है जैसे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर से मिलने का वक्त लेना, फीस जमा करना, ऑनलाईन लक्षणिक जाँच करना, खून जाँच आदि।
- अर्जियों के जमा करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण के स्वीकृत के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के लिए यह लाभ उपलब्ध कराता है।
- यह एक बड़ा मंच है जो अपने नागरिकों के लिए देशभर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है।
- भारत नेट कार्यक्रम (तेज गति का डिजिटल हाइवे) देश के लगभग 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा।
- डिजिटल इंडिया पहल में मदद के लिए बाहरी स्त्रोत नीति की भी एक योजना है। मोबाईल पर ऑनलाईन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जैसे वॉइस, डाटा, मल्टीमीडिया आदि, बीएसएनएल के अगली पीढ़ी का नेटवर्क 30 साल पुराने टेलिफोन एक्सचेंज को बदल देगा।
- पूरे देश में बीएसएनएल के द्वारा बड़े पैमाने पर वाई-फाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना बनाई गई है।
- कनेक्टिवीटी से जुड़े सभी संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए ब्रॉ डबैंड हाइवे है।
- सभी शहरों, नगरों और गाँवों में ब्रॉडबैंड हाइवे की खुली पहुँच माऊस के एक क्लिक पर विश्व स्तरीय सेवा उपलब्धता को मुमकिन बनाएगा।

स्वच्छता



दुर्गेश कुमार राय
अनुरक्षण - पूर्वखंड

स्वस्थ जीवन ही सूखी, सक्षम एवं प्रगतीशील जीवन का आधार है और यही एक सशक्त राष्ट्र की नींव भी है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन कहावतों में "जहां स्वच्छता होती है वहाँ देवता का निवास होता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।

अर्थात अगर अपने मातृभूमि को देवस्थान यानि स्वर्ग जैसा बनाना हो, तो स्वच्छता अति आवश्यक है। समाज में स्वच्छता का प्रचार प्राचीन समय में धर्म के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्तमान समय में इसका वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रचार एवं प्रसार करना अति आवश्यक है।

भारत में संक्रमण से होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण बदलते मौसम, विविध भौगोलिक संरचना तथा गरीबी एवं अज्ञानता आदि हैं। संक्रमण से होने वाली अधिकांश बीमारियाँ जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, आदि से प्रभावी रुप से बचाव का सबसे सस्ता एवं सुलभ माध्यम स्वच्छता है। इन बीमारियों से प्रतिवर्ष लाखों लोग या तो मर जाते हैं या कुपोषित अथवा अपंग होकर रह जाते हैं। इसके चलते हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में तो कमी होती है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग भी इसमें खर्च हो जाता है। स्पष्टत: अस्वच्छता हमारे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है।

अत: सभी राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों ने इस दिशा में कार्य किया है परंतु इसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। जिसका कारण इस कार्य में जन-जागरुकता एवं जन भागीदारी की कमी। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्तूबर 2014 को यानि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया जिसमें जन भागीदारी विशेष कर बच्चों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। इस पर करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च कर करीब सवा करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं में पुरूष एवं स्त्री के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। फलस्वरूप, आज देश के सत्तर हजार गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। अगला लक्ष्य है कि बापू के 150 वें जन्मदिन यानि 2 अक्तूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त करना।

खुले में शौच रोकना स्वच्छता अभियान का एक प्रारंभिक चरण है। इसके अलावा स्वच्छता के कई अन्य बिन्दु हैं जैसे स्वयं अपने घर एवं परिवार के अलावा गली, मुहल्ले, कसबे, शहर, प्रांत एवं राष्ट्र की संपूर्ण स्वच्छता। इतना बड़ा कार्य सिर्फ सरकारी प्रयास से कभी संभव नहीं है। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनना होगा। स्वच्छता को शिक्षा एवं जागरुकता अभियान के माध्यम से हमारे संस्कार में डालना होगा। स्कूलों में अक्षर ज्ञान से पहले शुरू के 2 वर्षों में हमें राष्ट्रीयता एवं स्वच्छता का मौखिक पाठ पढ़ाने की जरूरत है। देश की नारी शक्ति को इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी लेनी होगी।

सरकार हर माध्यम से जागरुकता का प्रयास कर रही है। परंतु इसे यथार्थ रूप देने हर नागरिक, हर परिवार, हर गाँव व शहर, हर प्राइवेट, पब्लिक संस्थान एवं हर प्रांतीय सरकार को सच्चे दिल से हाथ मिलाना होगा।

कंप्यूटर के उपयोग में सुरक्षा



सुनील कुमार कुशवाह
मुख्य प्रबंधक
(सीआईटी-ईआरपी)

हम सबने यह कहावत तो सुनी ही है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर! जाहिर सी बात है कि किसी बीमारी के इलाज में जितना समय और ऊर्जा खर्च होती है, उससे काफी कम ऊर्जा और थोड़ी सावधानी से हम काफी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बात जब आपके कंप्यूटर, ऑनलाइन डेटा और हैकिंग जैसे विषयों की हो रही हो तब यह और भी खास हो जाता है। नीचे कंप्यूटर के उपयोग और सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है।

पासवर्ड्स हैकिंग एवं फिशिंग से बचें (Passwords hacking and Fishing): जरा सोचिये, अगर आपके कंप्यूटर का, वेबसाइट एडमिन का पासवर्ड किसी के हाथ लग जाए? फिर न केवल उससे आपकी व्यक्तिगत या प्रोफेशनल सूचनाएँ सार्वजनिक होने का खतरा रहता है, बल्कि डेटा लॉस से लेकर डेटा डिलीट होने तक का रिस्क आपके सामने रहता है। आज की दुनिया में, यह विचार करना ही कितना भयावह है कि आपकी मुख्य मेल आईडी हैक हो जाए अथवा आपके कंप्यूटर का डेटा करप्ट हो जाए। ऐसे में पासवर्ड को कठिन रखना की उपयोगिता से आप अवगत हैं, जिससे कैपिटल, स्माल लेटर्स के साथ नम्बर्स एवं स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग शामिल होता है इसको समय-समय पर बदलते रहना भी एक अच्छा विकल्प है। कल्पना कर लें कि आपकी मेल पर एक लिंक आता है और उसे क्लिक करने पर आपके सामने हूबहू जीमेल या फेसबुक का लॉगिन पेज दिखने लगता है। वस्तुत: यह हैकर्स की चाल होती है कि आप सामने दिख रहे पेज को जीमेल या फेसबुक समझकर अपना युजर आईडी और पासवर्ड इंटर करें और ऐसा करते ही वह हैकर के पास चला जाता है। इससे बचने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट का यूआरएल ब्राउज़र में खुद टी टाइप करना चाहिए और जीमेल, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि बड़ी वेबसाइट के यूआरएल का सिक्योर (https) होना निश्चित कर लेना चाहिए। अंजान कंप्यूटर पर बैठते समय अगर आप अपने पासवर्ड को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट ब्राउज़िंग (Incognito Window) करना चाहिए, जबकि पासवर्ड रिमेम्बर करने का ऑप्शन ब्राउज़र द्वारा पूछते ही मना कर देना चाहिए।

ईमेल की सुरक्षा (Security of Email): ऑनलाइन की दुनिया में अगर सुरक्षा से सम्बंधित किसी जोखिम की बात होती है तो उसमें सर्वाधिक चर्चा ईमेल रिस्क की ही होती है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी ईमेल का पासवर्ड किसी के हाथ लग गया तो वह क्या-क्या कर सकता है? कल्पना कीजिए कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जितनी मेल आईडी हैं, उन पर कोई अश्लील वीडियो का स्पैम-लिंक भेज दे? जाहिर है, यह खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है और आपको अपनी सेंट-मेल में भेजी गई मेल पर भी कभी-कभार नज़र घूमा लेनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी मेल न. जर आएं, जिन्हें आपने नहीं भेजा है तो तुरंत अलर्ट हो जाएँ और अपने पासवर्ड चेंज करने के साथ ही 'लॉग आउट अदर डिवाइसेज' करें, जिससे खतरा कम हो सके। खुदा न खास्ता, अगर आपका पासवर्ड भी बदल दिया गया है तो तुरंत ही रिकवरी मेल्स और रिकवरी फोन्स की सहायता से उसका पासवर्ड रीसेट करने का प्रयत्न करें। बावजूद इसके अगर आप सफल न हों तो इसकी कानूनी रिपोर्ट करने में देरी न करें, अन्यथा आपकी मेल से हुई किसी गैर कानूनी गतिविधि के झमेले में आप भी पड़ सकते हैं। यह कुछ-कुछ आपके फोन के सिम की तरह



है जो प्रक्रिया आप फोन के सिम गुम होने पर अपनाते हैं, कुछ-कुछ वही प्रक्रिया ईमेल के हैक होने पर भी अपनाएँ। अपने ईमेल की सेटिंग चेक करते समय 'फॉरवार्डिंग रूल्स' पर भी जरूर ध्यान दें कि कहीं आपकी फ्यूचर मेल्स तो कहीं नहीं जा रही हैं! हालाँकि, ईमेल हैकिंग से बचने के लिए 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अपनाएँ जो जीमेल जैसे कई सर्विस प्रोवाइडर प्रदान करते हैं। इस क्रम में मालवेयर से सावधानी रखना भी उतना ही आवश्यक है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड फ्रॉड (Credit/Debit Card Fraud): यह एक ऐसा फ्रॉड है, जिससे आपको डायरेक्ट चूना लग सकता है, यदि आपने जरा भी असावधानी बरती तो। इसे हैक करने के लिए भी 'फिशिंग' जैसी टेक्निक्स काम में लाई जाती हैं तो ऑफलाइन भी इसके लिए काफी दुष्प्रयास किए जाते हैं। आप यदि बैंकों की ब्रांच में जाएँ तो बड़े-बड़े अक्षरों में लटके बैनर आपको हिदायत देते मिलेंगे कि 'आपका बैंक आपसे अकाउंट सम्बंधित जानकारी फोन पर नहीं मांगता है, अत: अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल किसी को न दें।' आपको आपकी ही भाषा वाली किसी लड़की या लड़के का फोन आता है, वह कहता है कि वह 'अमुक बैंक' से बोल रहा है और फिर धीरे-धीरे आपसे जानकारियाँ लेना प्रारम्भ करता है। नाम, पता, अकाउंट नं, क्रेडिट कार्ड डिटेल... ...!! ऐसे में कई लोग फँस जाते हैं और फिर उनको कुछ देर बाद पता चलता है कि उनके अकाउंट से रूपये निकल चुके हैं। अगर ऐसा मेसेज आपके मोबाइल पर आता है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। हालाँकि, बेहतर यह होगा कि आप ऐसे किसी जाल में फँसे ही नहीं। इसके लिए आप सिक्योर सर्वर (https) वेबसाइट के अतिरिक्त दूसरी किसी वेबसाइट का कतई प्रयोग न करें और जानी पहचानी और विश्वस्त कंपनियों के अतिरिक्त अनजान वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड डिटेल डालने से परहेज करें /अगर ऐसा करना अत्यंत जरूरी ही हो तो उस वेबसाइट और कंपनी का फिजिकल एड्रेस अवश्य ही चेक करें। सर्वे बताते हैं कि ऑनलाइन खरीददारी के लिए प्रीपेड कार्ड एक बढ़िया विकल्प होते हैं, जिसमें आप जरूरत के अनुसार राशि ही रखते हैं। वैसे आजकल अधिकांश कार्ड्स में एडेड लेयर सुरक्षा आती है, जो ओटीपी के माध्यम से ही आगे बढ़ती है, फिर भी पुराने कार्ड होल्डर्स को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तमाम विशेषज्ञ पब्लिक कम्प्यूटर्स और सार्वजनिक वाईफाई को शॉपिंग के लिए ठीक नहीं मानते हैं।

सुरक्षा एक ऐसा विषय है, जिसकी आवश्यकता हमेशा ही रहती है और बदलते तकनीकी युग में तो यह और भी आवश्यक है। तकनीक से निश्चित तौर पर आपको काफी सहूलियते मिली हैं, किन्तु अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो इसी तकनीक की सहायता से गलत तत्व आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए, तकनीक का इस्तेमाल अवश्य करें, स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करें, किन्तु "सुरक्षा" के साथ!

बलि पर रोक



पी आर सावंत
प्रबंधक सामग्री

यह घटना उस समय की है, जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारन में कस्तूरबा के साथ बैठे चरखा कात रहे थे। अचानक कुछ शोरगुल सा सुनाई दिया।

जब शोरगुल बढ़ गया तो गांधीजी को पता चला कि कुछ लोग एक हृष्ट-पुष्ट बकरे को फूल-मालाओं से सजाकर बैंड बाजे के साथ बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। अबोध व निर्दोष बकरे को बलि के लिए ले जाते देखकर कस्तूरबा विचलित हो उठीं और लोगों से बोलीं, "भला इस अबोध-गूँगे जानवर का वध करके तुम्हें क्या मिलेगा?"

वे लोग बोले, "माता, बकरे की बलि से देवी खुश होगी, इससे हमारे सब रोग-कष्ट दूर हो जाएँगे और न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को सुख-शांति मिलेगी, अपितु संपूर्ण गाँव में भी सुख-शांति फैलेगी।" लोगों की यह बात सुनकर गांधीजी बोले, "बताओ, जानवर श्रेष्ठ है या मनुष्य?" वे लोग बोले, बापू, निश्चित ही मनुष्य जानवर से श्रेष्ठ है। लोगों का जवाब सुनकर गांधीजी बोले, "जब मनुष्य जानवर से श्रेष्ठ है तो फिर जानवर की क्यों, मनुष्य की बलि देनी चाहिए। स्वस्थ व हट्टे-कट्टे मनुष्य की बलि से देवी ज्यादा खुश होंगी और फिर सभी लोगों को ज्यादा सुख-शांति व धन-धान्य की प्राप्ति होगी। बोलो, सभी लोगों की सुख-शांति व धन-धान्य के लिए आपमें से कौन अपनी बलि देने के लिए तैयार है?" गांधीजी की बात सुनकर सब लोगों को साँप सूँघ गया, वे सिर नीचे कर खड़े रहे। जब कोई भी अपनी बलि देने को तैयार न हुआ तो गांधीजी बोले, "चलो, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ।" यह सुनकर सभी व्यक्ति अत्यंत शर्मिंदा होते हुए बोले, "बापू, हमसे भूल हुई। आगे से हम किसी प्राणी की बलि नहीं देंगे। आज आपने इस बात का अहसास करा दिया है कि निर्दोष प्राणी की बलि से सुख-शांति व धन-धान्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु मानव के नेक कर्म, संघर्ष व मेहनत ही उसे ये चीजें प्रदान कर सकते हैं।" इसके बाद उन्होंने बकरे को छोड़ दिया और अपने-अपने घर चले गए।

विमुद्रीकरण (Demonetization)





जयंतिका मुखर्जी
हिन्दी अनुवादक

8 नवम्बर, 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 500 और 1000 के नोटों को उसी रात (8 नवम्बर) 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की। अर्थात ९ नवम्बर से कुछ तय जगहों (पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, रेल्वे स्टेशन इत्यादि) को छोड़कर देश में कहीं भी 500 और 1000 के नोटों के लेन-देन पर रोक लगा दी गई।

इन जगहों पर भी नोटों के प्रयोग को तय समय सीमा (अब २४ नवम्बर) तक ही अनुमति दी गई थी। जिन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट हैं वे उन्हें 30 दिसंबर तक देश के किसी भी बैंक या डाकघर में जाकर बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। सरकार ने पुराने नोटों की जगह 500 और 2000 के नए नोट जारी किए जो लोगों को बैंको और एटीएम के माध्यम से मिलने शुरू हो गए हैं। हालाँकि लेन-देन के पूरी तरह सामान्य होने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। शहरों में यह समस्या विकट रूप नहीं धारणकर पाई, लेकिन देश के पिछड़े इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

आइए, हम विमुद्रीकरण का आशय और कारण जाने कि सरकार इसका फैसला क्यों लेती है और भारत में ऐसा कब-कब हुआ।

विमुद्रीकरण क्या है

जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण (डीमोनेटाइजेशन) कहते हैं। विमुद्रीकरण के बाद उस मुद्रा की कुछ कीमत नहीं रह जाती। उससे किसी तरह की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समयसीमा तय कर देती है। उस दौरान जिन्होने अपने नोट बैंकों में जाकर नहीं बदले या जमा नहीं किए उनके नोट कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं।

विमुद्रीकरण करने का कारण

सरकार ऐसा कई करणों से कर सकती है। सरकार पुराने नोटों की जगह नए नोट लाने पर पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है। मुद्रा की जमाखोरी (कालाधन) को खत्म करने के लिए भी बड़े राशि के नोटों का विमुद्रीकरण किया जाता है। आतंकवाद, अपराध और तस्करी जैसे अपराधिक कामों में भी बड़े पैमाने पर नगद लेन-देन होता है। इन कामों में लिप्त लोग कई बार नगद राशि अपने पास जमा करते हैं। बाजार में कई बार नकली नोट भी प्रचलन में आ जाते हैं। सरकार नकली नोटों से छुटकारा पाने के लिए पुराने नोट बदल देती है। जालसाजी से बचने के लिए नई तकनीकी से तैयार किए गए ज्यादा सुरक्षित नोट लाने पर भी सरकार पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है। टैक्स चोरी के लिए किए जाने वाले नगद लेन-देन को हस्तोत्साहित करने के लिए भी सरकारें कई बार विमुद्रीकरण का रास्ता अपनाती हैं।

भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास

पहली बार साल 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 1938 में गठित भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक 10 हजार रुपये से अधिक का नोट जारी नहीं किया है। 1970 के दशक में प्रत्यक्ष कर की जाँच से जुड़ी वानचू कमेटी ने कालाधन बाहर लाने और उसे खत्म करने के लिए विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था। लेकिन इस सुझाव के सार्वजनिक हो जाने की वजह से कालाधन रखने वालों ने तत्काल अपने पैसे इधर उधर निकाल दिए।

1977 में इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए और केंद्र में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनवरी, 1978 में मोरारजी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000





के नोट बंद कर दिए। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल सरकार के इस कदम से सहमत नहीं थे। पटेल के अनुसार यह फैसला कालाधन खत्म करने के बजाय पिछली भ्रष्ट सरकारों को पंगु बनाने के लिए लिया गया है।

अब तक भारत में किसी नोट को पूरी तरह बंद केवल दो बार ही किया गया है लेकिन कई बार पुराने नोट को सरकार धीरे-धीरे बंद कर देती है और उसकी जगह उतने ही मूल्य के नए नोट जारी कर देती है। जैसे साल 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेसनीत सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। 2005 से पहले छापे गए 500 के नोटों के पीछे जारी किए जाने का साल नहीं लिखा होता था। सरकार ने बाज़ार में चल रहे 500 के नकली नोटों और नोटों की जमाखोरी को खत्म करने के लिए पुराने नोट बंद कर दिए। 500 के पुराने नोटों को बैंकों में नए नोटों से बदलने की सुविधा दी गई थी।

8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने की घोषणा की। हालाँकि उन्हें आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का समर्थन हासिल था। उर्जित पटेल ने पीएम मोदी के फैसले को बहुत साहसिक कदम बताया हालाँकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन विमुद्रीकरण को कालाधन बाहर लाने के लिए ज्यादा कारगर नहीं मानते हैं। कई अन्य विशेषज्ञ ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के प्रोफेसर अभिरूप सरकार के अनुसार कालाधन रखने वाले ज्यादातर लोग अपने पैसे विदेशी बैंकों में रखते हैं इसलिए देश में विमुद्रीकरण करने से ज्यादा बड़े मछलियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2016 तक भारत में 16.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट बाजार में थे जिसमें से करीब 14.18 लाख रुपये 500 और 1000 के नोटों के रूप में थे। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में तब तक मौजुद कुल 9026 करोड़ नोटों में करीब 24 प्रतिशत नोट (करीब 2203 करोड़ रुपये) ही प्रचलन में थे।

विमुद्रीकरण एक नई धारा या चिंता नहीं है। विश्व में ऐसे कई देश है जिसने अपने रुपये का विमुद्रीकरण किया है। आईए ऐसे कुछ देशों पर नजर डाले:

1) घाना

वर्ष 1982 में, घाना की सरकार ने 50 सेडीस के विमुद्रीकरण का फैसला काला बाजारी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए किया। हालाँकि उनके इस प्रयास को सफलता नहीं मिली। देशव्यापी अवस्था के फलस्वरुप उन्हें अपना यह फैसला रद्द करना पड़ा।



2) नाइजीरिया

नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई भी जब नाइजीरियन सरकार ने वर्ष 1984 में विमुद्रीकरण कर पुराने नोटों के बदले अन्य रंग के रुपये बाजार में लाए। तत्कालीन सैनिक सरकार के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कदम उठाया था।



3) म्यानमार (बर्मा)

वर्ष 1987 में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से देश को उबारने के लिए सैनिकों द्वारा करीब 80% म्यानमार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। इस विमुद्रीकरण के फलस्वरूप देश में काफी विरोध हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए।



5) उत्तर कोरिया

2010 में उत्तर कोरिया में विमुद्रीकरण किया गया जिसके चलते उत्तर कोरिया व्यापक आर्थिक समस्याओं का सामना करने पर बाध्य हो गया।



4) सोवियत यूनियन

मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में वर्ष 1991 में, तत्कालीन सोवियत यूनियन ने 50 और 100 रूबेल का विमुद्रीकरण किया। यह फैसला सरकार के विरूद्ध साबित हुआ और सरकार 8 महीने में ही गिर गई।



6) ज़िम्बाब्वे

ज़िम्बाब्वे के पास एक सौ ट्रिलियन डॉलर में रुपये थे, जिसका विमुद्रीकरण किया गया। इस विमुद्रीकरण के फलस्वरूप इसका मूल्य घटकर डॉलर 0.5 हो गया।



फिर भी अगर हम वर्ल्ड बैंक के आकड़ों को देखे तो पता चलेगा कि 2015 में दक्षिण एशिया में भारत की विकास दर सबसे ज्यादा रही है। ऐसा माना जाता है कि रियर एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इसी सेक्टर पर खपाई जाती है। आशा की जा सकती है कि इस नोटबंदी से रियल एस्टेट के कीमतें नीचे आएंगी। 500-1000 के पुराने नोटों पर पाबंदी लगाने से शैडो बैंकींग बंद होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अर्थव्यवस्था में वित्तिय स्थिरता को खतरा कम होगा। 'शैडो बैंकिंग' का अर्थ है बैंक जैसी गतिविधियाँ करना। इन पर बैंकिंग जैसी कोई कानूनी बाध्यता नाहीं होती और न ही कोई मजबूत कानून का शिकंजा ही होता है। बैंकिंग श्रेणी के बाहर जेपी लोग या संस्थान वित्तीय लेन-देन करते हैं उन्हें शैडो बैंकिंग की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय बैंकों के नॉन परफार्मेंस एसेस्ट्स अर्थात NPA सूचकांक नीचे आएगा। इससे बैंकों के पास इन्फ्रा के विकास हेतु एनआईवी4एस की अधिक क्षमता होगी और जनता को ज्यादा पैसा कम व्याज पर मिलेगा और लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

रुपया विमुद्रीकरण के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टी डालने पर हम आसानी से इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि विश्व के देशों में विमुद्रीकरण का फैसला कोई नई व्यवस्था नहीं है। देशों ने कालाबाजारी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए समय-समय पर ऐसे कदम उठाए हैं। हालाँकि यह विचारणीय विषय है कि कहाँ तक यह कदम देश हित में कारगर रहा है, या फिर किस हद तक इसको सफलता मिली है, या मिलेंगी।

स्वदेशीकरण में उच्च स्तर हासिल करना (एसआईसीएडीएस का स्वदेशीकरण)



एस डी डोल्हारे
मुख्य प्रबंधक (स्वदेशीकरण)

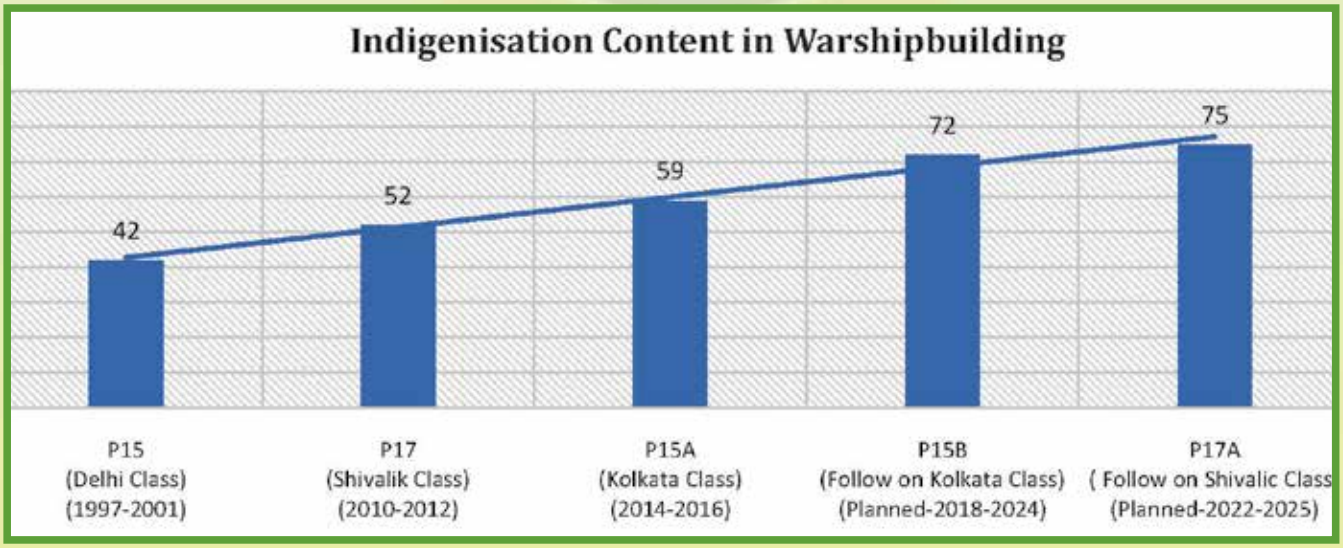
1. भूमिका - 'मेक इन इंडिया' की पहल माझगांव डॉक में सन 1960 से ही प्रारम्भ किया है एक सामरिक राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ स्वदेशी जहाज निर्माण योजना के अंतर्गत पहले युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी के निर्माण से जारी है। तब से एमडीएल निरंतर स्वदेशीकृत सामग्री का उपयोग युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण में करता आ रहा है।

स्वदेशीकरण के प्रति एमडीएल का सतत प्रयास और वचनबद्धता उनके जहाज निर्माण में स्वदेशीकृत उपकरणों के उपयोग प्रतिशत को देख कर ज्ञात होता है जो स्थिर गति से निरंतर बढ़ रहा है। जिसे नीचे दिए गए ग्राफ में देखा जा सकता है।

2. स्वदेशीकरण प्रयास में बढ़ोत्तरी - स्वदेशीकरण के इस प्रयास को और अधिक बढ़ावा देने एवं समर्थ बनाने के लिए एक स्वदेशीकरण विभाग का गठन नवम्बर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के लक्ष्य 'मेक इन इंडिया' को शक्ति प्रदान करने हेतु किया गया है। तब से अब तक एमडीएल ने स्वदेशीकरण पर महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसे आगे के पैराग्राफ में सूचीबद्ध किया गया है।

3. मेक इन इंडिया वेबपेज का निर्माण - एमडीएल ने पृथक रूप से 'मेक इन इंडिया' वेबपेज का निर्माण एमडीएल वेबसाइट में किया है जो रक्षा मंत्रालय के मेकइनइंडियाडिफेंस.कॉम से लिंक है और उसमें विविध मदों/उपकरणों का व्योरा है। जिसे स्वदेशीकृत करने की आवश्यकता है, उसमें एसओटीआर, स्वदेशीकरण प्रक्रिया तथा प्रभारी अधिकारी का विवरण अपलोड किया गया है इसका प्रमाण है कि वेबसाइट पर सूचीबद्ध मदों को देखकर, अनेक फ़र्मों ने स्वदेशीकृत मदों को विकासित करने हेतु एमडीएल से संपर्क किया है।

4. स्वदेशीकृत किए गए मद/उपकरण - स्वदेशीकरण विभाग की स्थापना के साथ ही, एमडीएल ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित मदों/उपकरण को भारतीय उद्योगों के माध्यम से स्वदेशीकृत किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:



क्र. सं	मदों/उपकरण	आयात के पुराने स्त्रोत	अब स्वदेश निर्मित है
क	एमआईसीएडीएस(शिपइन्स्टाइल्ड केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम)	मेसर्स स्मिथ, जर्मनी	मेसर्स एल एंड टी, सेक बेंगलुरु एवं डीआरडीई, ग्वालियर
ख	सोनर डोम	मेसर्स एटलस, जर्मनी	मेसर्स कीनेकों, गोवा
ग	ब्रिज विंडो ग्लास	मेसर्स सेंट गॉबेन, स्पेन	मेसर्स जीत एंड जीत ग्लास जयपुर
घ	एमसीटी ग्लैंड्स	मेसर्स रोक्सटेक, स्वीडन	मेसर्स वालमैक्स, फ़रीदाबा
ड़	प्रेशर रिड्युसिंग स्टेशन	मेसर्स डायनामिक कंट्रोल, युके	मेसर्स फ्लैश फोर्ज, नवी मुंबई
च	रिमोट कंट्रोल वाल्व्स	थॉमप्सन वाल्व्स, यूके	मेसर्स डेलवाल्व्स, सतारा, पुणे

5. ऊपर सूचीबद्ध, स्वदेशीकृत मदों में, शिप इन्स्टाल्ड केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम एक स्टेट ऑफ आर्ट डिटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर त्वरित और युद्धपोत के अंदर और बाहर निरंतर रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन और पर्यावरण में उपस्थित केमिकल वारफेयर एजेंट को मापने के लिए किया जाता है। युद्धपोत को नौसेना की सुपुर्दगी में एसआईसीएडीएस को इंस्टलेशन और संचालन क्रिया एक बहुत ही नाजुक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसको लगाने के बाद ही प्रमाणित किया जाता है कि अब एनबीसीडी का अनुपालन हुआ है और युद्धपोत युद्ध के योग्य है। एसआईसीएडीएस एक केबल है जो निम्न जहरीले केमिकल एजेंट को लिक्विड, एरोसोल एवं वेपर रूप में डेटेक्ट कर सकता है:

क) ऑल नर्व एजेंट्स
ख) ऑल नोन ब्लिस्टर एजेंट्स
ग) ऑल नोन ब्लड एजेंट्स
घ) ऑल नोन चोकिंग एजेंट
ड़) किसी भी नए एजेंट और द्रुतगामी को डिटेक्ट करने की क्षमता

6. अभी तक एसआईसीएडीएस विभिन्न भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इंस्टाल किए गए हैं। जो विदेशी विक्रेता से आयातित तथा भारतीय नौसेना से नामित थे। केवल तीन देशों (यूएस, यूके एवं जर्मनी) में ऐसे सिस्टम को विकसित करने की क्षमता है। अब, एसआईसीएडीएस के स्वदेशीकरण की ज़िम्मेदारी एमडीएल को रक्षा मंत्री उत्पादन समिति के निर्देशानुसार सौपी गयी है, जिसके संबंध में पत्र दिनांक 16 अपैल, 2016 के पत्र सं 2(3)/2014/डिटीपी द्वारा जारी किया गया है।

7. तदनुसार, एसआईसीएडीएस के स्वदेशीकरण का विकास एमडीएल, मुंबई, के नेतृत्व में मेसर्स एल एंड टी, सेक बेंगलुरू (रुपांकन एवं विकास पार्टनर), मेसर्स डीआरडीई ग्वालियर (टेस्टिंग एवं मूल्यांकन पार्टनर), आईएचक्यू, रक्षा मंत्रालय(एन)/ डीएनबीसीडी (तकनीकी आवश्यकताओं के प्रदाता) तथा आईएचक्यू, एमओडी(एन)/ डीओआई (निरीक्षण से संबन्धित गतिविधियों के लिए) के सहयोग से परिचालित है।

8. एसआईसीएडीएस स्वदेशीकरण अक्टूबर 2014 से आरंभ किया गया। एसआईसीएडीएस का सफल परीक्षण जनवरी 2016 में सीमुलेटर्स सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। फिर भी, डीआरडीआई, ग्वालियर में लाईफ एजेंट्स के साथ सिस्टम परीक्षण अप्रैल 2016 तक पूरा किया जा सका क्योंकि जनवरी 2016 से पहले परीक्षण स्लॉट उपलब्ध नहीं था और ग्वालियर स्थित डीआरडीई, प्रयोगशाला पहले से ही बुक थी। लाईव एजेंट्स के साथ सिस्टम का सफलतापूर्वक परिक्षण 25 से 27 अप्रैल, 2016 तक सभी अंशधारकों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

9. यह ध्यान देना आवश्यक है कि सम्पूर्ण सिस्टम का आरेखन और विकास भारत में 80% स्वदेशी सामग्री से किया गया है। इसके आगे, भारत, भी अब उन विशिष्ट देशों की श्रेणी में आ गया है जिनके पास सिस्टम के आरेखन एवं विकास करने की क्षमता है। एसआईसीएडीएस के परिचालन सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-क में रखा गया हैं।

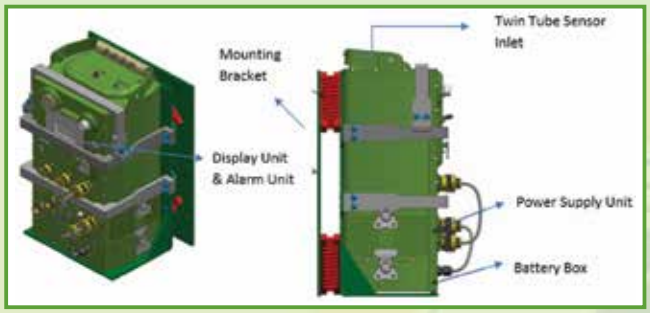
10. स्वदेशीकरण से विकसित एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) को एमडीएल के जारी परिजिनाओं (15बी के 4 जहाजों और पी17ए के 7 जहाजों) में शामिल करने पर इससे रु. 17 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और आगे आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना के विस्तार योजना में यह बचत बड़ी मात्रा में होगी। यह भी ध्यान देने की बात है कि यह रक्षा क्षेत्र में उपयोग करने के अलावा यह सिस्टम देश के भीतर स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और देश की सम्पत्तियों जैसे विमानपत्तन, समुद्री बन्दरगाहों, शोध प्रतिष्ठानों एवं संसद आदि की सुरक्षा में उपयोग किया जा सकता है।

अनुलग्नक-क

1. **एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) का परिचालन सिद्धांत**

एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) एक स्टेट ऑफ आर्ट डिटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय नौसेना के पोतों पर त्वरित और पोत के अंदर और बाहर निरंतर रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन और पर्यावरण में उपस्थित केमिकल वारफेयर एजेंट का पता लगाने के लिए स्थापित किया जाता है।

2. एसआईसीएडीएस (सिकैड्स), में स्टेट ऑफ आर्ट टविन ट्यूब सेंसर का उपयोग किया जाता है जो एक डिस्प्ले और पावर सप्लाई यूनिट के साथ जुड़ा होता है, जिसे चित्र 1 में जैसे दर्शाया गया है।



एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) का रुपांकन केमिकल वाफेयर एजेंट्स के मीनूटेस्ट ऑफ ट्रैसेस का पता लगाने के लिए किया गया है यह पहले एजेंट को पहचान कर डिस्प्ले पर दर्शाता है और आवश्यक अलार्म प्रदान कराता है।

3. एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) का उपयोग वायु में निहित सैम्पल एजेंट का पता लगाने के लिए किया जाता है यह एक अतिरिक्त डिवाइस है जिसे थ्रु बल्कहेड सैंपलिंग सिस्टम (टीबीएसएस) कहते हैं। इसे जहाजों पर आउटर बल्कहेड में लगाया जाता है जो बाहरी वायु को सेंसर यूनिट में खींचती है जिसे, चित्र -2 में दर्शाया गया है।

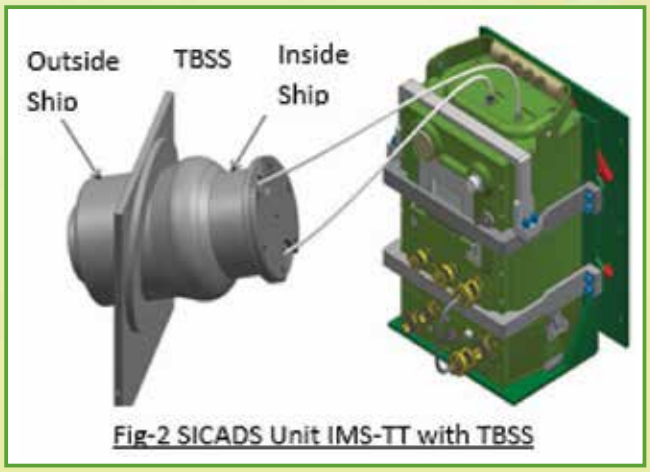


Fig-2 SICADS Unit IMS-TT with TBSS

4. स्टेट ऑफ आर्ट टविन ट्यूब सेंसर टेक्नॉलोजी आयोन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोनेटरी(आईएमएस) प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आईएमएस आधारित सेंसर एक ऐसी प्रणाली है जो वातावरण में मौजूद खतरनाक रासायनिक तत्वों (जी एवं एच) का पता लगाती है। यह उपकरण प्लासमा क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत पर परिचालित होता है यह विभिन्न प्रकार के गैसों के आधार पर उडान के समय आयोन को अलग करने की प्रक्रिया है। यह प्रणाली का निर्माण पर्यावरण में मौजूद गैस सैम्पेल अंदर की ओर खींचती है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उत्पन्न होता है, इसे आयोन मोबिलिटी स्पेक्ट्र कहते है।

5. केमिकल एजेंट्स की पहचान मोबिलिटी, के आधार पर की जाती है टाइम ऑफ फ्लाइट(टीओएफ) यानी, आयोन द्वारा ड्रिफ्ट ट्यूब के माध्यम से फ्लाइट करने का समय जैसेकि प्रत्येक केमिकल एजेंट का अपना अलग अस्तित्व होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट सूचक है कि कौन सा केमिकल एजेंट मौजूद है और उसकी पीक हाइट उस केमिकल एजेंट के केन्द्रीकरण का मापन है।

6. सेंसर में दो नोज़ल लगे होते हैं, एक एयर इनलेट के लिए और दूसरा एक्जॉस्ट एयर के लिए। सेंसर इनलेट से वायु खींचता है और केमिकल वारफेयर एजेंट्स (सीडब्ल्यूए) की उपस्थिति का विश्लेषण करता है। इस सिस्टम के फ्रंट पैनल में विभिन्न यूजर इंटरफसेज़ जैसे कंट्रोल स्विचेज़, डिस्प्ले विंडो, फोर बटन कीपैड सेंसर और अलार्म स्विच को इनपुट उपलब्ध प्रदान करने के लिए लगे होते हैं। यह सिस्टम आडियो-वियूअल अलार्म प्रदान करता है यदि, सीडब्ल्यूए का कंसंट्रेशन निर्धारित सीमा से आगे बढ़ जाता है तो फ्रंट बज्जर/डिस्प्ले के माध्यम से दर्शाता है को इनपुट उपलब्ध /ह/डिस्प्ले के माध्यम से दर्शाता है। या सिस्टम के हेल्थ स्टेटस के बारे में सूचना बिल्ट इन स्टेट (बीआईटी) के माध्यम से पावर ऑन के साथ और समय-समय पर आवधिक परीक्षणों के दौरान करता है।

7. भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर पाँच एसआईसीएडीएस (सिकैड्स) सेंसर आंतरिक और बाह्य वायु की निगरानी करने के लिए लगाए जाते हैं। युद्धपोत में दो सेंसर लगाए जाते है, एक प्रत्येक पोर्ट साइड में और दूसरा स्टारबोर्ड की साइड में। यह बाह्य वायु की निगरानी करते हैं और शेष तीन सेंसर प्रत्येक पोत के आंतरिक वायु की निगरानी के लिए लगाए जाते हैं। ये सभी सेंसर एक केंद्रीय निगरानी एवं नियंत्रण इकाई से जुड़े होते हैं। जैसे वही किसी केमिकल एजेंट पता लगता है यह आवश्यक सूचना एवं चेतावनी प्रदान करते हैं।

कश्मीर



संजय मिश्रा
प्र (मा.स.)

1947 के देसी राज्यों में जम्मू और कश्मीर का राज्य सबसे बड़ा था। उसका क्षेत्रफल 48,471 वर्गमील था और 78 प्रतिशत प्रजा मुसलमान थी। कश्मीर घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की जनता के नाक-नक्श सुंदर हैं। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर का बहुत महत्व है। उत्तर-पश्चिमी सरहद पर उन दिनों के विशालकाय रुस की सरहद थी। उत्तर-पूर्व में महाकाय चीन की सरहद है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कश्मीर का बहुत महत्व था, और है।

सन 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमृतसर करार के तहत महाराजा हरिसिंह के पूर्वजों को जम्मू-कश्मीर घाटी को 75 लाख रुपयों में बेचा था। 18 फरवरी, 1926 को महाराजा प्रतापसिंह ने अपने भतीजे कुँवर हरिसिंह का राज्याभिषेक किया। तब से महाराज हरिसिंह ने बाईस वर्षो तक जम्मू-कश्मीर पर राज किया।

अंग्रेज सरकार और उनसे प्रभावित आम लोगों की धारणा के विपरीत महाराजा हरिसिंह एक दूरदर्शी समाज-सुधारक राजा थे। अपनी कश्मीरी प्रजा के सुख-चैन और विकास के बारे में जाग्रत थे। अपने शासनकाल में हरिसिंह ने अनेक सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय सुधार किए। उन्होंने कन्या भ्रूणहत्या को सख्ती से बंद करवाया। बाल-विवाह और 16 साल की उम्र तक धुम्रपान नहीं करने का कानून बनवाया और उस पर ईमानदारी पूर्वक अमल किया गया। विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सन 1933 में मंदिरों में हरिजन प्रवेश शुरू करवाया और इसी तरह 1940 में दहेज प्रथा को बंद करवाया। इस प्रकार पूरे राज्य में समाज-सुधार की छोटी-सी लहर चल पड़ी थी।



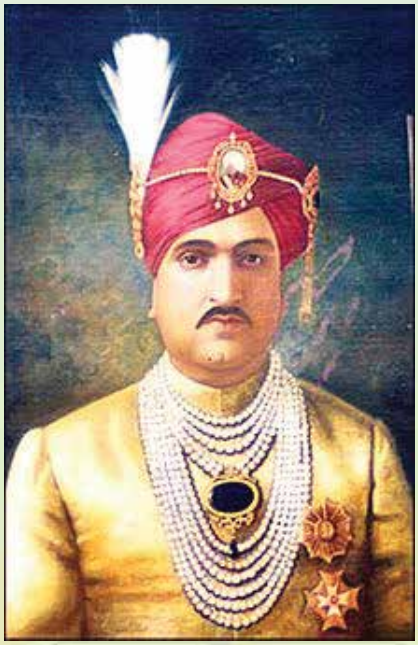
राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल-कॉलेज खोले गए और प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी कर दी गई। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य से बाहर की संस्थाओं में शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई गई। सभी इलाकों में मरीजों के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया गया और अनेक अस्पताल भी खोले गए। इसी क्रम में बनिहाल पास का रास्ता और सुरंगों को पक्का करवाया। सन 1928 में जम्मू-कश्मीर बैंक की स्थापना की गई और राज्य में कृषि ग्राम-सुधार, नगर विकास, उद्योग और टूरिज्म जैसे कुछ नए महकमें भी खोले गए।

1934 में महाराजा ने प्रजा सभा (आज की विधानसभा) की स्थापना की और उसके लिए सीमित चुनाव भी करवाए।

अंग्रेज सरकार को इन सब समाज-कल्याण नीतियों में राष्ट्रीयता की बू आने लगी, इसलिए अपनी पुरानी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने हिंदू-मुसलमान के कौमी दंगे करवाए और हर तरह के झूठे इल्जाम लगाकर मुस्लिम प्रजा को भड़काया। जब इन वारदातों के चलते राजतंत्र लड़खड़ाने लगा तो वायसराय ने ब्रिटिश रेजिडेंट को तैनात किया ताकि राज्य पर अंकुश बना रहे। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर श्रीनगर के एक स्कूल के अध्यापक शेख अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मुस्लिम कॉन्फरेन्स की स्थापना करवाई गई जो महाराजा के विरोध में काम करने लगी। आज यही संस्था नेशनल कॉन्फरेन्स के नाम से जानी जाती है।

नेशनल कॉन्फरेन्स के नेता शेख अब्दुल्ला को महाराजा साहब ने जून, 1946 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और सभा, भाषण, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़ाने के लिए जवाहरलाल जी कश्मीर जाकर उनका केस खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन महाराजा साहब ने पंडित नेहरु को सरहद पर गिरफ्तार कर लिया और कश्मीर में घुसने से रोक दिया। एक विशाल राज्य के राजा को इतने बड़े भारत देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार गिरफ्तार करवाना-रोकना अनुचित था। शायद महाराजा हरिसिंह घबराकर दिशाभ्रमित हो गए थे।

उस समय देश में कैबिनेट मिशन के साथ मंत्रणा चल रही थी। ऐसे मौके पर जवाहरलाल नेहरु हाजिर न हों तो विचार-विनिमय में अनेक विघ्न-बाधा आनी थी। इस विचार से बापू जी ने जवाहरलाल जी को लिखा कि उनका मान-अपमान कांग्रेस का मान-अपमान था, लेकिन ऐसे मौके पर दिल्ली में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। मन मारकर जवाहरलाल जी कश्मीर सरहद



राजा हरिसिंह

से लौट आए। ऐसी स्थिति 1947 तक चलती रही। बापू जी ने चाहा कि वे कश्मीर जाकर शेख अब्दुल्ला से मिलें लेकिन महाराजा साहब ने मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल तथा गांधी जी, तीनों से उन्हें नफरत भी थी। बापू जी तो ऐसे मनाही हुक्म के सामने सत्याग्रह करते लेकिन उन्होंने माउंटबेटन को आश्वासन दिया था कि वे देश की नाजुक स्थिति को अपने सत्याग्रह से ज्यादा विकट नहीं बनने देंगे। बापूजी कश्मीर के बारे में बड़े चिंतित थे। कई लोगों के माध्यम से महाराजा को समझाकर व्यक्तिगत दुर्गति और राजनीतिक विपदा से कश्मीर को बचा लेने के लिए बापू जी ने अनेक प्रयास किए लेकिन कोई सोया हो तो उसे जगाया जा सकत था; जागे व्यक्ति को जगाना या समझाना असंभव हो जाता है। बापू जी का कहना था कि कांग्रेस कोई पराई संस्था नहीं थी। कांग्रेस तो राजा-प्रजा दोनों की थी। अगर महाराजा कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार-विनिमय करेंगे तो उनका राज्य और सत्ता सुरक्षित रह पाएगी अन्यथा आपत्तियों के अंधड़ में राजा और राज्य दोनों बरबाद हो जाएँगे। 4 जुलाई 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने भी हरिसिंह को समझाते हुए पत्र लिखा कि महाराज साहब को कांग्रेस के प्रतिनिधि सरदार पटेल से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन 'विनाश काले विपरित बुद्धि' के फेर में महाराजा हरिसिंह ऐसी सारी दोस्ताना चेतावनी का निरादर करते चले गए और खतरा मोल लेते रहे।

14 जुलाई, 1947 को संविधान सभा का शुभारंभ हुआ, लेकिन तब भी महाराजा कश्मीर ने निर्णय नहीं लिया था कि वे किस देश के साथ सम्मिलित होंगे। रह-रहकर कश्मीर के बारे में बापू जी को भयानक आपत्ति की आशंका जकड़ लेती थी। उन्होंने सरदार को भी इस विषय में आगाह किया था। 15 अगस्त के एक सप्ताह पहले बापू जी दो दिन के लिए कश्मीर गए थे। बापू जी ने श्रीनगर में आम सभा को भी संबोधित नहीं किया। महाराजा साहब नहीं चाहते थे इसलिए बापू जी ने तो अपना वचन पालन किया और कश्मीर में कोई भी राजनीतिक प्रश्न नहीं छेड़ा, लेकिन उनको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा। श्रीनगर का वातावरण देखकर लगता था मानो बारूद से भरे तोपखाने के पास एक नासमझ राजा चिनगारी लिए लापरवाही से खेल रहा है। प्रजा राजनीतिक उत्थान की आशा लगाए थी। राजा सामंतवाद में डूबे थे। कहीं मेल नहीं था और भारत देश में हिंदू-मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ रहा था। बापू जी को स्पष्ट लग गया कि हिंदूस्तान-पाकिस्तान के बीच कश्मीर का झमेला खड़ा हो सकता था। लार्ड माउंटबेटन ने भी महाराजा को समझाया कि जल्दी से निर्णय लेकर मामला निपटा लें। क्रांति की गति बड़ी तेज होती है और कालचक्र किसी के लिए रुकता नहीं। सरदार पटेल ने महाराजा को यह भी आश्वासन दिया कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन महाराजा कुछ तय नहीं कर पाए। उनका खयाल था कि दोनों राज्यों से अलग रहकर व अपनी ताकत ज्यादा बढ़ा पाएँगे और पाकिस्तान-हिंदुस्तान दोनों को लटकाए रखकर फायदा उठाते रहेंगे। निर्णय के लिए ज्यादा समय लगेगा, इस आशय से

12 अगस्त, 1947 को महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एक वर्ष की अस्थायी मैत्री करार कर लिया। यहाँ पर महाराजा गुरुगंभीर गलती कर गए। उनका इरादा था कि पाकिस्तान के साथ-साथ भारत से भी समझौता करेंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने तेवर दिखाने आरंभ कर दिए।

उन दिनों कश्मीर घाटी का पूरा यातायात पाकिस्तान स्थित पश्चिमी पंजाब के रास्ते चलता था। अनाज, पानी, आवश्यक सामग्री, पेट्रोल, रसद, डाकतार, टेलिफोन, रेलवे, बैंक सब कुछ पाकिस्तान से संलग्न था। काश्मीर की इमारती लकड़ी का निर्यात व्यापार भी पश्चिमी पंजाब की नदियों पर चलता था। उन दिनों का कश्मीर अपनी आर्थिक व्यवस्था और यातायात के लिए पूर्णतया पाकिस्तानी पंजाब पर निर्भर था। महाराजा हरिसिंह की एकवर्षीय मैत्री करार ने पाकिस्तान की लालसा भड़का दी। अब पाकिस्तान खुले आम कश्मीर को हथिया लेने का प्रयास करने लगा। पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था का गला दबाना आरंभ कर दिया। नमक, चाय, चीनी, तेल, पेट्रोल कश्मीर जाने से रोक दिया। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के मुखपत्र 'डान' ने कश्मीर के महाराजा को धमकी दी कि उन्हें झट फैसला करके पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए अन्यथा उन पर भयानक आफत टूट पड़ेगी और वे पछताएँगे।

सितंबर, 1947 में खबर थी कि पाकिस्तान, कश्मीर सरहद पर कबाइलियों को एकत्रित कर रहा है। और पाकिस्तानी सशस्त्र जत्थों ने जम्मू पर धावा बोल दिया। बहुत से गाँव जला दिए गए, लूट लिए गए। जम्मू के हिंदू तबाह होने लगे। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित आक्रामक पाकिस्तानी हर तरह का बलात्कार और अनाचार करते थे और गाँव वालों को मार डालते थे। ऐसे हमले के सामने कश्मीरी सेना सर्वथा बेकार थी। कश्मीर में कुछ भी सँभल नहीं पा रहा था। ऐसी



पंडित जवाहर लाल नेहरू

हालात में महाराजा हरिसिंह को लगा कि कम से कम प्रजा का समर्थन होने से ठीक रहेगा। इस इरादे से 29 सितंबर, 1947 को उन्होंने शेख अब्दुल्ला और साथियों को रिहा कर दिया। शेख अब्दुल्ला कांग्रेसी नेताओं के मित्र थे, बापू जी के प्रशंसक थे और पाकिस्तान के 'मुस्लिम राष्ट्र' के सिद्धांत को नहीं मानते थे। जेल से छुटकर शेख साहब ने भी यही कहा जो योग्य होगा वही वे करेंगे। चालीस लाख प्रजा के हितों का रक्षण कर उनकी इच्छानुसार कश्मीर का फैसला किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अधैर्य और लोलुपत्ता की कोई मिसाल नहीं थी।

15 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर के दीवान मेहरचंद महाजन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़ा शालीन पत्र लिखा और रसद आदि के अभाव में कश्मीर की कठिनाई का वर्णन किया। पाकिस्तानी बैंक कश्मीरियों के चेक और पेंशन तक भुनाती नहीं थी और कश्मीर का पूरा यातायात बंद था। यहाँ तक कि कश्मीर में दर्ज मोटरों के आने-जाने पर भी पाकिस्तान ने रोकथाम लगा रखी थी। ऊपर से रेडियो पाकिस्तान कश्मीर की सतत निंदा करता और झूठे आरोप लगाता था। इतना सब कुछ तो पाकिस्तान सरकार की मदद और अनुमति से ही हो सकता था। इसलिए गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आजम को ऐसे अन्याय और अत्याचार को रोकने की कृपा करनी चाहिए अन्यथा कश्मीर को अन्य से सहायता लेनी पड़ेगी। इस पत्र से जिन्ना साहब और पाकिस्तान सरकार आगबबूला हो गए और जाहिर कर दिया कि ऐसे इल्जाम और धमकी का पाकिस्तान बदला लेगा और अगर कश्मीर पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होगा तो भयानक परिणाम आएगा। उसकी जिम्मेदारी कश्मीर सरकार पर रहेगी। इस धमकी ने महाराजा हरिसिंह को भयभीत कर दिया।

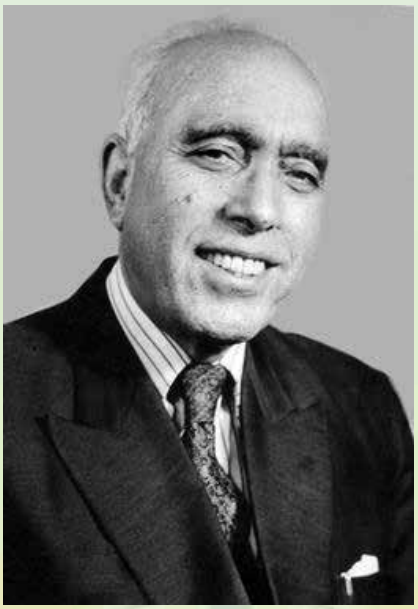
23 अक्टूबर को आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तानी अफसरों के कुशल संचालन में हजारों अफ्रीदी और सरहदी कबाइलियों ने एबोटाबाद, मानसेरा के रास्ते मुजफ्फराबाद पर हमला कर कश्मीर पर धावा बोल दिया। इन हमलावरों में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर भी रुखसती छुट्टी लेकर काम कर रहे थे। इन कबाइलियों का आक्रमण भयावह था। लूटते-मारते रास्ते-भर वे बलात्कार कर रहे थे। इन लोगों के लिए हिंदू तथा मुसलमान, ईसाई, सिख किसी में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि बारामूला की ईसाई संस्था की साध्वियों पर भी इन हमलावरों ने बलात्कार किया और बाद में उन औरतों का कत्ल कर डाला। 24 अक्टूबर को समाचार थे कि रावलपिंडी रोड पर पाकिस्तानी सैन्य की गाड़ियों से कबाइलियों को कश्मीर सरहद पर छोड़ा जा रहा है। 25 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद और डोमेल को कब्जे में कर लिया गया। बारामूला को लूटा और रात को वे लोग वहीं रुक गए। वहाँ से श्रीनगर 38 मील दूर रह गया था। ऐसे आक्रमण का सामना करने के लिए कश्मीर राज्य का सैन्य एकदम अपर्याप्त था। अंग्रेज अफसरों ने जानबूझकर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दी थी ताकि कश्मीर अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहे।

अब महाराजा हरिसिंह घबरा गए। उन्होंने भारत सरकार से सहायता माँगी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत सरकार को सलाह दी कि जब तक कश्मीर भारत में सम्मिलित नहीं

होता तब तक भारत सरकार का सहायता देना अनुचित, अवैधानिक और गैरकानूनी होगा। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के मुख्य सचिव वी. पी. मेनन कश्मीर गए। वहाँ पर महाराजा के साथ चर्चा करने के बाद करार पर हस्ताक्षर किए गए और कश्मीर राज्य भारत में विधिवत सम्मिलित हो गया। उस समय महाराजा ने यह भी आश्वासन दिया कि वे कश्मीर में प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करेंगे। इसलिए शेख अब्दुल्ला को मंत्रिमंडल में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया गया। कश्मीर की नेशनल कॉन्फरेन्स और शेख अब्दुल्ला ने खुद भी भारत सरकार में शामिल होने का लिखित समर्थन किया और सतत सहायता की याचना की ताकि आक्रमणकारियों से कश्मीर घाटी को बचाया जा सके। उस समय एक-एक घंटे का महत्व था। भारत सरकार ने कश्मीर राज्य को भारत में शामिल कर लिया और जैसे ही आक्रमणकारी हट जाएँगे और राज्य में अमन-चैन हो जाएगा तो मतदान करवाकर प्रजा की इच्छा के अनुसार आगे व्यवस्था की जाएगी, ऐसा निर्णय किया।

27 अक्टूबर की उषाकाल के समय मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 330 सिख सैनिकों का पहला दस्ता हवाई जहाज से श्रीनगर पहुँचाया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी के कारण ही दुश्मन श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा नहीं कर पाए। सोमनाथ शर्मा लड़ाई में काम आए और अपने देश का प्रथम परमवीर चक्र उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दिया गया। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त देश में जितने छोटे-मोटे हवाई जहाज थे सबकी सहायता से सरकार ने सेना को कश्मीर पहुँचाया। जिस गति से यह सारी व्यवस्था हुई उसे देखकर माउंटबेटन भी चकित थे। अगर चौबीस घंटे की भी देर हो जाती तो कश्मीर बरबाद हो जाता था।

हमला करने वाले अफ्रीदी इतने लोलुप और बर्बर थे कि बारामूला में लूटमार-बलात्कार करने की लालसा से तीन दिन वहीं रह गए। उन लोगों की लालच ने श्रीनगर को बचा लिया। वे लोग बारामूला



शेखअब्दुल्ला

से आगे बढ़े उसके पहले ही भारतीय जवानों ने हमलावरों को खदेड़ना आरंभ कर दिया। इन दिनों कश्मीर में तंत्र या व्यवस्था नदारद थी और बिजली, पानी, अनाज, रसद का एकदम अभाव था। महाराजा भागकर जम्मू चले गए थे। लेकिन कश्मीर नेशनल कॉन्फेरेन्स के स्वयंसेवक और नेताओं ने, और उनसे भी ज्यादा श्रीनगर के नागरिकों ने एक होकर स्थिति को सँभाल लिया। राजा और उनके अफसरों के बिना श्रीनगर और सारे कश्मीर की लगभग सारी व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही। उन लोगों का संगठन, सहकार और दृढ़ संकल्प आदर्श था। उन दिनों के कश्मीर के सांप्रदायिक भाईचारे को देखकर हिंदुस्थान के विभाजन की नृशंसता एक दु:स्वप्न के समान लगती है। भारतीय जवानों ने पुंछ पुन: जीत लिया और युद्धविराम होने तक हमलावरों को श्रीनगर घाटी के बाहर भगाकर राज्य को काफी हद तक निरापद कर दिया। जरा ज्यादा समय मिलता तो भारतीय जवान पूरे कश्मीर को पाकिस्तान हमले से छुड़ा लेते, लेकिन ऐसी मात खाने के बाद पाकिस्तान ने युद्धविराम की अपील किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल की अनिच्छा के बावजूद युद्धविराम करवाया। इस प्रकार आज का आजाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहा।

कायदे आजम जिन्ना को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी विजयघोष के साथ वे श्रीनगर जाएँगे। उसी आशय से वे बेचारे एबोटाबाद में पाकिस्तानी जीत के समाचार की प्रतीक्षा में बैठे थे। भारत सरकार के जवानों की जीत से तिलमिलाकर जिन्ना साहब ने बाकायदा पाकिस्तानी सेना को कश्मीर पर हमला करने का हुक्म निकाल दिया, लेकिन सेनापति फील्ड मार्शल सर आकिनकेल ने जिन्ना को रोका और स्पष्ट कह दिया, "अब कश्मीर भारत की भूमि है। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो सारे अंग्रेज अफसर पाकिस्तान छोड़कर विलायत लौट जाएँगे।" अंग्रेजों की सहायता के बिना जिन्ना एक दिन भी रहना नहीं चाहते थे। इसलिए डरकर हमला करने के हुक्म को उन्होंने वापस ले लिया। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सेक्रेटरी ऐलन केंपबेल लिखते हैं, "उन दिनों जिन्ना साहब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ विवाद करते रहे कि यह भारत का धोखा था।" माउंटबेटन यही कहते रहे कि कश्मीर के सम्मिलित होने के बाद उसकी रक्षा करना भारत का कर्तव्य था। पहले तो जिन्ना साहब ऐसा कुबूल करने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान की सहायता और नेतृत्व से ही कश्मीर पर यह हमला हुआ था, लेकिन माउंटबेटन ने जिन्ना को भारतीय वायु सेना और सैन्य की शक्ति का जब अंदाज दिया तब जिन्ना साहब ने सारे मामले निपटा देने का वायदा किया। उन दिनों कायदे आजम बड़े कमजोर हो रहे थे और घबराहट में शायद सच-गलत का भेद चूक जाते थे।

इस सारी लड़ाई में पाकिस्तानी हमलावरों की संख्या लगभग एक लाख तक पहुँच गई थी। उन कबाइलियों के सामने भारत सरकार कुल 16,000 सैनिकों को श्रीनगर भेज सकी थी। पाकिस्तानी सरकार चाहे कुछ भी खंडन करे, लेकिन भारत सरकार के पास प्रमाणभूत सबूत थे कि पाकिस्तान की मदद से ही कश्मीर पर आक्रमण हुआ था। वास्तव में जिन्ना साहब को

जिंदगी-भर की आदत थी-हर जगह दुराग्रह करके अपनी माँगों को बहुमती के मत्थे ठोकते जाना और कांग्रेस का नाजायज फायदा उठाना। जिन्ना साहब ने ही जूनागढ़ के मामले में यह प्रतिपादित किया था कि प्रजामत पूछने का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब कश्मीर महाराज ने इस सिद्धांत के अनुसार भारत में शामिल होने का निर्णय कर लिया तब पाकिस्तान से सहन नहीं हुआ और भारत के हस्तक्षेप का विरोध करने लगा। लेकिन जिन्ना साहब ने परोक्षरुप से स्वीकार कर लिया कि कश्मीर पर यह हमला पाकिस्तान की योजना थी जो भारत सरकार की स्फूर्ति से नाकाम हो गई। शायद उस समय कायदे आजम भूल गए थे कि कश्मीर के हमले के दायित्व के बारे में पाकिस्तान सरकार पहले तो साफ मुकर गई थी। उन दिनों के राजा हरिसिंह के साथ प्रजाजन और उनकी लोकप्रिय संस्था और गण्यमान्य नेता शेख अब्दुल्ला की पूर्ण सहमति पर ही कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। कश्मीर के नेताओं की स्पष्ट माँग पर ही कश्मीर घाटी के रक्षण के लिए इतनी मेहनत और भयानक खर्चा उठाकर भारत ने सैन्य साधन और जान-माल की हानि उठाई थी। शायद पाकिस्तान सरकार और दुनिया वाले इन तथ्यों को भूल जाते हैं, या फिर जानबूझकर भूल जाना पसंद करते हैं।

कश्मीर की इस लड़ाई ने अपना भोग लिया ही। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर उस्मान राजौरी और पुंछ का रक्षण करते हुए मारे गए। उस मुसलमान वीर को वफादारी और कर्तव्यपारायणता ही समझ आई थी। सांप्रदायिकता का उसे स्पर्श भी नहीं हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीरों ने इस राष्ट्र को बनाया है। उसी प्रकार नेशनल कॉन्फरेन्स के एक युवा नेता ने बारामूला के रक्षण में नगर निवासियों को संगठित किया और हमलावरों का सामना किया। दुर्भाग्य से मीर मकबूल शेरवानी दुश्मनों के हाथों में पड़ गए। उन लोगों ने उनसे पाकिस्तान की आजाद कश्मीर सरकार की वफादारी की कसम खाने को कहा, लेकिन शेरवानी ने अन्य किसी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कह दिया उन हमलावरों की जीत चार दिन की चाँदनी थी और दो दिन में भारतीय सेना उन लोगों को वहाँ से खदेड़ देगी। पाकिस्तानी हमलावरों ने उनको मार डाला। दुसरे ही दिन भारतीय सेना बारामूला पहुँच गई और मकबूल शेरवानी के कथन को पूरा कर दिखाया, लेकिन मीर मकबूल सदा के लिए कश्मीर से भी श्रेष्ठ स्वर्ग की राह चल दिए। अपनी प्रार्थना सभा में बापू जी ने मीर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ऐसे बलिदान से राष्ट्र बनता है। मीर की मृत्यु को हिंदू, सिख, मुसलमान सब सराहेंगे।

लार्ड माउंटबेटन के सुझाव पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख पाकिस्तान के विरुद्ध फरियाद दायर कर दी। पंडित जी को लगता होगा कि इस प्रकार यूनाइटेड नेशंस से न्याय की माँग करने से उस विश्व संस्था का महत्व बढ़ेगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपनी आस्था का ठोस परिचय दे पाएगा। अंत तक बापू जी और सरदार पटेल इस कदम का विरोध करते रहे। बापू जी को लगता था कि "कश्मीर तो दो भाइयों का आपसी मामला था। उसे आपसी समझौते से निपटाना चाहिए। दुनिया के सामने अपने वैमनस्य का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया वाले बंदर-बिल्ली का न्याय करेंगे और नुकसान पाकिस्तान और हिंदुस्तान का होगा। लेकिन उन दिनों नेहरू जी की भावुकता ने हमारे देश के घरेलू मामले को व्यर्थ में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। 30 दिसंबर, 1947 को यू.एन. की सिक्योरिटी काउंसिल के सम्मुख पाकिस्तान के विरोध में भारत ने फरियाद दर्ज कर दी। गुजरात में कहावत है कि **भले आदमी को कचहरी की सीढ़ियों पर पाँव नहीं रखना चाहिए अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती है।** ठीक वैसा ही हमारे देश का हुआ। कश्मीर के केस में दूसरों ने हम पर हमला किया, लेकिन अब हम और हमारा देश दुनिया की अदालत के कटघरे में अपराधी बने खड़े हैं। वर्षों पहले मैं अमरीकी विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। हमारे प्राध्यापक महोदय को भिन्न-भिन्न देशों के विद्यार्थियों में खुला वाद-विवाद का आयोजन करना बड़ा पसंद था। उन्होंने मुझे और पाकिस्तानी विद्यार्थी इस्लाम को कश्मीर पर बहस करने के लिए खड़ा कर दिया और लगभग चालीस विद्यार्थियों की कक्षा, हमारे तर्कों पर निर्णायक की तरह वाद-विवाद सुनती रही। मैंने बड़ी मेहनत से बिना कॉपी-किताब लिए कश्मीर का किस्सा आँकड़ों सहित सरल भाषा में पेश किया। इस्लाम ने पाकिस्तानी दूतावास से जो साहित्य मँगवाया था वह पढ़ दिया। मेरे संसारप्रसिद्ध प्रोफेसर डॉ. वेनवोकनवर्ग साहब और सारे गोरे विद्यार्थियों ने यही घोषित किया कि मिस गांधी अच्छा बोलती हैं इसलिए उसका वक्तव्य प्रभावशाली है, लेकिन पाकिस्तान सही है। मेरी तर्कपूर्ण चर्चा को वाक्पटुता कहकर खारिज कर दिया और इस्लाम के लंबे भाषण को सुनकर उन विद्यार्थियों ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। यह तो मामूली व्यक्तिगत अनुभव था, लेकिन आरंभ के पंद्रह-सोलह वर्षों में इन विदेशियों के पीछे भारत सरकार ने जो पैसा, समय, शक्ति और बुद्धि का व्यय किया था वह भयानक बरबादी थी। सदा के लिए कश्मीर के मामले में हम बेमतलब अभियुक्त बन गए हैं जबकि सत्य कुछ और ही है। नेहरू जी का उत्साहप्रेरित भोलापन कहें या बेवकूफी कहें, हमें बड़ी महँगी पड़ी है और आज तक हम उस गलती की सजा भुगत रहे हैं। बापू जी को इस सारे झमेले की बदनामी की कल्पना थी लेकिन नेहरू जी ने उनको अनसुना कर दिया। उनको लगता था कि विदेश नीति में बापू जी क्या समझेंगे? इसलिए बापू जी के प्रति इतना आदर-मान होते हुए भी नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को तरजीह दी और बापू जी को अनसुना कर दिया।

इस कश्मीर लड़ाई को लेकर अनेक लोगों ने बापू जी की अहिंसा की आस्था को ललकार दिया और

कहा कि दूसरे लोगों को उपदेश देने के लिए अहिंसा की बातें होती थीं। अपने देश के हित में बापू जी ने अहिंसा को छोड़कर शुद्ध हिंसा का समर्थन किया इसके जवाब में बापू जी ने कहा कि "अहिंसा में उनकी आस्था अविचल थी लेकिन अहिंसा तो हुक्म या दबाव से नहीं सिखाई जा सकती है। अपने सिद्धांत पर हिम्मत से खड़े रहने की ताकत पर आदमी की अहिंसा टिकती है।" अच्छा होता, अगर सारा श्रीनगर और नेशनल कॉन्फेरेन्स के नेता, कार्यकर्ता सब कश्मीर की रक्षा में अहिंसक सत्याग्रह में मीर मकबूल शेरवानी के समान काम आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए बापू जी न्याय और इनसाफी का पक्ष छोड़ देंगे, यह गलत हो जाता। बापू कहते थे कि उनकी अहिंसा कायरों की, कमजोरों की अहिंसा नहीं थी जो पहाड़ों की कंदराओं में छिपी रहे। बापू जी की अहिंसा तो रोज-रोज गली-कूचे-नुक्कड़ पर खटती है। उनकी अहिंसा सामाजिक क्रांति का अमोघ अस्त्र है जिसका हर घड़ी, हर स्थिति में उपयोग करना होता है।

जीवन में हमेशा तो अहिंसक साथी नहीं मिलते हैं लेकिन हर समस्या के दो पहलू होते हैं और उनमें से एक न्यायपूर्ण होता है। इस न्यायनीति को समर्थन देना समाजसेवी अहिंसक सत्याग्रही का कर्तव्य है। बापू जी की अहिंसा कर्तव्यशील पुरुषार्थ की अहिंसा थी। वह निष्क्रिय बनकर बच नहीं सकती है। आक्रमणकारी का प्रतिकार करना कर्तव्य होता है और आत्मकक्षा में शत्रु का निवारण करना यह परम धर्म है। अहिंसा के नाम पर हम कर्तव्यभ्रष्ट नहीं हो सकते। सत्य का साधक आलस्य या पिष्टपेषण में कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता है। अगर दुनिया के बाजार में अहिंसा टिक नहीं सकती है तो उसका कोई उपयोग ही नहीं रहेगा। वास्तविक अहिंसा बड़ी प्रखर होती है जो हर हालत में बड़ा कारगर प्रतिकार कर सकती है। अहिंसा की यह सफलता साधक की आस्था और निर्भीकता पर आधारित है। अहिंसा भीरु का मार्ग नहीं है। कश्मीर की जनता ने मदद माँगी और उस हालत में बापू जी ने सरकार की सैन्य सहायता का समर्थन किया। उन्हें स्पष्ट लगता था कि इस हमले में पाकिस्तान का सक्रिय योगदान और नेतृत्व था। ऐसी हालत में भारत सरकार अपने कर्तव्य से हट नहीं सकती थी। महाराजा कश्मीर और शेख अब्दुल्ला के सम्मिलित आग्रह पर ही भारत ने कश्मीर राज्य को देश में शामिल किया था। इसलिए कश्मीर का रक्षण करना भारत सरकार का धर्म था।

28 नवम्बर, 1947 को गुरु नानक जयंती थी। सिखों ने बहुत आग्रह से बापू जी को बुलाया था। बापू जी को कुछ शंका थी कि शायद सिख भाइयों को उनका अहिंसक मार्ग मान्य नहीं था। शायद बापू जी का सत्याग्रह का आदर्श उन सिखों को नापसंद होगा इसलिए वे इस कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन लोगों का बड़ा आग्रह था और उन्होंने ही बापू जी को बताया कि साथ-साथ शेख अब्दुल्ला भी भाषण करेंगे। बापू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंजाब की सांप्रदायिक अशांति के समय शेख अब्दुल्ला को कैसे सिख लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन भाषण के दिन सिखों की विशाल मेदिनी ने एकदम शांति से दत्तचित्त बापू जी और शेख साहब के भाषण सुने थे।

बापू जी का कहना था कि कश्मीर भारत देश के सांप्रदायिक समाधान का पैमाना था। अगर कश्मीर निवासी मुसलमान पूर्व पंजाब में, निरापद आ-जा नहीं सकेंगे तो भारत देश कश्मीर को कैसे रख पाएगा। उन दिनों किसी ने यह भी सुझाया कि जम्मू में हिंदूओं का बहुमत है, वह भारत को दे दिया जाए और कश्मीर पाकिस्तान को। बापू जी ने कहा, "एक विभाजन क्या कम था कि अब कश्मीर का भी विभाजन हो जाए? तब तो देश के गाँव-गाँव, गली-गली बाँटनी पड़ेगी। अगर कश्मीर के चालीस लाख मुस्लिम भारत में नहीं रह सकते तो भारत में बसने वाले चार करोड़ मुसलमान कहाँ जाएँगे? कौन-सा पाकिस्तान पाएँगे? इस तरह से तो समस्या का अंत नहीं होगा, इसलिए दोनों का साथ रहना परम आवश्यक था और आज भी है।

हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य रखना पड़ता है; उस हालत में अहिंसा का पालन कैसे होगा? इस विषय पर बापू जी काफी गहराई से सोच रहे थे। 18 जनवरी, 1948 का बापू जी ने सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा से चर्चा भी की। बापू जी और जनरल करिअप्पा के बीच इतनी अच्छी चर्चा हुई कि बापू जी ने उन्हें दुबारा आने के लिए कहा था लेकिन करिअप्पा 30 जनवरी तक कश्मीर कमांड का निरीक्षण करने गए थे। जब जनरल दिल्ली लौटे तो महात्मा जी की मृतक देह को पूरी वर्दी के साथ शानदार सलामी देने के सिवाय बापू जी के साथ चर्चा करने का मौका बीत चुका था।

बापू जी की बड़ी इच्छा थी कि वे जनरल करिअप्पा से सैन्य और अहिंसा के विषय पर गहराई से विचार-विनिमय करें लेकिन कुछ नासमझ लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी देश की ऐसी बुनियादी बातों पर चर्चा कर सकें। इस प्रकार वह अपूर्व घड़ी बीत गई जब भारतीय सेना का एक जनरल अहिंसा के पुजारी और सत्याग्रही के साथ सेना की नवरचना का मंगलाचरण करता। बापू जी की मृत्यु के बाद बेचारी सेना और अभागे देश को पुराने ढर्रे पर चलना ही नसीब था। मौलिक तरह से सोचने वाला एक आदमी भगवान के घर पहुँचा गया था। बहुत सालों बाद भारत सरकार ने जनरल करिअप्पा को फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया। लगता है अपनी सरकार को यथासमय काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन देर-सवेर जनरल करिअप्पा का सम्मान हुआ, यह उचित ही था।

महात्मा गाँधी मेरे पितामह - लेखिका श्रीमती - सुमित्रा गाँधी कुलकर्णी

महर्षि दयानन्द



सनेही प्रसाद
विद्युतकार

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के लिए जो विविध आंदोलन प्रारंभ हुए, उनमें आर्यसमाज का स्थान सर्वोपरि है। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद पुनर्जागरण की उस प्रवृत्ति के प्रतिनिधि थे जिसने अपनी प्रेरणा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से ग्रहण न कर प्राचीन शास्त्रों से प्राप्त की थी।



वस्तुतः स्वाधीनता-प्राप्ति का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू ही एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण से हुआ। भारत में सदियों के विदेशी शासन के कारण भारतीय संस्कृति और धर्म को बड़ा धक्का लगा। सांस्कृतिक मूल्यों की ओजस्विता जाती रही और उनका ह्रास होने लगा। लोगों में हीनता की भावना बढ़ने लगी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ही इस दुर्दशा का उपचार था। राजनीतिक आंदोलन से पहले उसे आना ही था, क्योंकि उसी के आधार पर किसी ऐसे राजनीतिक आंदोलन की इमारत खड़ी की जा सकती थी, जिसके लिए निष्ठा, साहस तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इस महान सांस्कृतिक आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले नेताओं में स्वामी दयानंद प्रमुख थे। अपने प्रचंड आंदोलन के फलस्वरूप वे एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए थे। लोग उन्हें एक महान समाज-सुधारक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पथ-प्रदर्शक मानते हैं। परंतु वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सुत्रधार भी थे। इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए।

महर्षि दयानंद ने अपने प्रमुख ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' में जिस प्रकार राजनीति की चर्चा, देश के लिए स्वराज्य, साम्राज्य और अखंड सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य को प्रस्तुत किया है, उसे पढ़कर स्तंभित होना पड़ता है। उनका कोरा कर्मकांडी संप्रदाय नहीं था। वे राजधर्म के उपासक थे। उनका धर्म व्यक्ति के लिए है और व्यक्तियों की इकाई के बाद जब समष्टि का प्रश्न उपस्थित होता है तब वे उस राजधर्म का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी पहली संख्या स्वराज्य है और उससे अगली है अखंड सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य। उनकी यह कल्पना और भावना उनके समस्त साहित्य और जीवन में ओतप्रोत है। साम्राज्यवाद की प्रथम सीढ़ी राष्ट्रवाद है। इसी से ऋषि दयानंद ने अपने देश के लिए अखंड सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की कल्पना की थी। उनकी स्वराज्य-कल्पना कितनी सुंदर, उत्कृष्ट और विशुद्ध है, यह उनके लेखों से स्पष्ट है।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने देश का आहवान करते समय अपने समाज की जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित

किया है और समाज के जिन क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य के द्वारा गति प्रदान करने की चेष्टा की है, उन सभी समस्याओं को स्वामी दयानंद ने बहुत बल देकर सामने रखा था और सभी क्षेत्रों में कार्य करना आरंभ कर दिया था। वे कार्य-समानता, अस्पृश्यता-निवारण, नारी-उत्थान, स्वदेशीयता और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। उत्तर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दशकों के दौरान हिंदुओं की अधिकांश संख्या स्वामी जी और आर्यसमाज की बड़ी ही प्रशंसक थी। इसका कारण वह महान सांस्कृतिक और समाज-सुधार आंदोलन ही था जिसे स्वामीजी ने आरंभ किया था। उनके जीवन के इस पहलू ने उन्हें एक महान राष्ट्रीय विभूति का रूप दिया। अतएवं वे स्वराज्य के पथगामियों में सर्वप्रमुख स्थान के अधिकारी हैं।

ऐसे महान ऋषी एवं राष्ट्र-निर्माता का जन्म 1824 ई. में काठियावाड़ प्रांत में मौरवी राज्य के अंतर्गत टंकारा नगर में राजमहल के निकट जीवापुर मुहल्ले में हुआ था। महर्षी दयानंद की समस्त बाल्यावस्था-संबंधी सूचना का मूलाधार स्वकथित वृत्त ही है। आर्यसमाज के इतिहास लेखक पं. इंद्र विद्यावाचस्पति लिखते हैं, "दयानंद के चित्त में जो-जो विचार-तरंगे उत्पन्न हुईं, जो-जो क्रांतियाँ खड़ी हुईं, वे आकस्मिक नहीं थी, परंतु हमें यह मान लेना चाहिए कि उनके कारणों पर पूरा प्रकाश डालने के साधनों का अभाव है। हम नहीं जानते कि मूलशंकर के प्रारंभिक गुरु कौन थे और न हमें निश्चयपूर्वक यही ज्ञात है कि उसके खेल के साथी किस श्रेणी के थे। यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि दयानंद में जो दृढ़ता और निर्भयता थी, वह माता की ओर से प्राप्त हुई थी या पिता की ओर से।"

स्वामी दयानंद का पितृदत्त नाम मूलशंकर पिता के धार्मिक विचारों को देखते हुए सर्वथा उचित था, क्योंकि पिता कर्षन जी शैव मतानुयायी और शंकर के विशेष भक्त थे। 'मूलशंकर' भी शिव की अगाध भक्ति का प्रदर्शक है। श्री कर्षन जी संस्कृतविद्या-प्रेमी थे तथा उनके परिवार में वेदपाठ बहुत होता था। यही कारण था कि उन्होंने अपने पुत्र मूलशंकर को भी वेदपाठ कराया था। बालक मूलशंकर की स्मरणशक्ति बहुत तीव्र थी, अत: पाँच वर्ष की अवस्था से पूर्व ही उसने अक्षरबोध प्राप्त कर लिया और उसे अनेक वेदमंत्र कंठस्थ हो गए थे। आठवें वर्ष उसका उपनयन संस्कार हुआ और वह नियमानुसार वेद पढ़ने लगे। 14 वर्ष की अवस्था तक वह व्याकरण और संपूर्ण यजुर्वेद पढ़ चुका थे। पिता की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका पुत्र भी उनके समान शिव का भक्त बने। इसलिए उनका सर्वदा यही अनुरोध रहा करता था कि मूलशंकर को नियमानुसार शिव-पूजन, शिव-व्रत तथा शिव-कथा-श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। अत: उसके अंत:करण में भी संस्कारों का बीजारोपण किया गया।

अमरत्व के पिपासु मूलशंकर ने प्रेममय घर को लात मारकर 22 वर्ष की आयु में वन का रास्ता लिया। 15 वर्ष पर्यंत वे लगभग समस्त भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में ज्ञान और सत्य की खोज में भटकते फिरे। भ्रमण करते हुए उन्होंने मथुरा के दण्डी स्वामी विरजानंद का यश सुना। यह समाचार सुनते ही उन्होंने मथुरा की ओर प्रस्थान किया और 14 नवम्बर, 1860 के दिन मथुरा में स्वामी विरजानंद का द्वार खटखटाया।

प्रज्ञाचक्षु होने पर भी दण्डी स्वामी को दयानंद की प्रतिभा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दयानंद ने अपार श्रद्धा के साथ उनसे तीन वर्ष तक विद्या ग्रहण की। इन तीन वर्षों में दण्डी स्वामी विरजानंद के चरणों में बैठकर निरंतर गंभीर अध्ययन द्वारा उन्होंने उस सत्य ज्ञान की प्राप्ति की, जो कि निरंतर भ्रमण से उन्हें उपलब्ध न हुआ था। दण्डी जी से उन्होंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि व्याकरण ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य आर्ष ग्रंथों का भी अध्ययन किया। प्रतिमा-पूजन का विरोध, अनार्ष ग्रंथों की उपेक्षा आदि के लिए दयानंद गुरु विरजानंद के आभारी थे। वैदिक साहित्य के अध्ययन में उन्हें प्रतिमा-पूजन, अवतारवाद आदि बातें मित्था प्रतीत हुईं। विद्याध्ययन समाप्त होने पर उनके पास गुरुदक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। कहीं से कुछ लौंग लेकर वे गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। उस समय दण्डी जी ने कहा, "देश का उपकार करो। सत्शास्त्रों का उद्धार करो। मत-मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म फैलाओ।" दयानंद ने इस आदेश को अंगीकार किया। इस अमूल्य उपदेश को शिरोधार्थ करके दयानंद गुरु के द्वार से विदा हुए।

गुरु का उपदेश शिरोधार्थ करके स्वामी दयानंद ने तात्कालीन भारत में फैले **पाखंड, अविद्या और अंधविश्वासों पर प्रबल आक्रमण किया।** उस समय हिंदू धर्म अत्यंत विकृत हो चुका था। सैकड़ों मत-मतांतर चल रहे थे। प्राचीन चार वर्णों का स्थान दूषित जात-पाँत ने ले रखा था। नारी, शुद्र और अछूत ये मानो मनुष्य ही नहीं थे। ईसाई और इस्लाम धर्म जीर्ण-शीर्ण हिंदू धर्म पर नवोन्मेष के साथ आक्रमण कर रहे थे। डॉ. गोकुलचंद नारंग के शब्दों में, "वह समय ऐसा था जब कि ईसाई और मुसलमान हिंदुओं पर निरंतर घृणित आक्रमण करके हिंदुओं के देवी-देवताओं आदि की भरपेट निंदा करते थे। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद धर्म-प्रचारार्थ निकले। उन्होंने सदियों से प्रचालित अंधविश्वासों और रूढ़ियों के खंडन का बीड़ा उठाया जिसके लिए उन्हें चहुँमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी। गुरु के आदेशानुसार उन्हें-अविद्याग्रस्त मत-मतांतरों का हटाना, मूर्ति-पूजा-खंडन, मनुष्यकृत ग्रंथों के स्थान पर आर्ष ग्रंथों का प्रचार, सत्य विद्याओं तथा आदि पुस्तक वेद की स्थापना करना और समाज में प्रचलित बुराइयों और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों का नाश करना था।

1857 की क्रांति के समय स्वामी दयानंद की आयु 33 वर्ष के लगभग थी। विदेशियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आक्रमण को निरस्त करने के लिए, पुरुषसिंह दयानंद रणक्षेत्र में कुद पड़े। 1855 में हरिद्वार में विशाल कुंभ मेला लगा। सन्यासी-गृहस्थी,

राजा-रंक सभी इस मेले में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार पहुँच रहे थे। अंग्रेजों के अत्याचार के कारण निर्धनों की जीर्ण-शीर्ण कुटियों से लेकर राजमहालों तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। महर्षी दयानंद इस चिंगारी को दावानल में बदल देने का कार्यक्रम बनाकर पैदल ही आबू पर्वत से दिल्ली होते हुए हरिद्वार जा पहुँचे और गंगा पार चण्डी पहाड़ के एकांत स्थल में अपना डेरा जमाया। **प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानी नाना साहब पेशवा, बाला साहब, अजीमुल्ला खाँ, ताँत्या टोपे, कुँवरसिंह, महारानी लक्ष्मीबाई तथा अनेक प्रमुख नेता वहीं पर ऋषि से मिले। ऋषि दयानंद ने इन सभी को क्रांति का विचार, प्रेरणा तथा कार्यक्रम दिया।**

इसके बाद कुछ समय तक आगरा, अजमेर आदि में प्रचार करके स्वामी जी ने 1867 ई. के अप्रैल मास में कुंभ के अवसर पर हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य अपनी पाखंड-खंडनी पताका स्थापित की। यह प्रथम अवसर था जब स्वामी जी ने एक विशाल जनसमूह के सम्मुख हिंदू समाज में प्रचलित अनाचारों और बुराइयों का खंडन करके वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया। तत्पश्चात् स्वामी जी ने विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों से काशी, प्रयाग, अजमेर आदि अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ किए, जिससे उनका यश चतुर्दिक व्याप्त हो गया।

प्रचार-कार्य करते-करते 1872 ई. के दिसंबर मास, में स्वामी जी भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता पहुँचे। वहाँ के लाट पादरी ने महर्षि की भेंट भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड नार्थब्रुक से करवाई। लार्ड नार्थब्रुक ने स्वामी दयानंद से वार्तालाप के समय यह प्रस्ताव रखा कि आप अपने प्रवचनों में अखंड अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना किया करें। स्वामी जी ने निर्भयता से लार्ड नार्थ कुक को दो टूक उत्तर दिया कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करना तो दूर रहा, मैं तो सदैव ही भारत की स्वतंत्रता और अंग्रेजी राज्य के नाश के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। वह वार्ता वहीं भंग हो गई।

कलकत्ता में स्वामी जी ने अपने युग धर्म क्षेत्र के अन्य तीन प्रमुख भारतीय महापुरुषों-रामकृष्ण परमहंस, देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचंद्र सेन से भेंट की। केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रम्हसमाज ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपने कार्य में सहयोग की आशा से उनकी ओर भ्रातृत्व का हाथ बढ़ाया।

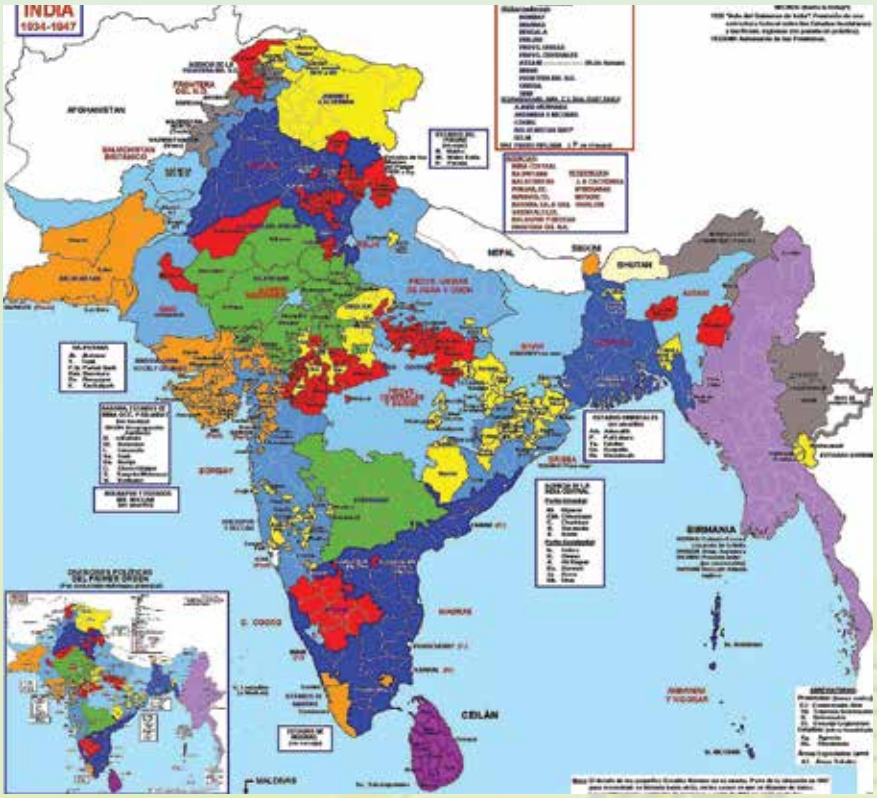
ब्रम्हसमाज का संगठन देखने के पश्चात स्वामी दयानंद के मस्तिष्क में विचार आया कि कोई ऐसा संगठन बना दिया जाए जो उनके द्वारा प्रतिपादित वैदिक सिद्धांतों का प्रचार करे और उनके पश्चात भी कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। उनका यह विचार उनके अंतस्तल में से बाहर आकर अब स्थूल रूप में मूर्तिमान होने के लिए अवसर ढूँढ़ रहा था। अंत में वह सुअवसर भी आ पहुँचा और दो वर्ष बाद बंबई में 10 अप्रैल, 1875 के दिन अपने सबसे महान् स्मारक 'आर्यसमाज' की नींव डालकर उन्होंने उस धर्मवेदी की प्रस्थापना कर दी, जिससे कि आज सब कोई परिचित है। उस समय ऐसी ही एक संस्था की आवश्यकता थी, जो अंधाविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर एवं प्रचलित धार्मिक अनाचरों से मुक्त हो, जो राष्ट्र को एक सूत्र में बाँध सके और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार कर सके। स्वामी जी ने आर्यसमाज की स्थापना कर इस कमी को पूरा कर दिया।

स्वामी जी द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' और वेद की व्याख्या में भी स्थान-स्थान पर पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की चर्चाएँ लिखी मिलती हैं। "प्रभो, हमारे देश में कभी विदेशी राजा का राज न रहे" - इस तरह की प्रार्थनाएँ भी उपासना मंत्रों में स्वामी जी ने सम्मिलित कीं। "कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। ... प्रजा पर पिता के समान कृपा, न्याय एवं दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं हैं" स्वामी जी ने 'सत्यार्थप्रकाश' में यह शंखनाद उस समय किया था, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्यशाही की जड़ें पाताल तक पहुँच चुकी थीं।

'सत्यार्थप्रकाश' की निर्माण-योजना 1863 ई. से आरंभ हो चुकी थी। उस समय भारत में विदेशी सरकार का भारी आतंक छाया हुआ था। आर्य (हिंदू) जाति पूरी तरह निराश हो चुकी थी। भारत की आत्मा मानो सो चुकी थी। समाज कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के वशीभूत होकर जर्जरित हो चुका था। कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। एक दिव्य द्रष्टा महर्षि ने, जो आर्यावर्त्त के प्राचीन ऋषि-मुनियों का उत्कृष्टतम प्रतिनिधि था, आर्य जाति को हिलोरे दे-देकर उस समय जगाना आरंभ किया और उसका आधार ग्रंथ बना 'सत्यार्थप्रकाश'।

भारत को स्वतंत्र करने के लिए धधकती ज्वाला हृदय में रखने वाले युगपुरुष ने अपने अमर ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' में आर्यों के चक्रवर्ती राज्य की याद देशवासियों को दिलाई और उनमें नई चेतना भरने के लिए लिखा, "सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती, सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे, अब इनके संतानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रांत हो रहे हैं।

वस्तुत: स्वराज्य और स्वदेशी की ऐसी लहर महर्षि दयानंद ने चलाई जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कांग्रेस आंदोलन में तीव्रता तब आई जब 'सत्यार्थप्रकाश' की 'स्वराज्य-भावना' से प्रेरणा पाने वाले श्री गोविंद रानाडे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, पं. श्याम जी कृष्ण वर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपतराय, भाई परमानंद, पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद भगतसिंह जैसे महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।



1857 का नक्शा

गाय का प्रश्न भी 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख आधार बना। उस समय जो कारतूस बंदूकों में लगते थे, उनमें गाय की चर्बी का भी प्रयोग होता था। बंदूक भरने के पूर्व सिपाहियों को कारतूस का खोल मुँह से तोड़ना पड़ता था। जब सिपाहियों को यह पता लगा कि इसमें गाय की चर्बी लगती है तो उनकी धार्मिक भावना का भड़क उठना स्वाभाविक था। कई स्थानों पर तो सिपाहियों ने इसका स्पष्ट विरोध भी किया, पर उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। सिपाहियों को हथियार उठानें में गाय के प्रति श्रद्धाभाव ने भी उस समय आग में घी का काम किया। स्वामी जी की दृष्टि भी उस ओर गई। नीति के नाते नैतिक दृष्टि से भी उन्होंने उस महत्वपूर्ण प्रश्न को खूब उभारा। स्वामी जी ने 1857 के बाद गाय की उपयोगिता पर ही एक पुस्तक 'गोकरुणानिधि' लिखी। इसमें एक स्थान पर तो यहाँ तक स्वामी जी ने लिख दिया, "जो गाय के रक्षक नहीं हैं, भक्षक हैं, वे म्लेच्छ हैं। भारत की पुण्यभूमि में एक क्षण भी म्लेच्छों को रहने का अधिकार नहीं हैं।" महारानी विक्टोरिया को गोवध बंद कराने के लिए एक स्मृति-पत्र भी उन्होंने उन्हीं दिनों भिजवाया था। संपूर्ण देश से दो करोड़ हस्ताक्षर इस पर कराने का अभियान चलाया गया। इस तरह स्वतंत्रता की तड़प उत्पन्न करने में जो भी कारण सहायक बन सकते थे, उन सबका ही स्वामी जी ने प्रयोग किया।

गुजरात में उत्पन्न होने के कारण महर्षि की मातृभाषा गुजराती थी। उनकी शिक्षा-दीक्षा सारी संस्कृत में हुई, पर उन्होंने अपने भाषणों और ग्रंथों का माध्यम हिंदी को बनाया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और हिंदी भाषा का प्रचार करने को कहा। साथ ही ज्ञान-वृद्धि के लिए किसी भी भारतीय मूल की आंचलिक भाषा के सीखने के वे विरूद्ध नहीं थे। किंतु जब उनका पदार्पण भारतीय सार्वजनिक रंगमंच पर हुआ तो भारत में राजनीति एवं राष्ट्रीय एकता को बाँधने वाला कोई सूत्र नहीं था। तब उन्होंने साहस के साथ एक निर्णय लिया कि आरंभ में बोलचाल के लिए टूटी-फूटी हिंदी ही चलेगी, किंतु देवनागरी में हिंदी भारती (आर्य भाषा) में ही अपने ग्रंथ लिखूँगा। हिंदी के लिए उनका यह संकल्प एक नींव का पत्थर सिद्ध हुआ।

स्वामी जी भली भाँति जानते थे कि हिंदी के द्वारा देश को जगाने में सरलता रहेगी। एक बार स्वामी जी की अंग्रेजी से अनभिज्ञता पर खेद प्रकट करते हुए ब्रम्हसमाज के नेता श्री केशवचंद्र सेन ने कहा, "महाराज, आपने एक बहुत बड़ी भूल की जो अंग्रेजी नहीं पढ़ी। यदि आप अंग्रेजी जानते तो वेदों का संदेश अमरीका, इंग्लैड और जर्मनी में भी जाकर देते।" इस पर स्वामी जी ने हँसकर कहा, "केशव बाबू, एक भूल आपसे भी हुई। आपने संस्कृत नहीं पढ़ी। यदि आप संस्कृत जानते तो एक और एक ग्यारह पहले हम दोनों मिलकर अपने घर का सुधार करते, बाद में समय रहता तो बाहर भी चलते।" स्वामी जी का विचार था, पराधीन देश के रहने वाले क्या संसार की आँखे खोलेंगे! उदयपुर के अपने एक भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए समग्र देश में एक भाषा का होना भी बहुत आवश्यक था। स्पष्ट है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के बावजूद स्वतंत्रता का संघर्ष रुका नहीं। ऋषि दयानंद देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के लिए वेद-प्रचार के माध्यम से नवीन उत्साह व साहस से पुनः जुट गए। उन्होंने स्वयं श्याम जी कृष्ण वर्मा को विदेश भेजकर क्रांति की अग्निशिखा को प्रज्वलित रखने की प्रेरणा दी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है, "मैंने आर्यसमाज, शाहजहाँपुर के उत्सव में एक आर्य संन्यासी के मुख से यह सुना कि भाई परमानंद को फाँसी दी जाएगी। मैने उसी समय अपने मन में फैसला कर लिया-जब तक मैं भी उसके बदले में दस अंग्रेजों को मौत के घाट नहीं उतार दूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा।" श्री

बिस्मिल ने वहाँ लिखा है कि मेरे क्रांतिकारी जीवन के प्रारंभ की यहीं से बुनियाद पड़ी। उसके बाद ही मैंने रिवॉल्वर चलाने और निशाना लगाने की ट्रेनिंग ली। क्रांतिकारी वीर सावरकर ने स्वामी जी को विदेशीपन से देश को सावधान करने के कारण मानसिक दासता से मुक्त करने वाले कायाकल्प का जनक कहा है।

अंग्रेज गुप्तचर ऋषि दयानंद के पीछे लगे हुए थे। गुप्तचर से पता लगा कि यह साधु धर्म-प्रचार की आड़ में फिर से देश को एक नई क्रांति के लिए तैयार कर रहा है। अंग्रेजों ने जोधपुर दरबार से इसके लिए कुछ गुप्त पत्र-व्यवहार भी उन्ही दिनों किया। अभी तक वे सब बातें तो पूरी तरह सामने नहीं आ सकीं, पर स्वामी जी की असामायिक मृत्यु में अंग्रेजों का भी निश्चित हाथ बताया जाता है। जोधपुर में उनको विष देने के बाद आबू में वे अपनी चिकित्सा करवा रहे थे तब ही कुछ डॉक्टरों के माध्यम से यह सब षड्यंत्र किया गया। फलस्वरूप 30 अक्तूबर, 1883 ई. को आधुनिक जागृत भारत के महर्षि दयानंद का देहावसान हो गया।

स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात आर्यसमाज को भी अंग्रेजों ने सशंकित दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में गुप्तचर भेजे जाने लगे। वहाँ क्या उपदेश होते हैं और क्या चर्चाएँ होती हैं इसकी रिपोर्ट जाने लगी। उधर आर्यसमाज के नेताओं ने खुलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए बीड़ा उठा लिया। लाला लाजपतराय को जब काले पानी की सजा हुई और उन्हें मांडले जेल भेजा जाने लगा तब सरकार ने आर्यसमाज के साथ लाहौर डी. ए. वी कॉलेज कमेटी के सदस्यों पर भी कड़ी दृष्टि रखनी प्रारंभ कर दी। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल काँगड़ी को भी अंग्रेज मुक्ति संग्राम का प्रशिक्षण केंद्र मानने लगे।

ऋषि दयानंद की मृत्यु के पश्चात अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपतराय, रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगतसिंह आदि ऋषि के मानस-पुत्र स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुतियाँ देते रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में भी ऋषि के शिष्यों की संख्या कम नहीं थी। ऋषि द्वारा प्रज्वलित यह क्रांति की ज्वाला बुझी नहीं और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ठीक नब्बे वर्ष पश्चात 15 अगस्त, 1947 को एक लंबे व अनथक संघर्ष के बाद शताब्दियों की पराधीनता से देश स्वतंत्र हुआ।

भारतीय संस्कृति की महानता



रिजवान बसरी
कार्यालय अधिक्षक

मार्टिन लूथर किंग भारतीय संस्कृति एवं गांधीवाद से बेहद प्रभावित थे। शांति स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार 'नोबल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था। नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने के कुछ समय बाद वे भारत की यात्रा पर आए । राष्ट्रपति भवन में उनके अभिनंदन समारोह में मिस्त्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी उपस्थित थीं।

अभिनंदन समारोह के बाद अनेक विषयों पर चर्चा चलती रही। देश-विदेश से अनेक पत्रकार आए हुए थे, जो अनेक तरह के प्रश्न कर रहे थे। तभी एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, "आपको शांति प्रयासों के लिए विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से आपने पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको शांति स्थापित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?" इस पर मार्टिन लूथर मुस्कुराकर बोले, "भारत देश से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। मुझे भारतीय सिद्धांतों व गांधीजी ने अत्यधिक प्रभावित किया। गांधीजी की अहिंसक नीति और उनके कार्य करने के तरीके ने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इस पर पत्रकार बोला, भारत के सिद्धांतों व गांधीजी के प्रति आपका लगाव कैसे उत्पन्न हुआ?" विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आपका क्या सुझाव है? मार्टिन लूथर किंग फिर मुस्कुराए और बोले, "मैंने अपने देश के अति भौतिकवादी माहौल के दुष्परिणामों को देखने के बाद 'गीता' तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। इसने मुझे बेहद प्रभावित किया। मैंने अनुभव किया कि भारतीय दर्शन ही मावनतावाद; सेवा व शांति की प्रेरणा देने में सक्षम है। गांधीजी के बताए सत्य-अहिंसा के मार्ग से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। मैंने इस प्रयोग को कसौटी पर कसा और सही पाया। उनके जवाब को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी शीर्षस्थ नेता उनकी भारतीय दर्शन और गांधी में अटूट निष्ठा तथा विश्वास देखकर भावविभोर हो गए। गांधी के प्रति एक विदेशी का प्रेम देखकर सभी जान गए कि गांधीजी ने अपने महान कार्यों से पूरे विश्व में अहिंसात्मक नीति और भारतीय संस्कृति को स्थापित किया है।



राकेश कुमार
वरिष्ठ रशियन अनुवादक



हताशा

कोई नहीं जानता कौन है वो।
वो किनारे पर बैठा एक अनजान सा मुसाफिर,
जाने क्या है सोच रहा,
टकटकी लगाए समुद्र में।
क्या वो चाहता है खोना
उसकी गहराइयों में
या फिर नाप कर उसकी सहनशीलता,
फिर से चाहता है उठना
और बनाना चाहता है अपनी पहचान।
कोई नहीं जानता कौन है वो,
वो किनारे पर बैठा, एक अनजान सा मुसाफिर
जाने क्या है सोच रहा,
टकटकी लगाए समुद्र में।

क्यो वो आशा भरी नज़रों से है देख रहा,
क्या वह चाहता है करना, तुलना
उसकी लहरों की शक्तियों को अपनी शक्तियों से,
क्या वह इसी से लेकर सीख
फिर से चाहता है चलना
और छूना चाहता है नई ऊँचाईयों को,
कि वो कमजोर नहीं,
मुझमें भी है शक्ति,
वक्त को बदलने की।

मैं भी जानता हूँ इसकी कीमत
और समुद्र से लेकर सीख
चाहता हूँ उसकी सहनशीलता
और उसकी गहराईयों को जीवन में उतारना।
कोई नहीं जानता कौन है वो
वो किनारे पर बैठा, एक अनजान सा मुसाफिर,
जाने क्या है सोच रहा,
टकटकी लगाए समुद्र में।

या फिर है वो एक हारा हुआ इन्सान,
जो हार कर दुनिया से क्षुब्ध होकर, थक कर,
यूँ ही समुद्र को है नाप रहा है।
और उसकी प्रत्येक हलचल को अपनी असफलताओं से,
मिलाने की कोशिश कर रहा है और उदास हो रहा है।
कोई नहीं जानता कौन है वो,
वो किनारे पर बैठा, एक अनजान सा मुसाफिर,
जाने क्या है सोच रहा,
टकटकी लगाए समुद्र में।

या फिर क्या है वो एक इन्सान,
जिसे दुनिया पागल कहती है।
क्या यही सोचकर वो यहाँ बैठा है,
कि तिरस्कार और डर से बेहतर मर जाना ही अच्छा है,
इसी में मिलेगी शांति और लहरों के साथ,
बह जाना ही अच्छा है
कोई नहीं जानता कौन है वो,
वो किनारे पर बैठा, एक अनजान सा मुसाफिर,
जाने क्या सोच रहा,
टकटकी लगाए समुद्र में।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

आईएनएस खंडेरी का जलावतरण



खंडेरी के जलावतरण के अवसर पर स्वागत भाषण देते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर राकेश आनन्द



जलावतरण के अवसर पर सम्बोधन करते हुए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल सुनील लान्बा



जलावतरण के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. सुभाष भामरे, रक्षा राज्य मंत्री एवं श्रीमती वीणा भामरे



आईएनएस खंडेरी (एमडीएल यार्ड 11876) का जलावतरण

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

हमारे सम्मानीय अतिथिगण



नेवल वार कालेज के प्रतिनिधियों का एमडीएल दौरा, कमोडोर एन के देसाई के साथ प्रतिनिधियों का सामूहिक चित्र



नेवल वार कालेज के प्रतिनिधि को मोमेंटों प्रदान करते हुए कमोडोर राकेश आनन्द, नि(सयो एवं का) के साथ श्री पी एस शेनवाई, अमप्र(पी17 ए)



श्री सतवीर सिंह (भारत के अलजीरिया, में राजदूत) एमडीएल दौरे पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से हाथ मिलाते हुए



श्री सतवीर सिंह (भारत के अलजीरिया, में राजदूत) को मोमेंटों प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर राकेश आनन्द के साथ अन्य निदेशकगण



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ विचार-विमर्श करते हुए रियर एडमिरल सुरिंदर आहुजा एसीडब्ल्यूपी एवं ए.



रियर एडमिरल सुरिंदर आहुजा एसीडब्ल्यूपी एवं ए को एमडीएल मोमेंटों प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कमोडोर राकेश आनन्द

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ



चीफ़ रसियन नेवी एडमिरल व्लादिमीर कोसोलेव के साथ अप्रनि कमोडोर राकेश आनन्द



चीफ़ रसियन नेवी एडमिरल व्लादिमीर कोसोलेव का एमडीएल दौरा पर मोमेंटों से प्रदान करते हुए अप्रनि कमोडोर राकेश आनन्द

उत्पादकता सप्ताह



सतर्कता सप्ताह के उद्घाटन पर दीप प्रज्वलित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सतर्कता सप्ताह के अवसर पर उपस्थित सीएमडी एवं निदेशकगण



सतर्कता सप्ताह में शपथ लेते हुए कमोडोर राकेश आनन्द, नि(सयो एवं का), श्री सतीश पेंढारकर, मुसअ, सीएमडी एवं अन्य अधिकारी



सतर्कता विभाग की पत्रिका 'सुचारिता' का विमोचन करते हुए सीएमडी, निदेशकगण एवं विभाग के अधिकारी

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

उत्पादकता सप्ताह



उत्पादकता सप्ताह कार्यक्रम में कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ) का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए श्री जय प्रकाश यादव, मुप्र (स.यो)



उत्पादकता सप्ताह कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

सुरक्षा सप्ताह



सीएमडी का स्वागत करते श्री एचएम हरयानी महाप्रबंधक (वाणिज्य)



नि(पन एवं भा.अ) कैप्टन राजीव लठ का स्वागत करते श्री एच वी कारेकर, का.नि. (सेवाएं-पूर्व खंड)



संरक्षा सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमडी कमोडोर राकेश आनंद

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

68 वां गणतंत्र दिवस समारोह



26 जनवरी, 2017 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झण्डा फहराते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कमोडोर राकेश आनन्द



गणतंत्र दिवस पर एमडीएल परिवार को संबोधित करते हुए सीएमडी



26 जनवरी, 2017 को गणतंत्र दिवस पर सीआईएफएस की परेड का अवलोकन करते हुए सीएमडी



26 जनवरी, 2017 को गणतंत्र दिवस पर अग्रनि के साथ नि(पन एवं भा.अ), मुसअ एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

बेस्ट प्रैक्टिस कार्यशाला



कार्यशाला में उपस्थित श्री संजीव शर्मा, नि(वित्त), कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ), एवं अन्य अधिकारी



बेस्ट प्रैक्टिस पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ)

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम एवं विप्स सदस्यों का वृद्धाश्रम दौरा



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दीप प्रज्वलित करती हुई श्रीमती रुचि आनन्द



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित महिलागण



दिनांक 21 जनवरी, 2017 को वीप्स की महिलाओं का वृद्धाश्रम दौरा



डॉ. कोली, वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धा का हाल-चाल पूछते हुए

कमोडोर राकेश आनन्द का सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण



30 दिसंबर, 2016 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रुप में कार्यभार ग्रहण करते हुए कमोडोर राकेश आनन्द



कार्यभार ग्रहण के दौरान खड़े निदेशकगण

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ



01 जनवरी, 2017 को एमडीएल के अप्रनि का पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ से स्वागत करते श्री डी मोकाशी एवं श्री उदय तलवलकर

एमडीएल शिशु सदन का उद्घाटन



एमडीएल शिशु सदन उद्घाटन के समय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए कमोडोर राकेश आनन्द नि(सयो एवं का)



एमडीएल शिशु सदन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ उपस्थित निदेशकगण एवं अधिकारीगण



एमडीएल शिशु सदन का रिब्बन काटते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ कमोडोर राकेश आनन्द नि(सयो एवं का) एवं सुश्री वंदना एवं उनकी बेटी

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

एमडीएल में सप्लायर मीट, वेंडर मीट एवं बेस्ट प्रैक्टिस कार्यक्रम



एमडीएल सप्लायर मीट कार्यक्रम में श्री एस पेंढारकर, सीवीओ सम्बोधित करते हुए।



एमडीएल सप्लायर मीट कार्यक्रम में उपस्थित आपूर्तिकर्ता और अधिकारीगण



वेंडर मीट कार्यक्रम में वेंडरों को संबोधित करते हुए एमडीएल के अप्रनि कमोडोर राकेश आनन्द



वेंडर मीट कार्यक्रम में उपस्थित वेंडर्स



एमडीआरसी क्लब में विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन



एमडीआरसी क्लब में विक्रेताओं के साथ निदेशक एवं अधिकारी

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ



एमडीएल की नई वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर बाएँ से खड़े श्री जी जी अग्रवाल, कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ), कमांडर पी आर रघुनाथ, नि(जनि), रि ए आर के श्रावत, अप्रनि, कमोडोर राकेश आनन्द नि(सयो एवं का), श्री एस पेंढारकर, सीवीओ, सुश्री कविता एवं श्री किरण बने।

एमडीएल क्रिकेट मैच



वित्त विभाग के द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में विजेता टीम को ट्रॉफी देते हुए श्री संजीव शर्मा, नि(वित्त)



क्रिकेट मैच में दोनों टीमों के साथ श्री संजीव शर्मा, नि(वित्त) एवं अन्य अधिकारीगण

जागतिक मराठी राजभाषा दिवस



एमडीएल में मराठी दिवस का आयोजन



मराठी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में पुरस्कार प्राप्त किए हुए प्रतिभागीगण

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में कार्यक्रमों की झलकियाँ

शिव जयंती समारोह और सत्यनारायन महापूजा



शिव जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए श्री संजीव शर्मा, नि(वित्त) के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण



शिव जयंती के अवसर पर बैठे हुए श्री संजीव शर्मा निदेशक(वि) के साथ अधिकारी एवं कर्मचारीगण



दिनांक 3 दिसंबर, 2016 को एमडीएल परिसर में आयोजित सत्यनारायण महापूजा में पूजा करते हुए राकेश आनन्द, नि(सयो एवं का)



सत्यनारायण महापूजा में उपस्थित अप्रनि रिए. आर के श्रावत, कैप्टन राजीव लठ, नि(पन एवं भा.अ) के साथ अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण

एमडीएल में कैंसर डीटेक्शन कैंप का आयोजन



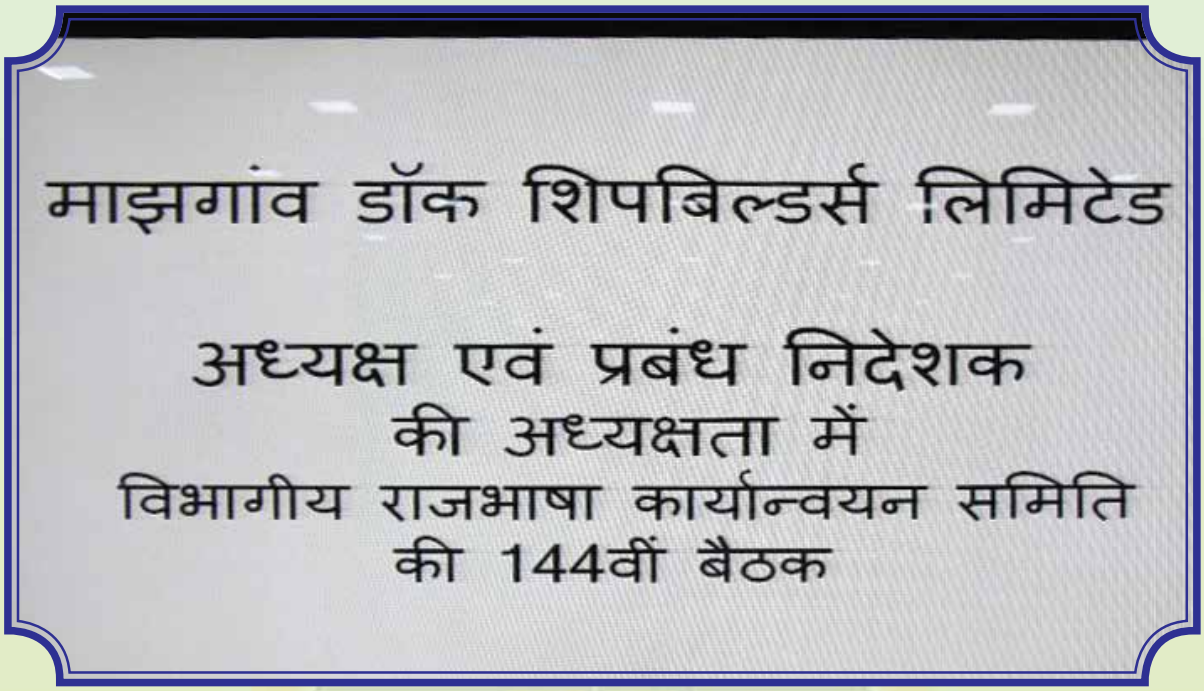
कैंसर कैंप में सुश्री डॉ. जैनब से कैंसर के बारे में चर्चा करते हुए अप्रनि कमोडोर राकेश आनन्द के साथ मुचिअ डॉ. हिरेन देसाई



कैंसर कैंप में टेस्ट का निरीक्षण करते हुए कमोडोर राकेश आनन्द के साथ मुचिअ एवं कर्मचारीगण

एमडीएल के कार्यक्रमों की झलकियाँ

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 144वीं बैठक 9 मार्च 2017 को सम्पन्न हुई



विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का स्वागत सम्बोधन करते हुए श्री रामप्रीत यादव, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी



18 जुलाई 2016 को टॉलिक की 57वीं बैठक में श्री अनुपकुमार श्रीवास्तव सचिव (राजभाषा) तथा मुंबई (पीएसयू) टॉलिक अध्यक्ष के करकमलों से एमडीएल को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए कमोडोर राकेश आनन्द, निदेशक (समवाय योजना एवं कार्मिक), हिन्दी अधिकारी एवं कर्मी



आशीर्वाद राजभाषा संस्थान की ओर से 23 सितम्बर, 16 को मुंबई दूरदर्शन केंद्र वर्ली, में आयोजित 25वें समारोह में एमडीएल की श्रेष्ठ गृह पत्रिका (जलतरंग) को श्री किरण शांताराम से पुरस्कार प्राप्त करते हुए वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री रामप्रीत यादव और श्री पी डी सिद्दीकी

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
राष्ट्र के पोत निर्माता

